हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 फरवरी, 1986

खण्ड 1, अक 5

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1988

पृष्ट संख्या

अध्यक्ष द्वारा औव्जर्वेशन –	
प्रश्न देने वाले सदस्यों की बजाये अन्य सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की, अनुमति देने सम्बन्धी	(5)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)2

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 23
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	
एन ० आई० टी० फरीदाबाद में बिजली की भारी कमी तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाईयों सम्बन्धी	(5) 27
वक्तव्य–	
सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(5)28
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(5) 33
सप्लीमैंटरी ऐम्टीमेट्स (सैकिण्ड इस्टालमैंट) 1985–86 पर चर्चा तथा मतदान	
(1) राज्य के राजस्व– पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा,	(5)34
(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(5) 34

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान' सभा हाल, विधान भवन', सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

अध्यक्ष द्वारा औब्जर्वेशन

प्रश्न देने वाले सदस्यों की बजाये प्रश्न तदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति देने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, इससे पहले कि हम क्वैश्चन्ज शुरू करें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के पेपर में एक बड़ी अजीब–सी खबर छपी है कि कल मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर क्वैश्चन्ज के बारे में एक अनप्रैसिडैंटिड डिसीजन लिया है । पता नहीं अखबार वालों ने यह कैसे लिख दिया है? जो मैंने कल एग्री किया था, वह अनप्रैसिडैंटिड नहीं है बल्कि रूल्ज आफ प्रोसीजर के मुताबिक है । किसी मैम्बर की ऐबसैसं में अगर कोई दूसरा मेम्बर स्पीकर को रिक्वैस्ट करता है तो स्पीकर सवाल का जवाब देने के लिये डायरैक्ट कर सकता है । इस के बारे ने प्रैसिडैट्स हैं । इस सम्बन्ध में मैं आनरेबल मैम्बर्ज का ध्यान रूल 52 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसे मैं पढ़ देता हूं –

"(1) When the time for asking questions arrives, the Speaker shall call successively each member in whose name a question appears on the list of questions.

(2) The member so called shall rise in his place and unless he states that it is not his intention to ask the question standing in his name, he shall ask the question by reference to its number on the list of questions.

(3) If on a question being called it is not put or the member in whose name it stands is absent and no one has been authorised by him to put it, the Speaker at the request of any member, may direct that the answer to it be given."

रूल क्लीयर है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मेम्बर साहिबान, अब सवाल होगे ।

Purchase of bus chassis and tyres by Haryana Roadways

***1059 Shri Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Transportbe pleased to state—

(a) the number of bus chassis purchased by the Haryana Roadways during the period from 1st April, 1985 to-date togetherwith the names and addresses of the suppliers of the said chassis;

(b) whether any procedure has been laid down for the purchase of new tyres for use in the Haryana Roadways; if so, the details thereof;

(c) the names and addresses of the firms from which new tyres were purchased by the Haryana Roadways during the period from 1983-84 to date ; and

(d) whether any complaint has been received regarding the purchase of tyres as referred to in part (c) above; if so, the action, if any, taken thereon?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) During the year 1985-86 from 1-4-1985 to 2.1.1986 172 chassis have been purchased, the details of which are given below :-

1. M/s Tata Engineering & Locomotive Co.Limited, 45 nos,

   Bombay

2. M/s Ashok Layland Limited, Madras
   127 nos.

(b) New tyres are purchased for use in Haryana Roadways as per the decisions taken by High powered purchase committee from time to time.

(c) The names and addresses of the firms from which the tyres were purchased from 1983-84 to date are given as under :-

1. M/s Goodyear India Limited, Faridaba d (Haryana).

2. M/s J.K. Industries Limited, Kankroli Distt. Udaipur (Rajasthan).

3. M/s M.R.F. Limited, Madras.

4. M/s Bombay Tyre International Bombay.

5. M/s Modi Rubber Limited, Modinagar (U.P.).

6. M/s Tyre Corporation of India Limited, Calcutta.

7. M/s Ceat Tyres of India Limited Bombay.

8. M/s Appollo Tyres Limited Cochin (Kerala).

9. M/s India Tyre & Rubber Co. Limited Bombay.

10. M/s Dunlop India Limited Calcutta.

11. M/s Premier Tyres Limited, Bombay.

12. M/s Vikrant Tyres Limited Mysore.

(d) No Sir.

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने सवाल के जवाब में बड़े विस्तार से सूचना दी है । मैं आपके माध्यम से उन से यह जानना चाहता हूं कि मैनुफैकचरर्ज से जब हम टायर वगैरह खरीदने जाते हैं तो वे सरकार को कोई कमीशन वगैरह भी देते हैं जैसे कि दूसरे प्राईवेट डिस्ट्रीब्यूटर्ज को कमिशन दिया जाता हे? दूसरी बात मेरी टायरों की क्वालिटी के सम्बन्ध ' में है कि जो दो ब्रांड हैं उनमें से कौन से ब्रांड को आप अच्छा समझते हैं और जो आपके पास टायर्ज की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से कौन से ब्रांड की क्वालिटी अप टू मार्क है?

कर्नल राव राम सिंह : सर, हम डायरैक्ट फर्मों से टायरों की खरीद करते हैं? किसी को बीच में कमीशन नहीं देते । पहले तो ऐसा था कि टायर कंपनियों से हाई पावर्ड कमेटी जिसके चेयरमैन हमारे मुख्यमन्त्री महोदय हैं, नैगोशिऐट करके प्राईस फिक्स करती थी । कभी कभी तो हम उन टायर कंपनियों पर दबाव डाल कर रेट नीचे करवा लेते थे लेकिन उसके बाद सभी टायर कंपनियों ने आपस में मिल कर एक ऐसोसिएशन बना जी और यह फैसला किया कि कोई भी टायर की कीमत कम नहीं करेगा । एक ही रेट पर सभी को सप्लाई की जाएगी । इसके बाद हमारी हाई पावर्ड कमेटी ने कीमतें घटाने के बारे? में काफी कोशिश की लेकिन वे नहीं माने और हमने यह फैसला किया कि दो तीन कंपनियों से टायर ले लिये जाए बाकियों को छोड़ दिया जाए । लेकिन फर्में अपने फैसले पर फर्म रहीं । हमने किसी को भी आर्डर नहीं दिया और उन्होंने सप्लाई बन्द कर दी जिस कारण से कई डिपोज पर मुश्किलें आ गई । उसके बाद हाई पावर्ड कमेटी ने यह फैसला किया कि जो इनकी प्राईस है उसी के मुताबिक आर्डर दे दिया जाए । इस लिये आज हिन्दुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी को एक ही रेट पर टायरों की सप्लाई हो रही है ।

श्री कंबल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि जितने भी मैनुफैकचरर्ज होते हैं वे अपनी रेट लिस्ट पर होल सेल डीलर्ज को कमीशन देते हैं । हरियाणा रोडवेज तो

एक बड़ा भारी कंज्यूमर है अतरू मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या होल सेल डीलर्ज की तरह ' इन्हें भी कोई कमीशन दिया जाता है कि नहीं?

कर्नल राव राम सिंह : सर, हमने किसी के साथ कोई कमीशन फिक्स नहीं की हुई है । हमने तो उनके साथ केवल यह तय किया हुआ है कि आप हमें किस रेट पर टायर सप्लाई करेंगे । मिनिमम से मिनिमम आप हमें बताएं । उन्होंने यह कहा कि हमारी ऐसोसिएशन का यह फैसला है कि हिन्दुस्तान में जितनी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग्ज हैं उन सब को– एक ही रेट पर टायरों की सप्लाई की जाएगी । जिस रेट पर कम्पनियों वाले हमें टायरों की सप्लाई कर रहे हैं, उसी रेट पर हिन्दुस्तान में दूसरी स्टेट्स को भी सप्लाई की जा रही है । हरेक कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी में काफी डिफरैन्स है । सर, जब मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग की से वा करने का मौका मिला, उस वक्त हमने यह फैसला किया कि सभी कंपनियों के टायरों की क्वालिटी चौक करने के लिये एक एक डिपो को डिफरैन्ट– डिफरैन्ट कम्पनी के टायरों की सप्लाई दे दी और हरेक डिपो साल के बाद टायरों की परफोमैन्स के बारे में रिपोर्ट दे कि किस कंपनी के टायर की परफारमैन्स कैसी रही । जिन कंपनियों की परफोरमैन्स खराब रही उनको हमने ड्रौप कर दिया । जिन कंपनियों के टायरों की रिपोर्ट अच्छी थी, माइलेज अच्छी थी उन कंपनियों को डिपोज अलाट कर दिये गये ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, जब टायर खरीदे जाते हैं उस वक्त कंपनी वाले इस बात की गारन्टी देते हैं कि अगर टायर खराब निकलेगा तो उसकी कौस्ट वापिस दी जाएगी । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपको भी इस तरह की गारन्टी कपंनी वाले देते हैं?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि गारन्टी तो कोई नहीं होती लेकिन अगर पहले साल भर में टायर चलते चलते बर्स्ट हो जाए तो उसकी रिप्लेसमैंट कम्पनी वाले कर देते हैं । जब कभी हम ऐसी शिकायत भेजते हैं तो वे 40–50 आदमियों की एक टीम भेजते हैं । वह पूरी तरह से इंस्पैक्ट करती है । अगर टायर में कोई पत्थर कट या कील लगा हो तो वे रिप्लेस नहीं करते । वैसे आम तौर पर वे को–आप्रेट करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं ।

Elections to Municipal Committees

***1076. @ Shri Nihal Singh & Shri Fateh Chand Vij j :** I Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any decision has been taken to hold Municipal elections in the State; if so, the time by which these are likely to be held ?

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : हां, 1981 की जनगणना के आधार पर 74 नगरपालिकाओं की वार्ड–बन्दी तथा मतदाता सूचियों की तैयारी से सम्बन्धित कार्य

इस मास के अन्त तक सम्पन्न कर लिये जाने की संभावना है । तत्पश्चात इन नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये जायेंगे ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें पिछले चार सालों से दोहरायी जा रही हैं यानी हर सैशन में यह बात दोहराई जाती है । अगर चुनाव का हक पंचायतों को दिया जाता है, ब्लाक समितियों को दिया जाता है तो शहरों को क्यों नहीं दिया जॉता? क्या मन्त्री महोदय इस इलैक्शन के लिये कोई निश्चित तिथि बताएंगे कि मई, जून, जुलाई तक यह करवा दिये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार की नियत बहुत ही साफ है । सरकार ने 81 में से 74 नगरपालिकाओं की वार्ड–बन्दी कम्पलीट कर ली है । बाकी 7 की वार्ड बन्दी इसलिये नही हुई कि उनके केस कोर्ट में पड़े हैं । इन सात कमेटियों के नाम हैं –गुड़गांव, जगाधरी, थानेसर सढौरा, रानिया, हेली मण्डी और पटौदी ।

चौधरी लीला कृष्ण : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस बारे में क्या कोई हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी,अगर थी तो क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है?

श्री ओम प्रकाश महाजन : इस बारे में हाई कोर्ट का फैसला 6 नवम्बर, 1985 को हुआ । आनरेबल जज तिवातिया साहब और सुरेन्द्र सिंह जी ने कम्बोज साहब की रिट पर यह

फैसला किया था । हमें 53 दिन का टाइम चाहिए जिसमें चुनाव करवा सकते हैं । इसमें 30 अप्रैल आखिरी डेट है, अभी समय पड़ा है । हमने कोई अपील नहीं की है ।

Construction of Panipat bye-pass

***1083. @Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister for Public Works (B & R)** be pleased to state whether any decision has been taken for the construction of a bye-pass in Panipat keeping in view the increased traffic and the town being a big industrial city of the State; if so, the date on which the said decision was taken and the action taken thereon ?

Public Works Building and Roads Minister (Shri Amar Singh) :

(a) No.

(b) In view if (a) question does not arise.

श्री भले राम : स्पीकर साहब, पानीपत एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर बाई पास क्यों नहीं बन सकता?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, 1982 में हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को इस बाई पास के लिए 1,40,16,800 रुपए का एस्टीमेट बना कर भेजा था लेकिन वह एस्टीमेट 21–9–83 को वहां से अन–एप्रूवड होकर आ गया । वह इस , जानकारी के साथ वापिस हुआ कि मुरथल से करनाल तक फोर लेन बन रही हैं जिसमें पानीपत भी शामिल है । उस पर 42

करोड़ 50 लाख रुपये खर्च आएगा जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर है । इसमें से 3 करोड़ 42 लाख रुपए सम्भालखा पानीपत, घरौंडा और करनाल की सड्कों की सरफेस, फुट पाथ और ड्रेनेज फैसिलिटीज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा । जहां तक पानीपत का सम्बन्ध है, आपको पता है कि पीछे जब पानीपत में राष्ट्रपति महोदय आए थे उस समय आपको कितना लम्बा चौड़ा मैदान नजर आता था । लोग वहां पर नाजायज तौर पर ट्रक वगैरह खड़े कर लेते हैं मौर बाकायदा सड़क को घेर लेते हैं । अगर देखा जाए तो वह सड़क इस समय 6 लेन की हैं इसलिये वहां पर बाई पास न ही भारत सरकार ने और न ही वर्ल्ड बैक प्रोजैक्ट ने एप्रूव किया । इसलिये बाई पास बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर 16 करोड़ रुपया खर्च आएगा । यह 16 करोड़ रुपया और सड़कें या अन्य कामों पर खर्च किया जा सकता है ।

श्री ए० सी० चौधरी : अभी मन्त्री जी ने बताया कि एक करोड़ 4० लाख रुपए का एस्टीमेट इन्होंने सैटर को भेजा जो किसी कारणवश एप्रूव नहीं हुआ । स्पीकर साहब एस्टीमेट बनाने या उसकी ऐप्रूवल से आवाम को कोई सरोकार नही है । पानीपत एक इम्पोटैट और हिस्टौरिकल शहर है और जी० टी० रोड के दोनों तरफ बसा हुआ है । आए दिन वहां पर एक्सीडैटं होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बाई पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया था । एक्सीडैटंस का कारण सिर्फ एक है कि थोड़े से एरिया में बड़ा टाउन दोनों तरफ बसा हुआ है। क्या मन्त्री महोदय बताने की

कृपा करेंगे कि क्या इन्सानों की जिन्दगी की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अगर जिम्मेदारी 'है तो सरकार सैटर पर दबाव क्यों नहीं डालती? इन्सानों की जिन्दगी बचाने के लिये दो तीन करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता ।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब क्लीयरली आ चुका है । उन्होंने कहा है कि बह सड़क पहले ही 6 लेन के बराबर काम कर रही है ।

श्री निर्मल सिंह : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि अम्बाला कैट में बाई पास बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, अगर हां तो कब तक वना देंगे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि थ्रू आउट अम्बाला से दिल्ली तक रोज एक्सीडैटंस होते हैं । कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई मरा न हो या घायल न हुआ हो या कोई बस याट्रक उलटा न हो । इसलिये जैसे सम्मालखा तक फोर लेन बनाई गई है क्या अम्बाला तक भी बनाएंगे ?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, वैसे तो मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड बैक प्रोजैक्ट से मूरथल से करनाल तक फोर लेन सड़क बनाने की एप्रूवल ले ली है । यह बड़ी मेहनत के बाद हुआ है । मूरथल से करनाल तक हैवियस्ट टैरफिक है और इंडिया में सब से ज्यादा ट्रैफिक इस रेंज में आता है । आगे भी जहां जहां दिक्कत

आ रही है हम डबल लेन बना रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो फोर लेन करेंगे ।

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, यह प्रश्न श्री फतेह चन्द विज का है । मन्त्री जी ने इसका उत्तर दिया कि वहां पर बहुत जगह खाली है लेकिन लोग ट्रक खड़े कर लेते हैं । क्या विज साहब ने यह सवाल इसीलिये किया है कि बाई पास बन जाए और उनके ट्रकों को जी ० टी ० रोड पर खड़े होने के लिए स्थान मिल जाए?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न और इसका जवाब तकरीबन हर सैशन में आता रहा है एक्चुयली मिनिस्टर साहब ने अब– भी काफी डिटेल्ड जवाब दिया है । वह सड़क तो काफी चौड़ी कर दी गई है लेकिन वहां लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हांसी– के पास बाई पास बनाने की स्कीम चल रही है उसको कब तक बनाने का विचार है? दूसरे हांसी से ढाना और हांसी कतोपुर बाई पास कब तक बन जाएंगे? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हांसी दिल्ली रोड को भी फोर लेन बनाने का विचार है?

श्री अमर सिंह : इस रोड पर हमारा हांसी तक फोर लेनिंग के बारे में काफी तेजी से काम शुरु करवाने का विचार है । इसके साथ जो टैलिफोन और बिजली के पोल सड़क पर हें

उनको हटाने के लिए संबन्धित विभागों से खतो किताबत चल रहा है । जब यह मसला हल हो जाएगा तो काम शुरु करवा देंगे । हांसी में बाई पास बनाने की जरुरत नहीं है क्योंकि वहां पर फोर लेन सड़क बन जाएगी ।

श्री कवंल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने कहा कि पानीपत में 6 लेन की सड़क का प्रोवीजन है । हमारी स्टेट में से तो नेशनल हाई–वे गुजरते हैं । यह मानते हैं कि उन पर एनक्रोचमैंट है तो उसको हटाया क्यों नहीं जाता? इसके अलावा, रोहतक में कुछ समय पहले बाई पास बना था लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब है । क्या मन्त्री जी ऐसे कदम उठाएंगे कि एग्जिस्टिंग रोडज पर जो बौटल नैक्स हैं, उनको बन्द कर देंगे ताकि सड्कों पर क्लीयर ट्रैफिक चल सके? इसके अलावा जो बाई पास हैं उन पर कोई आदमी नाजायज कंसट्रक्शन न कर सके क्या इस कानून को सख्ती से लागू करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, कानून तो है लेकिन जहां कहीं भी बाई पास बनाए गए हैं, दो साल के बाद उनके इर्दगिर्द आबादी हो जाती है, दुकानें बन जाती हैं । मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने बाकायदा पुलिस को आदेश जारी कर दिए हैं कि रोडज पर नाजायज तरीके से ट्रक पारकिंग न हो लेकिन उसके बावजूद भी लोग रोड पर ही ट्रक खड़े करते हैं । सरकार इस बात का ध्यान

रखेगी कि जहां कहीं इस तरह की बात होगी, हम उसके लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शंज जारी करेंगे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया कि मूरथल से करनाल तक वन–वे ट्रैफिक यानी फौरलेन रोड किया जा रहा है । मैं आपके द्वारा मच्छी जी से जानना चाहूंगा कि मूरथल से करनाल तक फोरलेन रोड बनाने की. एप्रूवल कब आई और इस पर काम कब तक शुरू कर देंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में 27– 1–1986 को एप्रूवल आ चुकी है और इस पर 42 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे । इसको बनाने के लिए गलोबल टैंडर इन्वाइट करने का काम अप्रैल 1986 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा । उम्मीद है मार्च, 1990 तक यह काम पूरा हो जाएगा ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, शाहबाद से बबैन–लाडवा रोड है, बबैन में बहुत बड़ी मण्डी भी बन चुकी है तथा शाहबाद में शूगरमिल भी लग गया है लेकिन वह रोड बहुत नैरो है । सिंगल रोड होने के कारण उस पर आम तौर से एक्सीडैंटस होते रहते हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उस रोड को थोड़ा करने पर विचार किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : आप जो सप्लीमैंटरी पूछ रहे हैं इसका मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, उस रोड पर बहुत एक्सीडैटस होते हैं । इसलिए उस रोड को चौड़ा करवाना बहुत ही जरूरी. है । उस रोड पर ट्रैफिक पास नहीं हो सकता और गन्ने से भरे हुए ट्रक पास नहीं हो सकते । शाहबाद शूगर मिल में इन्द्री और लाडवा तक का गन्ना आता है । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस रोड को चौड़ा करने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष : आपको उस रोड के बारे में क्वैश्चन देना चाहिए था । मैंने आपको कहा था कि आप गन्ने के बारे में और सड़क के बारे में क्वैश्चन दे दें । यह सवाल मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री ब्रिज मोहन : स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेंगे मैं जो सप्लीमैंटरी पूछने जा रहा हू वह मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है । स्पीकर साहब, जब भिवानी से जींद जाते हैं तो जो रोहतक रोड से बाईपास है, वहां पर रेलवे लाइन आती है, वहां पर रोड बहुत तंग है । मैं यह भी कहूंगा कि उस जगह पर ओवर ब्रिज बनाने के, लिए शायद सरकार के पास पैसे की कमी होगी इसलिये सरकार वहां पर ओवर ब्रिज बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट करती

श्री अध्यक्ष : यह सवाल मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है ।

S.W., R.C.C. and P.V.C. pipes in the Public Health Stores

***1084. Chaudhri Kundan Lal :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether any S.W., R.C.C. and P.V.C. pipes are lying in the stores of P.W.D. (Public Health) at present in the State ;

(b) if so, the category-wise total number of pipes as referred to in part (a) above together with total cost thereof ; and

(c) the time by which the aforesaid pipes are likely to be used according to the present scheme?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है । (अनुबन्ध ''क'') (ग) पी० वी० सी० पाईप अगले तीन मास के भीतर प्रयोग में लाए जाने की संभावना है । एस० डब्लयू० तथा आर० सी० सी० पाईप मास दिसम्बर, 1986 तक प्रयोग में लाए जाने की संभावना है ।

अनुबन्ध ''क ''

श्रेणीवार पाईपों की कुल संख्या तथा कुल लागत का विवरण

श्रेणी	साईज (मिली मीटर)	वर्तमान जन स्वाः विभागीय स्टोरों में पड़ी संख्या	लागत (रु० लाखों में)
1	2	3	4
एस० डब्लयू ०	100	21,344 नं०	
	150	5,346 नं०	
	200	33,447 नं०	
	250	7,304 नं०	
	300	12,942 नं०	
	350	2,068 नं०	
	375	1,809 नं०	
	400	1,359 नं०	26.50
		85,619 नं०	
आर० सी० सी०	100	114.00 मीटर	
	150	280,56 मीटर	

	200	8.00 मीटर	
	225=	10:00 मीटर	
	250	2812.00 मीटर	
	300	4709.69 मीटर	
	350	1198.00 मीटर	
	400	4770.75 मीटर	
	450	535.08 मीटर	
	500	1856.50 मीटर	
	600	2309.27 मीटर	
	700	7.50 मीटर	
	800	2381.50 मीटर	
	900	657.50 मीटर	
	100	465.00 मीटर	35.00
		22115.35 मीटर	
पी० वी० सी०	63	2342.00 मीटर	

	75	17480.00 मीटर	
	90	21604.81 मीटर	
	110	42963.58 मीटर	
	140	3268.00 मीटर	
	160	3481.44 मीटर	
	200	2199.48 मीटर	34.00
		93339.31 मीटर	कुल जोड : 95.50

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने मेरे सवाल का गोलमोल जवाब दिया है । ये खराब होने वाली पाइपें हैं । ये पाइपें चार पांच साल में खराब हो जाती हैं और डिपार्टमैंट ने बड़ी भारी तादाद में खरीद ली हैं, जबकि डिपार्ट–मैंट के पास सीमेंट और सरिया नहीं है जिसकी वजह से सीवर का काम रुका पड़ा है । सफीदों नगरपालिका ने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के पास सीवरेज के लिए' 1.10 लाख रुपए भी जमा करवा रखे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एस० डब्लयू० पाइपें कितने अर्से से स्टौक में पड़ी हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : कर साहब, ऐसा कोई पाइप नहीं होता जो चार पांच. साल में खराब होजाता हो । पाइपें तो 50 साल भी खराब नहीं हो सकतीं । जहां तक पाइपें ज्यादा खरीदने की बात है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पाइपें ज्यादा नहीं खरीदी गई । पाइपें तो काम की शक्ल में खरीदी जाती हैं यानि सीवरेज का काम लार्ज स्केल में होता है, उसी के मुताबिक खरीदी गई हैं । कई बार एमरजैसी पड़ जाती है, यदि उस समय हमारे पास पाइपें नहीं होंगीं तो कहां से लाएंगे? यदि उसी वक्त किसी कम्पनी को आर्डर दिए जाएं तो कम्पनी वाले उसी टाईम पर पाइपें सप्लाई करने से इन्कार कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडवांस स्टौक तो रखना ही पड़ता है । जहां तक सफीदों के मल निकास की बात है, उसके लिये हमारे पास 32.98 लाख रुपए की धनराशि जमा हुई थी । इसमें से 3 लाख रुपए की धन राशि राज्य ऋण से, 2.90 लाख रुपए की धनराशि राज्य अनुदान से और 5.50 लाख रुपए की धनराशि नगरपालिका ने जमा करवाई थी जिस पर काम चालू है । उसके बाद नवम्बर के महीने में 13.83 लाख रुपए की धनराशि नगरपालिका सफीदों ने और जमा करवाई है । इस वक्त वहां पर लगभग 1000 मीटर सीवरेज बिछाई जा चुकी है । बाकी का काम 1986– 87 में पूरा हो जाएगा । टोटल सीवरेज 6355 मीटर लम्बी बिछाई जानी है । सीवरेज के लिए नवम्बर के महीने में जो पैसा हमारे पास जमा हुआ है उसके लिये टैंडर भी इनवाइट कूरने हैं और दूसरी कार्यवाही भी करनी है । उसमें

टाईम लगता है । ज्यों–ज्यों हमें पैसा मिलता जा रहा है, हम काम करते जा रहे हैं ।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि तीन कैटेगरी की पाइपें खरीदी गई हैं, वे एक्सैस नहीं खरीदी गई जितनी रिक्वायरमैंट है उसी के मुताबिक खरीदी गई हैं । लेंकिन सवाल के जवाब में बताया गया है कि एस० डब्लयू ०, आर० सी० सी० और पी० बी० सी० पाइपें काफी मात्रा में स्टौक के अन्दर पड़ी हैं । स्पीकर साहब, स्टीक के अन्दर पाइपें रखने के कुछ नार्म्ज होते होंगे । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि स्टोकिंग के क्या नार्म्ज हैं, यदि एक्सैस माल खरीद लिया गया तो वह कितना खरीदा गया और जिसने माल एक्सैस खरीदा उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, पाइपें स्टौक करने के कोई लम्बे चौड़े नार्म्ज नहीं 'हो सकते । हमारे विभाग में सीवरेज का काम लार्ज स्केल पर चलता है । जैसे इस साल भी 333 लाख रुपए का सामान खरीदा जा चुका है । हमारे विभाग का करोड़ों रुपए का बजट होता है । हमारी कोशिश यह होती है कि स्टौक में 'थोड़ा बहुत सामान जरूर रखें क्योंकि हम एक जगह का माल दूसरी जगह पर नहीं भेजते हैं क्योंकि माल लोड करते समय टूटने का डर रहता है । हम जरूरत के मुताबिक ही स्टौक में माल रखते हैं ।

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि जो एस० डब्लयू०, आर० सी० सी० और पी० वी० सी० पाइपें खरीदी गई, कितनी क्वांटिटी में खरीदी गई, कब खरीदी गई और स्टौक में कितनी पड़ी हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, स्टौक में सामान आता जाता रहता है । नया सामान आता रहता है और पुराना जाता रहता है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे क्लीयर कर देता हूं । इस वक्त स्टोक में एस० डब्लयू० पाइपें 26.50 लाख रुपए की, आर० सी० सी० की 35 लाख रुपए की, और पी० वी० सी० 34 लाख रुपए की स्टौक में पड़ी हैं । टोटल 95.50 लाख रुपए की पाइपें इस वक्त स्टौक में पड़ी हैं साल भर में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की लगभग 15 करोड़ रुपए की खरीद होती है देहात के लोगों को पीने का पानी देना होता है । स्टौक में कोई ज्यादा सामान भी नहीं है तीन महीने का एडवांस सामान तो रखना ही पड़ता है । यदि एकदम पाइपों की जरूरत पड़ जाए और हमारे पास न हों और उसी वक्त किसी कम्पनी को आर्ड र दिए जाएं तो वह पाइप सप्लाई करने के लिये इन्कार भी कर देती है इसलिये ती न चार महीने का एडवांस सामान रखना ही पड़ता है ।

श्री ब्रिज मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस साल सीवरेज के लिए कितना बजट रखा गया है –डे

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, यह तो कोई सवाल नहीं है । इस साल का बजट तो अभी सदन में पेश ही नहीं हुआ है ।

10.00 बजे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने यह सवाल पू छा था कि परचेज करने के और स्टौक रखने के क्या नार्म्ज हैं । अभी मुख्य मन्त्री जी ने जवाब देते हुए बताया है कि हम पब्लिक हैल्थ पर साल में 45 करोड रुपये के करीब खर्च करते हैं । यह बात ठीक है कि सामान का स्टोक होना चाहिए और इन्होंने बताया भी है कि हमारे पास इस समय पाइपों का कोई 95. 50 लाख रुपये का स्टौक पड़ा है । मेरा ख्याल है कि चौधरी कुन्दन लाल जी यह पूछना चाहते थे कि क्या किसी वक्त किसी आफिसर ने इतना अधिक सामान तो नहीं खरीद लिया जो एक साल नहीं, दो साल नही, तीन साल नही बल्कि कई सालों तक इस्तेमाल होता रहा हो? यदि कभी ऐसी कोई स्टेज आई हो तो उस बारे में मन्त्री जी स्थिति स्पष्ट कर दें । साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि इस काम के लिए नार्म्ज कोई लम्बे चौड़े नहीं हैं

। यदि लम्बे लम्बे चौड़े नहीं हैं तो छोटे मोटे जो नार्म्ज हैं, वही बता दें ताकि हमें पता लग जाए कि नार्म्ज क्या हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जरूरत के मुताबिक ही सामान खरीदा जाता है । थोड़ा सा ज्यादा सामान हम जरूर खरीदते हैं ताकि काम चलता रहे । यह बात अलग है कि किसी स्टोर में तीन महीने आगे का स्टाक हो और किसी में 6 महीने का स्टौक हो । कई सालों तक का एडवांस में सामान खरीदने वाली बात हमारे नोटिस में तो है नहीं । हमारे पास इस समय कितने रुपये का सामान पड़ा है, उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने अभी बता ही दिया है ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि जो पाईप इन्होंने खरीदे हुए हैं, वे 4– 5 सालों में खराब हो जाते हैं । अब दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने अभी बताया है कि हमने कोई 95.50 लाख रुपये का सामान खरीदा हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो इन्होंने इतने रुपये की पाईप खरीद कर ली, दूसरी तरफ सीमेंट 'और लोहे के सरिये इनके पास न होने की वजह से सीवरेज का काम रुका हुआ पड़ा है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि इतने रुपये की पाईप तो खरीद ली जबकि सीमेंट और लोहे के सरिये आदि नहीं खरीदे गए?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा काम रुका हुआ पड़ा है । टारगेट के मुताबिक हमारा सारा काम ठीक चल रहा है । मेरे आनरेबल मैम्बर को कोई गलतफहमी हो गई है । स्टोर में जो सामान होता है उसमें से सामान निकलता रहता है और आता रहता है । कुछ समय के लिये एडवांस में तो सामान रखना ही पड़ता है ताकि किसी –एमरजेंसी आदि के काम के लिये कोई रुकावट न आए ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने एडवांस में पाईप खरीदे हुए हें, वे इसलिये तो नहीं खरीदे कि जहां से ये पाईप खरीदने थे, वह फैक्टरी बन्द होने जा रही थी या फिर इन पाइपों के रेट बढ़ने की संभावना थी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : मुख्य मन्त्री जी ने अभी हाउस को बताया है कि इस काम के लिये साल में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं । इसमें हमने सिर्फ 95.50 लाख रुपये का ही सामान खरीदा हुआ है । यह कोई ज्यादा सामान नहीं है । ऐसी भी कोई बात नहीं है कि रेट बढ़ने वाले हों या कोई फैक्टरी बन्द होने वाली हो । इसके लिये हमने एक हाई पार्वड कमेटी बनाई हुई है । बाकायदा टेन्डर इन्वाईट किए जाते हैं । जिसका टेन्डर कम रेट का होता है उसी से पाईप खरीदते हैं ।

Recruitment of M.V.I. and Foreman in Haryana Roadways

1086. @Master Shiv Parshad : Will the Minister for Transport

Shri Fateh Chand Vij

be pleased to state the minimum educational qualifications required for recruitment to the posts of M.V.I. and Foreman in the Haryana **Roadways?**

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) : The statement (Annexure A') is laid on the Table of the House.

ANNEXURE 'A'

1.	Motor Vehicle Inspector		
	By direct recruitment		By Pro motion
(i)	Intermediate	(i)	Matriculation
		(ii)	Experience on the post of—
(ii)	Holds diploma in Automobile Engineering of a recognised Institute. Has minimum experience for a period of 3 years of an Automobile Engineering Workshop.		(a) Service Station Incharge for a minimum period of 3 years. or
			(b) Head Mechanic for a minimum period of 4 years.
2.	Foreman		
(i)	Diploma in Automobile/Mechanical/	(i)	Matriculate.

	Electrical Engineering from a recognised Institute		
		(ii)	3 years experience on the post of Service Station Incharge.
(ii)	3 years experience in repair/ maintenance in an automobile workshop of Government, semi-Government Department or Public Undertakings.		

Taking over of foodgrain trade in the State

***1077. @Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state whether the Government has received any proposal from the Government of India either for removal of commission agents and middle men from foodgrain trade or to take over the Food-grain trade in the State ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (चौधरी कल्याण सिंह) : नहीं ।

चौधरी धर्म वीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या खाद्यानों की खरीद के बारे में कमीशन एजेन्ट्स और मिडल–मैन बनने के लिये गवर्नमैंट आफ इण्डिया की परमिशन लेना जरूरी है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इनका पूछने का मकसद यह है है कि जो गेहूं और चावल की प्रक्योरमेंट सरकार करती है, उसमें बिचौलिये हैं या नहीं । मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि इस बारे में भारत सरकार ने यह कहा है कि इस खरीद के लिए बीच में बिचौलिये नहीं होने चाहिएं । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये बिचौलिये नहीं हैं । आप जानते हें कि दो किस्म के आढ़ती होते हैं । एक आढ़ती वह होता है जिसकी दुकान पर किसान अपना माल ला कर डालता है जिसे' हम कच्चा आढ़ती कहते हैं 1 दूसरा वह आढ़ती होता है जो उस दुकान से सामान को खरीदता है, उसे हम पक्का आढ़ती कहते हैं । पक्का आढ़ती ही उस दुकान से सामान खरीदता है और माल को दूसरी जगह भेजता है । हम स्टेट लैवल पर जो परचेज करते हैं उसके लिये ये हमने इसलिये रखे हुए हैं ताकि किसानों को कोई तकलीफ न हो । इस काम के लिए सिर्फ एक बोरी पर 19 या 20 पैसे ही देते हैं । 19 या 20 पैसे लेने पर सारी जिम्मेवारी उसी व्यक्ति की हो जाती है जो उस माल को खरीदता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यों ही कच्चे आढ़ती की दुकान पर माल आता है तो पक्का आढ़ती उसके सामान को खरीद कर उसकी पेमेंट उसी वक्त कर देता है । वही आदमी सारे सामान को गोदाम तक पहुंचाता है । यह सारी जिम्मेवारी उसी की है । जब सामान गोदाम में पहुंच जाता है तो वह सरकार को बिल देकर अपनी पेमेंट ले लेता है ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई

तकलीफ न हो । लोगों की सुविधा के लिए ही ऐसा किया गया है ।

श्री भले राम : क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि जब किसान अपना अनाज मण्डी में लेकर आता है तो उसके साथ हेरा–फेरी की जाती है और उसके माल की ठीक बोली नहीं लगाई जाती जिससे किसान परेशान होते हैं?

चौधरी भजन लाल : सरकार के नोटिस मे ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसानों के साथ किसी किस्म की कोई हेराफेरी की जाती है । इस काम के लिए बाकायदा मार्किट कमेटियां बनी हुई हैं जिनमें किसानों को ही चेयरमैन बनाया जाता है । अगर ऐसी कोई बात हो तो वे अपने नुमायन्दों को इस बारे में बताएं या अपने चुने हुए एम ० एल ० एज ० को बताएं । वे सरकार के नोटिस में लायें । ऐसी कोई बात होगी और सरकार के नोटिस में आएगी तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी ।

चौधरी धर्म वीर गाबा : क्या इन मिडलमैन को समाप्त करने के लिए सरकार कोई कार्पोरेशन या बोर्ड गठित करने पर विचार करेगी?

चौधरी भजन लाल : यह काम बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फिर इसके लिए औफिस बनाना होगा और स्टाफ लगाना होगा जिस पर खर्च बहुत अधिक आयेगा ।

श्री निर्मल सिंह : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि क्या किसी मार्किट कमेटी का चेयरमैन किसान न हो कर कोई और है?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, बाकायदा हर जगह किसान ही मार्किट कमेटियों के चेयरमैन हैं । यह अलग बात है कि किसी मार्किट कमेटी में चेयरमैन जाति से महाजन हो । यदि वह महाजन खेती करता है तो उसे हमें किसान ही मानना पड़ेगा ।

Hadva sub-drain and road link drain in Safidon sub-division

***1085. Chaudhri Kundan Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the latest position of Hadva sub-drain and road link drain situated in sub-division, Safidon, togetherwith the time by which these drains are likely to be completed ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Proposals for construction of these two link drains are under process of investigation and preparation. Work of execution will be taken up after the approval of schemes by the Haryana State Flood Control Board and after observing all formalities including land acquisition. However, temporary relief is being provided to the area through the flood pool pumps as and when problem arises.

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस काम पर हर साल काफी रुपया खर्च होता है और हर साल ही जमींदारों की फसलें तबाह होती हैं । इसलिए मैं मन्त्री जी से यह जानना

चाहता हूं कि क्या इस काम को इस साल पूरा कर देंगे ताकि जमींदारों की फसलें भी नष्ट न हों और सरकार का पैसा भी बरबाद न हो?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा जब फ्लड आया था तो जन ड्रेन्ज का इस सवाल में जिक्र किया गया है, वहां मैं स्वयं श्री कुन्दन लाल जी के साथ गया था और टैम्परेरी अरेन्जमैंटस करवाए थे ताकि आबादी को नुक्सान न हो । मैं कह सकता हूं कि उसके बाद किसी आबादी को फ्लड से नुक्सान नहीं हुआ है 1 इसके अलवा, इन गांवों में जो खेत हैं उनसे पानी को पम्प आउट करवाया गया था ताकि फसल काश्त हो सके । अध्यक्ष महोदय, जहां तक रैगुलर ड्रेन्ज बनाने का सम्बन्ध है, पहले 6 हजार फुट की ड्रेन्ज बननी थीं लेकिन कुन्दन लाल जी के कहने पर 12 हजार फुट की ड्रेन्ज बनाने का फैसला हुआ । इन पर 6 लाख रुपया लगेगा । स्कीम्ज वगैरा तैयार करके हम भेज रहे हैं । दूसरी ड्रेन्न की भी ऐसी ही बात है । प्रोसैस में टाईम लगता ही है । सरकार ने मेजर काम तो मुकम्मल कर लिए हैं लेकिन पूरी स्टेट में छोटी छोटी ड्रेन्ज बनाने की बेशुमार डिमांडज हैं । फंडज की कंस्ट्रेन्टस की वजह से इनकी प्रायरिटी फिक्स करनी पड़ती है । वर्ष. 1985– 88 'का फ्लड एण्ड ड्रेनेज डिपार्टमैंट का ऐनुअल बजट 14 करोड़ रुपये का था लेकिन बाद में फाइनैंस डिपार्टमैंट ने जो प्रतिबन्ध लगाए उससे वह रिड्यूस होकर 11 करोड़ रुपये रह गया । इस 11

करोड़ रुपये के खर्च का ब्यौरा भी मैं हाउस को बताना चाहूंगा । मसानी बैरेज के ऊपर 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे । वर्क–चार्जड समेत सारी ऐस्टेब्लिशमैंट के ऊपर 6 करोड़ रुपया खर्च होगा । लैड ऐक्विजिशन की लायबिलिटीज तकरीबन 2 करोड़ रुपये की है । यही पोजीशन 1986– 87 के ऐनुअल प्लान की है । तकरीबन तकरीबन कोई रुपया नई स्कीम्ज के लिए बचता नहीं है । फिर भी महकमा और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि प्रायरिटी स्कीम्ज को ऐक्सिक्यूट किया जाए क्योंकि फाइनैन्शल कंस्ट्रेन्टस की वजह से टोटल स्कीम्ज ऐक्सिक्यूट नहीं हो सकती ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने सारे पैसे का हिसाब दे दिया और यह कि कहा कि इनके पास पैसा नहीं बचता । लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यदि परमात्मा न करे इस साल फ्लड– आ गया तों ये उसंक्रा इन्तजाम कैसे करेंगे? स्पीकर साहब, कुछ ड्रेन्ज ऐसी हैं जिनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल आई हुई है लेकिन उनका काम इसलिये रुका हुआ है क्योंकि सैक्शन 4 और 6 के कागजात तैयार होने में देरी लगती है । इस तरह की छोटी छोटी गलतियों की वजह से साल? साल काम नहीं रुकना चाहिए । क्या मन्त्री जी महकमे को जनरल हिदायत देंगे कि वे छोटी मोटी गलतियों 'को दूर करके सैक्शन्ज 4 और 6 के कागजात को जल्दी कम्पलीट करें ताकि समय से काम हो सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर' साहब, महकमा तो लैड ऐक्विजिशन के लिए प्रपोजल्ज बनाता है । लैड ऐक्विजिशन औफिसर्ज दूसरे हैं । दिक्कत यह है कि पहले तो फार्मजं किसी काम के लिए डिमांड पेश करते हैं लेकिन जब ड्रेन बनने या सड़क बनने का समय आता है तो उसकी मुखालिफत करते हैं । स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि ड्रेन्ज और सड़कें आदि तो जमीन पर से ही जाएंगी । कई बार लोग कोर्टस में चले जाते हैं जिसकी वजह से देरी हो जाती है । इसके लिए लोग भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं । फिर भी माननीय सदस्य अगर कोई स्पैसिफिक बात बताएंगे तो उसको ऐक्सपिडाइट करेंगे । (विष्य)

श्री ब्रिज मोहन : स्पीकर साहब, एल० ए० ओ० मुआवजे के केसिज की तारीख कई कई– महीने तक नहीं लगाते और सरकार की तरफ से मुआवजे का जो पैसा दिया जाता है वह खजाने में जमा नहीं होता । क्या मन्त्री जी एल० ए० ओज० को हिदायतें जारी करेंगे कि वे मुआवजे के केसिज की तारीख जल्दी लगाया करें और महकमा मुआवजे के पैसे को खजाने में जमा करवाए ताकि लोगों को समय से मुआवजा मिल सके?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सरकार की तरफ से तो पूरी हिदायतें हैं । इसके अलावा जब कभी और हिदायतें देने की जरूरत महसूस होती है तो वे दी जाती हैं लेकिन एक. बात मैं हाउस में अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हमारे साथी एल० प० ओज० की बदलिया राजनैतिक प्रैशर से नहीं करवाऐंगे तो काम

ऐकसैलरेट हो जाएगा । अनफार्चुनेटली इसमें हम सब लोग भी और बाहर के लोग भी शामिल हैं जिसकी वजह से सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ता है ।

श्री ब्रिज मोहन : कास को ऐक्सपिडाइट करने के लिए एल० ए० ओ० की पावर्ज एस० डी० एम० और दूसरे अधिकारियों को भी दी जा सकती हैं ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : एल० ए० ओ० की पावर्ज डी० आर० ओ० को दे रखी हैं लेकिन कई जगह अभी केसिज डी० आर० ओ० के पास नहीं हैं बल्कि एल० ए० ओ० के पास ही हैं । इसको हम जल्दी ही सौर्ट आउट कए रहे हैं ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्दी जी से यह जानना चाहता हूं कि सफीदों सब–डिविजन में हाउवा सब्र–ड्रेन तथा रोड लिंक ड्रेन के न बनने के कारण जो बस्तियों में पानी घुस जाता है उसका इस साल की बरसात आने से पहले प्रबन्ध करायेंगे? स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी और खजाना मन्दी जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी ड्रेन्ज के लिए, जो हर साल लोगों के लिए खतरा बनी रहती है, स्पैशल रुपया दिया जाए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं. कि पैसा मिलने पर सब जगह काम करवा देंगे ।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, रतिया हल्के में सधानी साधवान ड्रेन में' पंजाब से पानी आता है और घग्गर में गिरता है । वहां एक पुल भी बनना है । अभी जो पुल है वह छोटा है और नीचा है । (विघ्न) क्या उस पुल को ऊंचा उठाने के लिए कार्यवाही की जाएगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सीकर साहब, चौधरी नेकी राम जी ने पहले कभी पुल की चर्चा नहीं की । अब जो बात इन्होंने बताई है इसका पता करवा लेंगे और देखेगे कि इसे पी ० डब्लयू ० डी ० ने बनाना है या ड्रेनेज डिपार्टमैंट ने बनाना है । **चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अभी कहा कि पैसे की कमी की वजह से ड्रेन्ज बनाने के लिए अभी पैसा खर्च करना संभव नहीं है । हरे भी यह पता है किं एस ० वाई ० एल ० कैनाल के लिए ज्यादा पैसा जा रहा है । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां केवल हजारों रुपये का काम है क्या उसे ये करवाने की कृपा करेंगे? मेरे हल्के में भी एक गंडूरी ड्रेन है जिसकी वजह से कई गांव परेशान रहते हैं । क्या मन्त्री जी उसके काम' को जल्दी करवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब कभी माननीय सदस्य अपने इलाके की दिक्कत बताते हैं, मैं. उन्हीं के सामने महकमे के अधिकारियों को बुलाकर और मीटिंग करके मसले को सौर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं । इनकी भी

जो प्रोब्लम है उसको भी मैं सौर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, चौधरी शमशेर सिंह जी के नोटिस में है कि जहां पर नहर के पैरेलल ड्रेनें खोदी गई ' हैं, वहां नहर परे तो पुल हैं लेकिन ड्रेन पर नहीं हैं, क्योंकि नहर पर पहले पहले का है और ड्रेन बाद, में खुदी है । लोगों को, ड्रेन पर पुल न होने से पानी से गुजरना पड़ता है । मिसाल के तौर पर रिडाना गांव में जहां ड्रेन बाद में निकाली गई है, पुल नहीं है । उसके बारे में मैंने कई बार लिख कर दिया है जो आपके पास भी आया होगा । क्या मन्त्री महोदय ऐसी ड्रेनों पर पुल बनाने में प्रैफरेन्स देंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : पहले से जहां रास्ता है वहां पर क्रोसिंग पुल की आवश्यकता है, वहां पुल जरूरी है । जैसे भलेराम जी बताएंगे उस बारे में हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, जहां पर ड्रेन्ज बनी हैं वहां लोगों के खाल भी जाते हैं । अब खाल ड्रेन के कारण रुके हु ए हैं । क्या मन्त्री महोदय उनके साईफन बनाने में प्रायरिटी देंगे ताकि लोगों को नुकसान न हो?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि वाटर कोर्सिज पर तुरन्त इन्तजाम कर दिया जाये ।

फिर भी अगर कोई इमीजिएट प्रोबल्म है तो बताएं क्योंकि पानी तो किसान को हर पारी में लगाना पड़ता है । इसलिये अब ये बताएंगे तो मैं डिपार्टमैंट से कहकर जरूर बन्दोबस्त कराऊंगा ।

चौधरी कुन्दन लाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिन जमीदारों की दोनों फसलें मारी गई हैं, उनका मालिया या तकावी माफ की जाएगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : श्री कुन्दन लाल जी को सरकार की नीति का अच्छी तरह पता है कि जब किसी किसान की फसल मारी जाती है तो लैण्ड रैविन्यू माफ हो सकता है या पोस्टपोन भी हो सकता है । इसी तरह वाटर चार्जिज की बात है । डिप्टी कमीश्नर से पता कर लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ । पटवारी ने गिरदावरी न की हो, इस बारे में जिले से इंडीविजुएल केस का पता चलेगा, जो भी सरकारी मदद होगी वह जरूर की जाएगी ।

Labour organisation in the State

***1087.@ Master Shiv Parshad and Shri Fateh Chand Vij : :** Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state the number of members of each of the labour organisations functioning in the State ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : आवश्यक सूचना अनुबन्ध '' क' ' पर है ।

अनुबन्ध 'क' '

	श्रम संगठन का नाम	प्राप्त रिटर्नों के अनुसार सदस्यता
1.	इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)	40,370
2.	आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)	31,517
3.	भारतीय मजदूर संघ (बी ० एम ० एस ०)	36,977
4.	हिन्द मजदूर सभा (एच ० एम ० एस ०)	11,358
5.	सैन्ट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)	14,171
6.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू ० टी ० यू ० सी ०)	50,040
7.	स्वतन्त्र (किसी केन्द्रीय श्रम संगठन से एफीलेशन नहीं)	69,284

चौधरी साहब सिंह सैनी : स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फिगर्ज. अलग अलग यूनियन की दी हैं । यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 50,040 की फिगर्ज गलत लगती हैं । क्या मुख्य मच्छी जी डिस्ट्रिक्टवाईज फिगर्ज बताएंगे?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सैनी साहब की बात ठीक है । इसमें चालीस हजार एग्रीकलचर लेबर भी शामिल कर लिए हैं । एग्रीकलचर लेबर शामिल करके फालतू संख्या दिखा रखी है ।

चौधरी धर्म बीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, जो इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स टेरड यूनियन नहीं बनने देते, क्या गवर्नमैंट उन इन्डस्ट्रीयलिस्टस को मजबुर करेगी कि मजदूरों की यूनियन बनने दें?

चौधरी भजन लाल : सात या सात से ज्यादा आदमी किसी जगह काम? करते हों तो अपनी यूनियन रजिस्टर करवा सकते हैं और यूनियन बना सकते हैं ।

चौधरी धर्म वीर गाबा : अगर कोई इन्डस्ट्रीयलिस्ट यूनियन नहीं बनाने देता है तो क्या सरकार उसके खिलाफ ऐक्शन लेगी, या लेबरर्ज को यूनियन बनाने में मदद करेगी?

चौधरी भजन लाल : अगर ऐसी बात है तो वे गवर्नमैंट के नोटिस में लायें कि फलां जगह पर इन्डस्ट्रीयलिस्ट मजदूरों को परेशान करता है, यूनियन नहीं बनने देता तो सरकार जरूर मदाखलत करेगी और उनकी जरूर मदद करेगी ।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने आईए एन० टी० यू० सी० (इंटक) की 40370 की फिगर्स दी हैं, क्या इसमें वे फिगर्स भी शामिल हैं जो ए० आई० टी० यू ०

सी० के मैम्बर हैं क्योंकि ये अलग अलग 2 यूनियन हैं? इनको वे इस यूनियन में ज्वायस नहीं करने देते है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में अलग अलगरू संख्या बताई है । वैसे सारे प्रदेश में 869 टोटल संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं लेकिन हमारे पास रिटर्न 290 संस्थाएं भेजती हैं । जिनके नाम आपके सामने हैं, ये अलग अलग जगह पर हैं । इंटक 46 जगहों पर, भारतीय मजदूर संघ 70 जगह, हिन्द मजदूर सभा 15 जगह, सैडल इंडियन ट्रेड यूनियन 37 जगह, यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस छः जगह और आजाद 7 जगह पर है । इस प्रकार हमारे पास 290 की रिटर्न आती हैं लेकिन कुल 889 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, हमारे यहां फरीदाबाद में गैडोर टूल्स इंडिया लिमिटिड के चार प्लांटस हैं । यह बड़ी भारी कन्सर्न है । वहां पर पहले सी० आईए टी० यू० यूनियन थी फिर आईए एन० टी० यू० सी० यूनियन बनी । वे लोग मैनेजमैंट से साजिश करके सी० आईए टी० यूनियन के लोगों के रोजमर्रा हाथ पैर तोड़ते रहे जिसके कारण वह यूनियन काम नही कर पा रही है । ऐसी और भी कई फैक्टरीज हैं जैसे ऐस्कार्ट है, वहां पर भी ऐसा ही वाकया हुआ है । क्या सरकार उन लोगों को प्रोटैक्शन दे कर मैम्बर– शिप बढ़ाने में उनकी मदद करेगी?

चौधरी भजन लाल : ए० सी० चौधरी साहब की बात ठीक है कि मैनेजमैंट हमेशा यह प्रयास करता है कि दोनों यूनियनें लड़ती रहें और वह– आराम से अपना कामु करता रहे । आमतौर पर उनकी यही पालिसी रहती है लेकिन सरकार की नीति यह रही हैकि जितनी ट्रेड यूनियन बनी हुई हैं, उनकी पूरी मददकी जाये । जब सरकार के नोटिस में आता है कि मैनेजमैंट– उनके साथ –अन्याय कर रहा है या परेशान कर रहा है तो सरकार दखल देती है । सरकार की तरफ से लेबर कोर्ट बने हुए हैं, लेबर कमीश्नर देखता है कि अन्याय न हो । अगर सरकार के पास इस किस की कोई बात आती है तो वह खुद बातचीत करती है । जहां कहीं झगड़ा होता है, उस झगड़े का समाधान करने की सरकार कोशिश करती है । अगर माननीय सदस्य के नोटिस में है ओक कहीं किसी फैक्टरी में उनके साथ ज्यादती हो रही है तो सरकार के नोटिस में लाएं, हम जरूर ऐक्शन लेगे ।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मैंने गैडोर फैक्टरी का नाम लिया है । उन लोगों ने चौलेंज करके कहाकि फलां जगह पर आप लोगों के हाथ पैर तोड़ेने उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं हुआ जिससे गुण्डे आदमी डिमोरेलाइज हो सकें?

चौधरी भजन लाल : मुझे गैडोर के बारे में इन्होंने आज ही बताया है । मैं आज ही इसके बारे में पता करवाऊंगा और जायज बात सरकार जरूर करवायेगी ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, ये जो यूनियन के नाम दिए हैं, इनमें इनडिपैडेन्ट की तादाद सबसे ज्यादा है । क्या यह प्रदेश के लिए खतरनाक नहीं हैकि इतनी आर्गेनाइजेशन्ज को आजाद/बेलगाम छोड़ दिया जाये? (हंसी)

चौधरी भजन लाल : प्रंजातन्त्र में हर आदमी को अधिकार है कि वह इन्डीपैन्डैन्ट हो सकता है, और किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है । इस लिए आप कोशिश करिये कि वे किसी पार्टी में शामिल हों तो अच्छी बात

Mr. Speaker : Question Hour is over.

अतारॉंकित प्रश्न एवं उत्तर

Revenue received by the Chief Administrator, Agricultural Marketing Board

205. Rao Inderjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise total amount received by the Chief Administrator of the Agricultural Marketing Board from the various Market Committees in the State during the years 1983-84, 1984-85 and 1985-86 (todate);

(b) the district-wise percentage of amount out of the amount referred to in part (a) above allocated to the Market Committees to supplement their annual budget during the said period; and

(c) the annual budget estimates presented to the

Chief Administrator by the Market Committees of (i) Rewari, (ii) Kanina, (iii) Ateli, (iv) Mohindergarh and (v) Narnaul togetherwith the amount of budget estimates sanctioned/ approved in each case during the period mentioned in part (a) above ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क)	जिले का नाम	वर्ष 1983–84	1984–85	1985–86 (31–12–85) तक
		में प्राप्त राजस्व (रु० लाखों में)		
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	34.48	45.36	34.82
2.	कुरुक्षेत्र	116.03	120.55	115.53
3.	करनाल	79.46	77.51	61.70
4.	सोनीपत	16.04	20.51	17.34
5.	जींद	40.24	43.79	43.77
6.	रोहतक	16.34	19.33	17.63

7.	गुड़गांव	8.59	-10.80	14.87
8.	फरीदाबाद	9.55	11.93	14.60
9.	महेन्द्रगढ़	33.07	24.10	20.98
10.	सिवानी	14.53	12.46	13.71
11	हिसार	101.38	99.24	88.85
12.	सिरसा	86.37	55.46	70.57
	कुल	556.08	541.04	514.37

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में वर्णित बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व में मार्किट कमेटियों को अपना वार्षिक बजट पूरा करने के लिये इस प्रकार कोई धन–राशि विभाजित नहीं की जाती है । फिर भी यह वर्णित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा यह राशि मार्किट कमेटियों से उनकी आय का 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत (जो उनकी आय के स्लैब पर आधारित है) प्राप्त की जाती है । मार्किट कमेटियों द्वारा अपनी आय का शेष 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अपने वार्षिक खर्च के लिए रख लिया जाता है । फिर भी यदि किसी कमेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो बोर्ड द्वारा उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कमेटियों को ऋण/सहायता देता है ।

(ग) बजट अनुमान (रु० लाखों में)

क्र० सं०	मार्किट कमेटी का नाम	शीर्ष		1983– 84		1984–85		1985–86	
				प्रस्तावित	स्वीकृत	प्रस्तावित	स्वीकृत	प्रस्तावित	स्वीकृत
1.	रिवाड़ी	(1)	आय	66.65	42.65	45.57	49.57	51.73	71.73
		(2)	व्यय	81.17	40.30	64.72	54.46	60.04	65.84
2.	कनीना	(1)	आय	3.69	3.69	3.33	4.33	4.88	4.88
		(2)	व्यय	9.70	6.63	5.68	5:89	6.08	5.98
3.	अटेली	(1)	आय	11.48	12.51	16.69	17.69	10.19	12.19
		(.2)	व्यय	18.95	13.41	24.15	20.53	29.10	16.08
4.	महेन्द्रगढ	(1)	आय	7.74	7.74	8.76	8.26	8.37	9.87
		(2)	व्यय	8.25	6.02	7.49	6.36	8.58	7.62
5.	नारनौल	(1)	आय	21.74	22.74	23.28	30.28	22.59	29.54
		(2)	व्यय	33.91	31.70	48.03	48.63	34.0.5	30.80

Patients treated in Medical College Hospital, Rohtak

207. Shri Rain Bilas Sharma : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of outdoor and indoor patients treated in Medical College Hospital, Rohtak during the period from 1-4-1985 to-date ;

(b) the details of expenditure incurred on the purchase of medicines, bandages, instruments and vehicles separately in the said institution during the period as referred to in part (a) above; and

(c) the number of posts of Professors, Readers, Registrars, Lecturers and Nurses lying vacant in the said Medical College at present togetherwith the time since when the said posts are lying vacant as such and the time by which the same are likely to be filled up ?

वन एवं जेल मन्त्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान) : प्रश्न के भाग (क) (ख) तथा (ग) का उत्तर निम्नलिखित है :–

(क) चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, रोहतक में 1–4– 85 से 27– 1–8 से तक 3,24,213 बाहरिंग तथा 28,025 अन्तरंग रोगियों की चिकित्सा की गई ।

(ख) निम्नलिखित वस्तुओं पर व्यय निम्न प्रकार हुआ है :–

1.	दवाइया	37. 28 लाख

2.	पट्टियां	7. 14 लाख
3.	यन्त्र	18.86 लाख
4.	वाहन	शून्य

(ग) कुल स्वीकृत आचार्य 39, टीचर्स – 177 (सहयोगी आचार्य / रीडर / लैक्चरारज), रजिस्ट्रारज / डिमांस्ट्रेटरज 151 और नर्सिज –367 पदों में से केवल क्रमानुसार 10,33,60 तथा 53 पद ही रिक्त पड़े हुए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र० स०	पद का नाम नाम	कुल रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं रिक्तियों की संख्या	वर्ष
1.	प्रोफैसरज	10	2	1978
			1	1980
			1	1983
			4	1984
			2	1985

2.	टीचर्ज (सहयोगी आचार्य / रिडर / लैक्चरारज)	33	14	1975
			2	1981
			9	1984
			8	1985
3.	रजिस्ट्रारज / डिमांस्ट्रेटरज	60	1	1983
			14	1984
			42	1985
			3	1986
4.	नर्सिज	53	53	1985

प्रोफैसरज / टीचर्ज की रिक्तियों को भरने बारे साक्षात्कार मार्च, 1986 में होने हैं जबकि रजिस्ट्रारज / डिमास्ट्रेटरज के पदों को भरने बारे साक्षात्कार पहले ही हो चुके हैं और चयन किए जा चुके हैं । रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Hospital in Ambala City

208. Master Shiv Parshad and Shri Fateh Chand

Vij : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that foundation stone for the construction of a hospital in Ambala City was laid by the Chief Minister of the State ; if so, the date on which it was laid ;

(b) whether the construction of the said hospital is in progress ; and

(c) the time by which the construction of the said hospital is likely to be completed ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती करतार देवी) :

(क) जी हां, 1 1– 2– 198० को ।

(ख) जी नहीं । तथापि स्टाफ के लिये 45 रिहायशी भवन और नर्सिज होस्टल पूर्ण हो चुके हैं ।

(ग) पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

एन ० आइ ० टी ० फरीदाबाद में बिजली की भारी कमी तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाईयों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री ए ० सी ० चौधरी एम ० एल ० एं ० की ओर स एन ० आई ० टी ० फरीदाबाद में शार्टेज आफ पावर/इलैक्ट्रीसिटी की वजह से फैक्टरीज के बन्द होने, एम्पलाइज के जौबलैस होने तथा

स्टूडैन्ट्स को पढ़ाई में बड़ी मुश्किल आने सम्बन्धी काल अटैन्शन का नोटिस मिला है । मैं इसे एडमिट करता हूं । वे अपना नोटिस पढ़ दें ।

Shri A.C. Chaudhri (Faridabad) : I want to draw the attention of the august House towards a matter of urgent public importance that due to acute shortage of power/electricity in N.I.T. Faridabad, most of the factories are at the verge of closure and employees of such factories are being rendered jobless. The situation so created has resulted in great discontentment amongst the labourers. Moreover due to non-availability of domestic electricity supply, the house-wives in general and the students in particular whose examinations are drawing very nearer are greatly hard hit. The patients are also feeling great hardship and difficulties on this account.

Accordingly, to the latest regulatory hours of supply of power/ electricity, it has been generally observed that after 10.00 P.M. at night, there is frequently no street light and some time complete darkness. This state of affairs has increased large number of thefts and the anti-social elements have also become very active.

I, therefore, draw the attention of the Government and request that the Govenment should make a statement on this matter on the floor of the House as the matter is of great public importance, recent occurence and of serious nature.

श्री अध्यक्ष : आप इसका जवाब कब देंगे?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमसेर सिंह सुरजेवाला) : अभी द देता है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

वक्तव्य–

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Power to Faridabad area including New Industrial Town-ship is supplied from two sources i.e. 220 K.V. substation, Ballabgarh and State's own Thermal Power Station at Faridabad. While power generation at State's own Thermal Power Station is controlled by Haryana State Electricity Board, the power received from 220 K.V. substation, Ballabgarh is under the control of Bhakra-Beas Management Board. Both the above sources are connected through a 66 K.V. ringmain system, which is never switched off. The power supply to all the sectors in Faridabad area has been satisfactory by and large as per regulatory measures during recent months. However, at times, when restrictions are imposed by Bhakra-Beas Management Board, to control consumption from 220 K.V. substation, Ballabgarh, deviation from the regulatory measures has to be made. The power supply position in respect of the consumers mentioned by the Hon'ble Member was as below :—

Industries :

The power to the industries was supplied for 6 hours a day for 4 to 5 days a week during the months of December/January. The 3rd Unit of 60 MW at Faridabad Thermal was under capital maintenance in December/January with the result that whenever Bhakra Beas Management Board imposed restrictions from 220 K.V. substation, Ballabgarh, lesser power was supplied to industries on some days, due to low availability.

Domestic Supply :

Power to the domestic consumers was given regularly from 5.00 P.M. to 8.00 A.M. everyday in the recent months. However, during month of January, 1986 for 15 to 20 days, the power to domestic consumers had to be switched off for 2 to 6 hours in order to restrict our demand during night time on account of less power availability.

Hospitals :

Power supply **to** the hospitals is considered as essential service and is maintained round the clock. In Faridabad area, there are no independent feeders for supply of power to hospitals. Still utmost efforts were made to maintain supply of those feeders round the clock. Since the hospitals are getting power through mixed feeders, at times, there is a possibility of interruptions for short durations because of local faults.

Street light :

The power supply to the street light is in conformity with the power supply during night to the urban feeders,

which were kept switched on from 5.00 P.M. to 8.00 A.M. by and large, but for a few days in January 1986, as mentioned earlier in the case of domestic consumers.

The power supply to the State as a whole and Faridabad in particular, improved substantially with effect from 10th February, 1986 due to better availability from all sources including State's own Thermal Power Stations. Sir, you will be glad to know that the plant load factor of Panipat and Faridabad Thermal Power Stations in January and February was as under :-

"At Panipat, it was 56.27 % in January and 40 % in February. At Faridabad, it was 33.93 % in January and it increased to 42 % in February."

On the instance of the State Government and thanks to the personal intervention and interest of the Union Minister of Energy, the State started receiving its full share of power from Central projects and in addition, has also started receiving Central assistance to the tune of 10 to 20 lakhs units a day with effect from 17th February, 1986. From 18th February, 1986, the power regulatory measures have been relaxed to a great extent with the result that industries in Faridabad rare presently getting power for about 8 to 10 hours a day for five days a week. All restrictions on domestic consumers in the State have been withdrawn and they are getting supply round the clock presently.

Besides that, I would like to take the House into confidence and inform the hon. Members about the power position, the total installed capacity in the State and the new

power station etc. which is coming up in the State. If you compare the power position as was in March, 1967 and on 31st December, 1985, the comparative statement shows that the installed capacity in March, 1967 was 343 M.W. and on 31st December, 1985, it was 1445.5 M.W. The length of high/low tension lines in March, 1967 was 18663 KMs. and on 31st December, 1985, this length increased to 120054 K.Ms. Sir, the number of electric pumping sets in March, 1967 was 20190 and as on 31st December, 1985, this number was 274003. The number of general consumers in March, 1967 was 223903, but this number of general consumers was 1776201 on 31st December, 1985. Commercial consumers in March, 1967, were 57875 but this figure now increased to 185144. The number of industrial connections in March, 1967 was 9749 and it was 53935 on 31st December 1985. The per capita consumption, which is a sign of progress of the State and the country, was 57 K.W.H. but now it is 236 K.W.H.

which, I think, is in a very few States as in Haryana. Further, I would like to inform the House that the total installed capacity at present is 1445.5 M.W. Out of this, 415 M.W. is from the local thermal power stations and 1030.5 M.W. is from outside the State i.e. from the Hydro and other sources. During the Seventh Plan period, a sum of Rs. 1010 crores has been set apart for power generation projects and distribution system in the State. The total installed capacity is likely to increase to 2222 M.W. at the end of the Seventh Plan. Sir, if I include the Yamunanagar Thermal Plant, about which the Union Energy Minister has assured that the financial help for this project will be available to the State and it will be completed within

the Seventh Plan, the installed capacity of which may be 300 M.W., the total installed capacity will be more than double at the end of the Seventh Plan. Sir, in the Seventh Plan, 5 lakh new connections will be given, out of which 75000 will be of tubewells and 20000 will be of industries. Sale of power envisaged in the agriculture sector is about 40 %. The twelvth annual survey report has indicated the shortage of 445 M.W. in the installed capacity of the State by 1989-90 and the energy deficit will be 351 million units But after the generation from the Yamunanagar Thermal Powe Station starts coining, then it will be totally wiped out and there will be no shortage of power in the State at the end of the Seventh Plan. The cause of shortage of power in the recent past was the shortage in the generation in Central power projects on an average of 9 to 10 lakh units per day. The State Government and the Haryana State Electricity Board are making strenuous efforts to i mprove the generation.

We are also taking steps to improve the PLF of the existing plants and also taking effective steps for renovation wherever necessary, Sir, and certain steps have already been initiated to increase the PLF of the thermal power stations in Haryana. Out of 243 technical officers working at Faridabad and Panipat Thermal Plant stations, 137 graduate engineers have undergone thermal training at Test Institute of Badarpur and Nagpur. 150 diploma engineers have also undergone training at Test Institute at Badarpur and Nagpur. A thermal training institute for the training of operators and technicians has been opened at Panipat thermal plant station and a batch of 20 technicians has already under gone this training. We have also taken certain measures for enforcing discipline and I

would like to tell the House that from Faridabad and Panipat thermal plants more than 400 persons were surplus at each of the plant. They have been shifted to outside the State in the recent past and they have been deployed in the field and that has restored a very good discipline at both the plants. Besides that, a separate generation cadre is being created to increase the dedication and the efficiency of the staff of the plants. The PLF after November, 1985 is showing improye ment. The PLF in January, 1986 at Panipat is more than 56 %. For renovation and modernisation of the two plants, a sum of Rs. 40 crores for Faridabad and a sum of Rs. 16 crores for Panipat has been sanctioned and the work on these projects has already been taken in hand in consultation with C.E.A. Shri Vasant Sathe, Union Energy Minister, was at Panipat on 16th February and the Hon'ble Chief Minister was also there. The Union Energy Minister has assured that the State will not only get its own share from the plants which are situated outside the State but an additional 10 lakhs units per day will be given to Haryana and this additional power of 10 lakhs units per day has started coming from 17th of this month. That is why, from 18th February all the restrictions on domestic supply have been removed and more power is available to the industrial as well as to other sectors. I hope the HSEB will maintain this level. Thank you, Sir.

Shri A.C. Chaudhry : Sir, I a m thankful to the Hon'ble Irrigation and Power Minister for having come out with facts and figures which, of course, I partly refute. But as on date I may not be in a position to give my full version regarding the enhanced generation claimed by the Hon'ble Minister and the steps taken by the Government for improving

the same. But on the contrary, I would like to draw your kind attention and that of the House that the Hon'ble Minister has claimed that the Government has made 6 hours assured supply to Faridabad. It is not a mockery with the common sense that those who have spent crores and crores of rupees by installing their industries in Faridabad, which not only add to the production of the country but also provide the employment to a large number of people, who, if otherwise, may have become a permanent burden on the State Exchequer and headache for the Government? By providing only six hours electricity, if the Government claims that they have been successful in providing electricity, this is anybody's guess. Anyhow, with regard to the rural industries, the Government on one hand is giving incentives after incentives just to facilitate the technocrats to go in for self employment. We are not providing electricity even for six hours a day. We are expecting the industries to add to the production by working round the clock. Simultaneously, there are 4,000 small industries on urban feeders in Faridabad, which are being regulated in 5 hours shift. Over and above that, water supply of Faridabad is dependent upon the availability of electricity because there is no reservoir in Faridabad nor there is any other source barring only tubewells. So one can very well imagine the fate of the residents of the areas, who are getting only water supply only for two hours. My learned friend, Hon. Minister has quoted in his reply that light is available right from 5 P.M. to 8 A.M. With due apology, I contradict it. Normally, switches are made on at 6 A.M. You can very well imagine, Sir, and this House will appreciate the students, who are supposed to attend their classes by 8 O'clock, they will get up at 4 O'clock to prepare for the examination if they get

power or electricity at 6 O'clock. One can imagine what type of students we are bringing out and what the fate of the students would be. Hon'ble Speaker, Sir, over and above the voltage is also the problem for us. If we get power for 2 or 3 hours. the voltage is very much low. Even in hospitals, there is a general complaint from the patients that X-rays could not be done because of low voltage. Is it not playing with the lives of those who very much depend upon the Government for their immediate rescue ? Sir, while the Government has claimed that the power is available...

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप सवाल पूछिए ।

श्री ए ० सी० चौधरी : मैं तो उसी के बारे में कह रहा हूं जो इन्होने कहा

श्री अध्यक्ष : जो कुछ इन्होंने कहा है वह आप मत कहिए । आप सवाल पूछ ले ।

श्री ए० सी ० चौधरी : मेरी तरफ से तो यही सवाल है कि मेरे इलाके में बिजली की कमी के कारण काफी परेशानी है । सरकार कहती णै कि पांच घंटे बिजली सप्लाई होती है । स्पीकर साहब, चौबीस घंटे चलने वाले कारखाने पांच घंटे की बिजली सप्लाई से कैसे काम चला सकते है? मैंने एस ० सी ० एस० भी भेजा कि मेरे इलाके में लेबर अनरैस्ट हो रहा है, इमिजिएटली बिजली की सप्लाई बढ़ाई जाए । कारखाने डीजल पर ज्यादा डिपैन्ड नहीं कर सकते । इसलिये सरकार प्री तरह से ध्यान देकर इलाके की प्रोबलम को सौल्व करे ।

Chaudhri Shamsher Singh Surjewala : Sir, the H.S.E.B. and the Government are not to be blamed for all the things which Shri A.C. Chaudhri has said because as far as the question of availability of power to hospitals and water supply schemes is concerned, I have already told that they have no separate feeders. A separate feeder is not to be provided by H.S.E.B. The H.S.E.B. will only provide power and the feeder will be got installed by the hospital authorities. It is for them to have a separate feeder. If they do not have a separate line, they are on the mixed feeder and we try to feed them on the mixed feeder.

If a line is common, the interruptions are bound to occur. As far as power supply to the water supply scheme is concerned, I have the same argument. The Public Health department is supposed to have a separrate feeder. We are prepared to feed separetely to all the essential services throughout the State Which we are already doing . There may be less availability of power but if they do not have separate feeders for water supply, hospitals, telephones and other essential services, then we are not to be blamed. That may be the reason for the X-rays which , he said, for not being taken, on a mixed feeder there may be industrial load, there may be domestic load and there may be commercial load and naturally the voltage will drop out. The hospital may be at the fag end of the line. As far as the supply of electricity to industries and the domestic sectors **is** concerned, I have never stated that it was absolutely from 5 P.M. to 8 A.M. on all days. I have admitted, Sir, if he has tried to listen, that in January for 10 to 20 days there was a serious problem. The supply was very less and we could not feed the whole of the night. So, during

the nights lights were switched off for 6 hours, sometimes for 4 hours and even sometimes for two hours. Now, everything has been restored. As far as industries are concerned, the policy of the State Government is very clear. We will certainly give power to the industries but our priority is for agriculture. Therefore, at that time, when the agriculture load and the agriculture demand was at the peak, the State Government and the H.S.E.B. certainly tried to fulfill its obligation to that sector. We first of all try to feed agricultural sector and then certainly if we have power we try to give power to industrial sector as well as to other sectors. In the face of less availability of power, we have divided the State in three zones for the last one and a half years and after that I can say one thing surely that there is no discrimination with any area or with any sector and we are trying to feed everybody but it all depends upon the availability of power. As soon as it has improved, we have started giving power to Faridabad and other industries. I have said that it is about 8 to 10 hours a day but actually the figure may be more than 10 hours a day. I have deliberately scaled it down and stated that it is being supplied for about 8 to 10 hours a day. Actually, we are supplying for more than 10 hours a day. I cannot assure that it will be always more" than 10 hours to the industries. But we will try to give 8 hours supply to industries a day and we will try to do our level best to improve it.

सदन की मेज पर रखे गये कागज– पत्र

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहिबान, अब मन्द्री महोदय टेबल आफ दी हाउस पर पेपर्ज ले करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table —

The 13th Annual Report and Accounts of the Haryana Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1979-80, as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 14th Annual Report and Accounts of the Haryana Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1980-81, as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 18th Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation Ltd. for the year 1984-85, as required under section 38(3) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Audit Report on the Accounts of the Haryana Financial Corporation Ltd. for the year ending 31st March, 1984, as required under section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Beard for the year 1983-84, as required under section 75(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Annual Financial Statement for the year 1985-86 and revised Estimates for the year 1984-85 of the Haryana State Electricity Board as required under section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The 17th Annual Statement of Accounts for the year 1983-84 of the Haryana State Electricity Beard as required

under section 69 (4 & 5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The statement showing loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15th January, 1986 for which the State Government stood guarantee for repayment thereof as required under section (6 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(i) The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1983-84 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

(ii) The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1983-84 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

(iii) The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1983-84 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Health Department Notification No. G.S.R. 2/P.A.16/65/S.53/85, dated the 27th December, 1985 regarding the Haryana Homoeopathic Practitioners (Election) Rules, 1985 as required under section 55 of the Punjab Homoeopathic Practitioners Act, 1965.

सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (सैकिण्ड इंस्टालमैट) 1985– 86 पर चर्चा तथा मतदान

(1) राज्य के राजस्व पर प्रसारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा ।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब ईयर 1985–86 के सप्लीमैन्ट्री ऐस्टीसेट्स (सैकिण्ड इंस्टालमैट) पर डिस्कशन होगी । जो आनरेबल मैम्बर्ज चार्जड आइटमज को डिस्कस करना 'चाहे, वे कर सकते है तथा पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाइम सेब करने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गयी साल डिमांडज फार ग्रांटस will be deemed to have been read and moved. आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वह उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं । डिस्कशन के बाद डिमांड्ज हाउस की वोट के लिए पुट की जायेंगी ।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,51,780 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 1--Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,70,58,100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,56,19,000 for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 198.6_ in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45,07,860 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 5 Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,35,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,48,01,596 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,41,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 58,36,734 for revenue expenditure-be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand. No. 12—Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 for revenue expenditure and-Rs. 10,00,000 for capitalexpenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and. Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 42,28,000 for revenue expenditure and Rs. 10,27,28,000 for capital expenditure to granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 14—Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,3],66,000 for revenue evpenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,20,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48,26,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 32,82,250 for revenue expenditure be granted to the Governor

to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986, in respect of Demand No. 19—Fisheries.

That a 'supplementary sum not exceeding Rs. 20.00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 20—Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,38,82,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 23—Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,48,00,165 he granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 25 —Loans and Advances by State Government.

श्री भले राम (बड़ौदा–एस ० सी ०) : स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार इस सदन से, कुछ पैसा जो पहले ही खर्च कर चुकी है और जिसका प्रोवीजन बजट में नहीं था, उसकी स्वीकृति लेना चाहती है और यह सारा पैसा 88 करोड़ 77 लाख के लगभग है । उसमें से, 16 करोड़ 51 लाख रुपया प्लान साइड के तहत और 72 करोड़ 28 लाख रुपया नौन प्लान साइड के तहत मांगा गया है । मैं डिमांड नम्बर 4,920 और 25 के? बारे में अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा । डिमांड नम्बर 4 के

तहत 2 करोड़ से ऊपर की राशि सरकार द्वारा मांगी गयी है । स्पीकर साहब, पीछे जब फल्ड आया था तो कई गांवों में बरबादी हुई थी । लोगों के मकान वगैरह बाढ़ के कारण गिर गये थे और लोगों की काफी हानि भी हुई थी 1 इसके लिये हरियाणा सरकार ने पैसा मांगा है । अच्छी बात है कि जहां बाढ़ आती है वहां सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिये लेकिन सरकार ने मकानों की मरम्मत के लिये 500– 600 रुपए की जो राशि निर्धारित की है यह बहुत ही थोड़ी है । इतने पैसों में तो एक ईंटों का, सीमिन्ट का ट्रक तक नहीं आता, मकान की मरम्मत क्या होगी? इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इस राशि को और बढ़ाना चाहिये ताकि लोगों को कुछ न कुछ राहत मिल सके । फलड के कारण हर साल हरियाणा के अन्दर बरबादी होती है । लगभग 18 लाख हैक्टेयर इलाका हर साल फलड से बरबाद होता है लेकिन सरकार के आकड़े अब यह बताते हैं कि 16 लाख हैक्टेयर पर अब सरकार ने कंट्रोल कर लिया है । केवल 2 लाख हैक्टेयर जमीन बचती है जहां पर अब भी फलडज आते हैं । अब सरकार ने कहा है कि इस साल 15 हजार हैक्टेयर जमीन के इलाके को प्रोटैक्ट करेंगे । इस फलड का सरकार को सदा के लिये पक्का इन्तजाम करनी चाहिए । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने फलड कंट्रोल के लिये 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । यह बहुत अच्छी बात है । सरकार को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिये ताकि फलड का रोग सदा के लिये काटा जा सके जिससे लोगों को राहत मिले और हरियाणा

का कोई गांव बरबाद न हो । इसलिये इस मांग को पास किया जाए ।

11.00 बजे ।

स्पीकर साहब, इससे अगली डिमांड नम्बर 9 है जोकि शिक्षा' से संबंधित है । इसमें 7 करोड़ से कुछ ज्यादा धनराशि की मांग की गयी है । प्राइमरी और मिडिल श्रेणियों की पाठ्य 'पुस्तकें बदल जाने के कारण बाहर की प्रैसों से पाठ्य पुस्तकों की छपाई के कारण इस राशि की मांग की गयी है । पहले ये पुस्तकें ऐजुकेशन बोर्ड खुद छपवाता था । उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, चीपर भी पड़ती थीं और समय पर पुस्तकें अबेलेबल हो जाती थीं । आप इसके लिये आकड़े उठा कर देख लीजियेगा । अब क्या होता है कि बाहर की प्रैसों से छपवाने के कारण ये पुस्तकें न तो समय पर मिलती हैं, न ही चीपर पड़ती हैं और न ही उनकी क्वालिटी ही अच्छी होती है । सरकार के इस प्रकार के कदम उठाने का क्या फायदा है? इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन पाठ्य पुस्तकों की छपवाई का काम सरकार एजुकेशन बोर्ड को सौंप दे ताकि ये पुस्तकें समय पर उपलब्ध हो सकें और बच्चों क्रो किसी प्रकार की असुविधा न हो । आज भी ये पुस्तकें बाजारों में उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे । दूसरी बात एजुकेशन की है । स्पीकर साहब, गोहाना में कुछ गांवों में सरकार ने एडल्ट एजुकेशन सैंटर खोले हैं । यह अच्छी बात है, पहले ये सारे सैंटर सोनीपत में थे और हमारा गोहाना कवर नहीं

हुआ था । इससे यह भी फायदा हुआ है कि वहां पर जो लेडीज पढ़ाती हैं जिनके पास कोई काम नहीं था, अब उनको सौ रुपया महीना मिल जाता है। मैं चाहूंगा कि यह पैसा बढ़ाया जाना चाहिए । यह ठीक है कि यह स्कीम सैंटर की है लेकिन हमारी सरकार भी इसमें कुछ मदद कर सकती है या सैंटर से और पैसा मांग सकती है । सैटंर तो गोहाना में जरूर खोल दिए गए लेकिन वहां का जो एडल्ट एजुकेशन अफसर है, वह गोहाना की बजाए सोनीपत में बैठता है । सोनीपत में बैठ कर वह सैटरों की चौकिंग कैसे कर सकता है? इसलिये मैं चाहता हूं कि उसका हैड क्वार्टर गोहाना में होना चाहिए ताकि वह सभी सैटंर्ज की चौकिंग कर सके । अगली बात मैं लोन्ज एंड एडवांसिज की कहना चाहता हूं जो डिमांड नम्बर 25 के अन्डर है । यह अच्छी बात है कि जो हमारे फोर्थ क्लास के ऐम्पलाईज है उनको व्हीट लोन दिया जाता है या दीवाली के टाइम पर फैस्टीवल लोन दिया जाता है । यह पैसा. उसके लिये सरकार ने मांगा है । व्हीट लोन के लिए सरकार चार सौ रुपया देती है जोकि क्लास फोर .एम्पलाईज को मिलता हैं, पहले तो यह लोन सभी एम्पलाईज को मिलता था । इस बारे में मैं गुजारिश करूंगा कि मंहगाई को देखते हुए यह राशि थोड़ी है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऐम्पलाईज बढी हुई कीमतों के अनुसार अपनी जरूरत की गेहूं खरीद कर रख सकें । स्पीकर साहब, मांग नम्बर 20 फौरैस्ट की है । हरियाणा सरकार की अच्छी स्कीम है कि उसने सारे प्रदेश में दस करोड़ से भी ज्यादा पेडू लगाए हैं । स्पीकर साहब, आपको पता है 23 तारीख

को किस ढंग से पेड़ू काटे गए और सरकार का कितना नुकसान हुआ । मैं चाहता हूं कि जितना नुकसान हुआ सै उसकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं और असो के लिए ऐसा नुकसान न होने का इंतजाम किया जाए । पेड़ों से जहां हमें इकनौमिक फायदा होता है, वहां दूसरे भी बहुत फायदे होते हैं जैसे ज्यादा पेड़ू होने से वाता– वरण साफ रहता है तथा इनसे बारिश होती है । इसलिये इनका बहुत महत्व है, इनको प्रोटैक्ट करना चाहिए । इसके अलावा, मैं फारैस्ट गार्ड्स के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने इनको बहुत ज्यादा पावर दे रखी हैं । मैं यह नहीं कहता कि इनको लगाया ही न जाए । अगर किसी का पशु कहीं पर थोड़ा मुंह मार देता है तो ये नोटिस दे देते हैं कि पांच सौ रुपए का नुकसान हो गया । नोटिस में ये ऐसे आदमी का नाम लिख देते हैं जिसके साथ इनकी कोई नाराजगी हो । इसलिये इनको इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए । इसके अलावा, हर एक डिमांड में किश्तों की बात आई है कि मंहगाई बढ़ने की वजह से एम्पलाईज को डी० ए० की किश्तें दी गईं । यह अच्छी बात है कर्मचारियों को ये किश्तें दी जानी चाहिए । हमारी हरियाणा सरकार देश में पहली सरकार है कि जो सैटर अपने कर्मचारियों को किश्तें देता है, उसके साथ ही सबसे पहले यह अपने कर्मचारियों को दे देती है । इस बारे में हमारे मुख्य मन्त्री फौरन घोषणा कर देते हैं लेकिन यह कब तक चलेगा । मैं चाहता हूं कि मंहगाई को रोकना चाहिए । आज प्राइस इंडैक्स कितना ऊपर चला गया है, हमें चीजों की प्राइस फिक्स करनी चाहिए । इसलिये इसकी ओर भी

ध्यान दिया जाए । हमारे एम्पलाइज की समय–समय पर इस सरकार ने मदद की है, जब भी मौका आता है तो हमारी सरकार पीछे नहीं रहती । इसके साथ साथ मैं यह भी आशा करता हू कि अब जो सैटर के या पंजाब के पै–कमिशन की रिपोर्ट आएगी, हमारी सरकार इस बारे में भी पीछे नहीं रहेगी । इसके लिये या तो हरियाणा सरकार अपना अलग से पै–कमिशन बनाए या जो पैट्रन पंजाब के पे– कमीशन का होगा, या सैटर का होगा, उनको मद्दे नजर रखते हुए यहां पर भी वे स्केल लागू करे । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि ये सारी डिमांडज पास कर दी जाएं ।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पेश हुए हैं, मैं भी इनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं विशेषतरू डिमांड नं० 9, 15, 17, 13, 20 और 23 पर अपनी बात कहना चाहूंगा । डिमांड नं ० 9 एजुकेशेन से संबंधित है जिसमें 7,41, 01,000 रुपए रखे गए हैं । स्पीकर महोदय, आपको पता है कि एजुकेशन विभाग बहुत बड़ा विभाग है । गांवों में जितने स्कूल हैं तकरीबन सबको पंचायतें बनाती हैं लेकिन उन स्कूलों की इतनी अच्छी हालत नहीं है और बारिश के दिनों में बच्चों को बैठने के लिए बहुत तकलीफ होती है । (इस समय थी उपाध्यक्ष पदासीन हुए) बच्चों को गर्मियों में भी बहुत तकलीफ होती है इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू । जहां पर स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी नहीं है उनको रिपेयर वगैरह के लिए ज्यादा पैसा देकर

उनकी हालत सुधारी जाए । इसके अति– रिक्त उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है और अखबारों में भी छपा है कि टीचर्ज सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं । विशेष तौर पर जो टीचर्ज देहात में लगे हुए हैं उनका यह ग्रीवैस है कि शहरों के टीचर्ज को हाउस ' रैट भी मिलता है और उनको ट्यूशन का भी फायदा होता है लेकिन गांव के टीचर्ज को ये सुविधाएं नहीं मिलतीं । टीचर्ज ने हर एम०एल०ए० को अपना मांग पत्न दिया था मेरा ख्याल है कि सब को मिल गया होगा । मैं अनुरोध करूंगा कि ये अध्यापक हमारे समाज की सब से बड़ी सेवा करते हैं । जो हमारे बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, इनका चरित्र निर्माण इन्होंने ही करना है इसलिये सरकार को इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए और यह जो पैसा रखा गया है इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हुए उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अब मैं डिमांड नं ० 15 जो इरीगेशन से संबंध रखती है, पर कुछ कहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी जिले से संबंध रखते हैं जिससे मैं रखता हूं । आपको पता है कि हमारी सिंचाई के साधन ट्यूबवैल्ज हैं और नहर का पानी हमारे यहां नहीं है । इसके साथ यह भी सब को पता है कुरुक्षेत्र जिला पैदावार के लिहाज से सारे हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में सब से आग्हे है । धान और गेहूं की उपज पिछले साल जो हमारे किसानों ने पैदा की है वह रिकार्ड तोड़ है । यह भी उसके बावजूद है कि हमें बिजली जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल

पाती है । मिसाल के तौर पर थानेसर, रादौर और शाहबाद हल्कों में नहर की सिंचाई नहीं है । वैसे तो बताया गया है कि सातवीं योजना के अन्दर इसके लिए कुछ पैसा रखा गया है । अगर इन हल्कों में नहर की सिंचाई हो जाए तो इस जिले के किसान और भी पैदा कर सकते हैं । इसके साथ–साथ ट्रांस– फारमर्ज की बात है क्योंकि लोड कम होता है, जैसे कहा भी गया है और ट्यूब–वैल्व के पानी का लैवल इतना नीचा चला गया है कि 5 हार्स पावर की मोटर पानी नहीं उठाती, साढ़े सात हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ती हे । इसके अलावा, ट्रांसफारमर्ज पर ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वे सड़ जाते हैं और कई बार कई गांवों के ट्रांसफारमर्ज एक–एक महीने तक तबदील नहीं होते हैं क्योंकि ट्रांसफारमर्ज की रिपेयर करने के लिए हमारे जिले कुरुक्षेत्र में कोई वर्कशाप नहीं है । ट्रांस– फारमर्ज की रिपेयर्ज का काम धूलकोट में होता है इसलिए उसमें काफी समय लग जाता है । मैंने मुख्य मन्त्री जी और आई० पी० एम ० साहब से यह मांग की थी कि आप हमारे कुरुक्षेत्र जिले में जो भी उपयुक्त स्थान समझें, वहां एक ट्रांसफारमर्ज की रिपेयर्ज के लिए एक वर्कशाप खोल दें । कुरुक्षेत्र में एक मसाना गांव है, वहां पर 33 के एसी ० का सबस्टेशन भी है, यदि वहां पर ट्रांसफारमर्ज की रिपेयर्ज के लिए एक वर्क शाप खोल दी जाए तो सरकार को उसके लिए जमीन भी एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी । यदि उस गांव में वर्कशाप खोल दी जाती है तो ट्रांसफारमर्ज की रिपेयर्ज के लिए धूलकोट नहीं आना

पड़ेगा और किसानों को भी काफी सहूलियतें हो जाएंगी । इस डिमांड के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता था ।

अब मैं डिमांड नम्बर 17 जोकि एग्रीकल्चर के बारे में है, अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जै से मैंने पहले कहा कि कुरुक्षेत्र जिला उत्पादन के लिहाज से सबसे आगे है । कुरुक्षेत्र जिले में केवल धान और गेहूं की फसल' ही ज्यादा नहीं होती बल्कि गन्ना भी बहुत ज्यादा माता में होता है । गन्ना पैदा करने में भी कुरुक्षेत्र जिला बहुत आगे है । एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट वैसे तो किसानों की बहुत सेवा कर रहा है लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार किसानों को जो सबसिडी वगैरह दी जानी होती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है वह जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही गड़बड़ हो जाती है । मैं कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के लूपहोल हैं, वह महकमे को मजबूती के साथ ठीक करने चाहिएं ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आए । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 18 ऐनीमल हस्वैडैरी के बारे में है जिसके बारे में सदन के अन्दर पहले भी कई बार चर्चा हुई है और एक क्वैश्चन के माध्यम से यह सूचना मांगी गई थी कि देहातों और शहरों में कितने कितने हस्पताल हैं । जवाब में हस्पतालों की संख्या बताई गई थी और उससे मालूम हुआ कि देहातों में भी काफी पशु हस्पताल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर पशु हस्पताल और स्टोकमैन सैंटर नहीं हैं । यदि उन गांवों में पशु

बीमार हो जाते हैं तो उनको शहर के पशु हस्पताल में ले जाना सख्त ही कठिन होता है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे गांवों में पशु हस्पताल या स्टोकमैन सैटर खोले जाएं । गांव वाले उसके लिए बिल्डिंग भी बना कर देने के लिए तैयार हैं । जिन गांवों में वैटरनरी होस्पिटल या स्टोकमैन सैटर नहीं बै उन गांवों में डेरी डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के तहत वैटरनरी होस्पिटल या स्टोकमैन सैटैर खोले जाने चाहिएं । मेरे हल्के में भूत माजरा, धांदला और सिरसला गांव हैं उनके अन्दर स्टौकमैन सैटर खोले गए थे । एक, महीना काम करने के बाद उन सैटंर्ज को बन्द कर दिया गया और उनको वहां से तबदील करके किसी दूसरी जगह ले गए । मुझे बताया गया कि अम्बाला कमिश्नर ने शायद ऐसा किया था । मैंने इस बारे में मन्त्री महोदय से बात की कि उन सैंटर्ज को बन्द करने का कोई तुक नहीं है, उनको चालू किया जाए । लेकिन उन को दोबारा चालू नहीं किया गया है । मैं आज फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन तीनो स्टौकमैन सैंटर्ज को दोबारा चालू किया जाए ताकि उस एरिया के लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े । मेरे हल्के में कई गांव ऐसे हैं जहां क्र लोगों को यह सुविधा नहीं है । उन गांवों के लोग सरकार को जगह देने के लिए तैयार हैं और बिल्डिग बना कर देने के लिए तैयार हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि ऐसे गांवों में स्टौकमैन सैंटर और वैटरीनरी होस्पिटल खोले जाएं ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 20 फौरैस्ट के बारे में है । इस डिमांड के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । फौरैस्ट के बारे में सरकार की स्कीम है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ू लगाए जाएं । यह अच्छी बात है, पेड़ू लगने चाहिए । एक स्कीम सोशल फौरैस्टरी की है । इसके लिए सरकार ने अभी पीछे फैसला किया था कि जो पंचायतों की लैड खाली पड़ी है उनमें सोशल फौरैस्टरी लगाई जाए । पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दिया कि पंचायतों की जमीन में सोशल फौरैस्टरी लगाई जाए । उसके बाद पंचायतों की जमीनों पर सोशल फौरैस्टरी लगाने का काम शुरू हुआ लेकिन उसके साथ साथ झगड़े भी पैदा हो गए । जिन पंचायतों ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके दिया है, उन गांवों में गरीब हरिजनों और दूसरे लोग जिनके पास जमीन नहीं हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है । वे लोग कहते हें कि अगर पंचायतों की सारी जमीन सोशल फौरैस्टरी लगाने के लिए ले ली गई तो हमारे पास अपने पशु खड़े करने के लिए भी जगह नहीं रहेगी । कई गांवों में इस तरह के झगड़े पैदा हो गए हैं । मेरे हल्के में एक बकाली गांव है । उस गांव की पंचायत ने अपनी जमीन में फौरैस्टरी लगाने के लिए कहा । फौरैस्ट डिपार्टमैंट ने उसमें फौरैस्टरी लगाने के लिए गड्ढे भी खोद दिए और उनमें नर्सरी के पौधे भी लगाने के लिए लेकर आ गए लेकिन किसी वजह से उस काम को रोक दिया गया । उस याव में बहुत टैन्शन पैदा हुई । मैंने भी उन गांवों वालों का समझौता करवाने की कोशिश की ताकि टैन्शन का किसी तरह

निपटारा हो जाए । वह काम अभी तक पैंडिंग पड़ा है । द्रुम चाहते हैं कि फौरैस्टरी लगे और लोगों का भला हो लेकिन कई गांवों में झगड़े पैदा हो गए । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि ऐसी बातों का किसी अच्छे ढंग से निपटारा किया जाए । मैं इस बारे में सरकार को द्बाव देना चाहूंगा कि गांवों में जिन लोगों के पास अपने पशु वगैरह खड़ा करने के लिए जमीन नहीं है, 'उनके लिए जमीन रिजर्व रख करके बाकी पंचायत की जमीन पर फौरैस्टरी लया दी जाए जिससे उनमें कोई झगड़ा नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, अगली डिमांड नम्बर 23 ट्रांसपोर्ट के बारे में ' है । इस डिमांड के करे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छी है और लोगों को इससे बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं लेकिन फिर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोग सर्विस मांगते हैं. कि यहां पर बस रूट मिलना चाहिए लेकिन यह फैसिलिटी महकमा पूरी तरह से मुहैया नहीं कर 'पाया है । यह भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश का हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है जिसके कारण लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं लेकिन फिर भी बसों की कमी के कारण लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं नही मिलती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है लेकिन वहां बस डिपो नहीं है । कैथल में बस डिपो है । मैं सरकार से पिछले 3–4 सालों से मांग करता आ रहा हूं कि कुरुक्षेत्र में बस डिपो बनाया जाए । कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कालेज भी है और बहुत बड़ा धार्मिक शहर भी है । वहां पर बस अड्डा भी बहुत बड़ा है

इसलिए बस–डिपो बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कुरुक्षेत्र में बस–डिपो बनाया जाए । कैथल में भी बस–डिपो रहे लेकिन कुरुक्षेत्र में भी बनाया जाए । इस समय वहां पर सब–डिपो बनाया हुआ है, उसमें 52 बसें हैं, वे लोगों को पूरी सुविधा नहीं दे पा रही हैं । इन शब्दों के साथ मैं सभी सप्लीमैंटरी डिमांड्ज का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हू ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन (बरवाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । सबसे पहले मैं इन सभी सप्ली– मैटरी डिमांडज का समर्थन करता हूं । बोलने से पहले मैं उन डिमांडज का नाम बतलाऊंगा जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं । मैं डिमांड नम्बर 3, 4, 8, 9, 12, 15, 18, 23 और 24 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 3 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । यह डिमांड होम डिपार्टमैंट के बारे में है । पुलिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा की पुलिस ने कानून और व्यवस्था को ठीक रखने में बहुत अच्छा काम किया हैं। मैंने गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर बोलते हुए यह बात कई–! थी कि हरियाणा की पुलिस सारे हिन्दुस्तान में अच्छी है । मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा । पुलिस जहां इतना काम करती है इसलिये उसको कुछ सुवि– धाएं भी मिलनी चाहिएं । एक तो मेरा सुझाव यह है कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन

पर व्हीकल जरूर होने चाहिएं क्योंकि क्राइम को रोकने के लिए व्हीकल का होना बहुत ही जरूरी है । सरकार ने पुलिस स्टेशन पर जीप दी हुई है और किसी पुलिस स्टेशन पर मैटाडोर भी दी हुई है लेकिन शायद सभी पुलिस स्टेशनों पर नहीं हैं । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी पुलिस स्टेशंज पर व्हीकल दी जाएं । दूसरा मेरा सुझाव है कि जब नया पुलिस स्टेशन बनता है तो उसके पास एस०एच०ओ० और एम०एच०सी० के सार्टर बनाए जाएं । बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सभी पुलिस स्टेशन वालों के लिए क्वार्टर बना दिए जाएं लेकिन उसमें' पैसा ज्यादा लगता है इसलिए शायद सरकार सभी के लिए क्वार्टर नहीं बना सकती । लेकिन एस०एच०ओ० और एम०एच०एसी० दोनों के लिए पुलिस स्टेशन के पास क्वार्टर जरूर होने चाहिएं । अगर ये पुलिस स्टेशन से दूर रहते हैं तो वहां पुलिस स्टेशन पर पहुंचने में उनको बहुत टाईम लग जाता है और इतनी देर में जो क्राइम करता है वह भाग जाता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके क्वार्टर पुलिस स्टेशन के पास जरूर बनाए जाएं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक उकलाना मण्डी है । वहां पर पहले पुलिस स्टेशन नहीं था लेकिन अब सरकार ने द्रा पुलिस स्टेशन बना दिया है । वहां पर पुलिस स्टेशन तो बना दिया है लेकिन उसके लिए कोई बिल्डिंग वहां नही है । एक छोटा सा कमरा है, जिसमें पुलिस वाले बैठते हैं । इसके अलावा, पुलिस वालों ने एक और धर्मशाला को किराये पर लिया हुआ है । मैंने

सरकार को कई बार लिख कर दिया है कि वहां पर जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन बनाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 4 जो राजस्व के बारे में । है, कुछ कहना चाहूंगा । इसके बारे में मै यह कहूंगा कि 3– 4 गांवों के लिए एक पटवारी सरकार ने लगाया हुआ है । कई जगहों पर एक–एक गांव के लिए । एक–एक पट– वारी भी लगाया हुआ है । आप भी देहात के रहने वाले हैं और मैं भी देहात से ताल्लुक रखता हूं । आपको भी पता होगा और दूसरे साथियों को भी पता होगा कि पटवारी गांवों में नहीं रहते । शहर का रहने वाला पटवारी देहात में नहीं रहता । पटवारियों की यह कोशिश रहती है कि वे अपने घर पर ही बैठे रहें जबकि इससे लोगों को बड़ी भारी दिक्कत होती है । लोगों को कभी पटवारी से फर्द लेनी होती है तो कभी नकल लेनी होती है । इस काम के लिए पटवारी का गांव में न होना किसानों के लिए बहुत दिक्कत की बात है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पटवारियों को खासकर गांवों में रहने के लिए कहना चाहिए ताकि किसानों को या दूसरे लोगों को कोई दिक्कत न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं रोडज के बारे में कहना चाहूंगा । सड्कों के बारे में हम यह कहै सकते हैं कि यहां सड़कें बहुत अच्छी हैं । मैंने पहले भी कहा था कि नई सड़कें बनाई जाएं लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं यानि जो सड़कें बनी हुई हैं, उनकी मेन्टीनैसं की तरफ विशेष ध्यान दिया .....

सडकों को मेनटेन महीं करेंगे तो उनका बनाये जाने का कोई .... भी कहा था कि बरवाला से जीन्द एक .....पर पुल नहीं था । वह तो मैंने कोशिश कर .....उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए । .....आया था कि यहां की सड़कें इतनी अच्छी हैं .....लग जाता है कि यह हरियाणा आ गया है । .....हैं कि बस में बैठे बैठे यात्रियों के सिर .....सरकार से प्रार्थना है कि बरवाला से जीन्द ..... उसकी मेन्टीनैस की तरफ खास ध्यान .....

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा कें बारे में कहना चाहूंगा । शिक्षा मन्दी जी अभी बैठे थे लेकिन लगता है कि वे किसी काम के लिए सदन से बाहर चले गए हैं । शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें विशेष सुधार की जरूरत है । कल एक साथी ने बोलते हुए कहा था कि शिक्षा में एक नैतिकता का विषय भी होना चाहिए । हमने हर फील्ड में तरक्की की है । हमने आर्थिक सेव, सामा– जिक क्षेत्र व दूसरे सैदों में काफी तरक्की की है लेकिन हमारी मौरल वैल्यू कम हुई है, बढ़ी नहीं है । इसलिए किसी राष्ट्र की तरक्की के लिए मोरल विषय का होना जरूरी है । इसलिए मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि नैतिकता के बारे में बच्चों को जरूर बताया जाना चाहिए । मैं अपने ही गांव में एक बार शिक्षा मन्त्री को लेकर गया था । मैंने अपने गांव में लड़कियों

का एक गुरुकुल बनाया हुआ है और उसे 8वीं कक्षा तक सरकार की मान्यता प्राप्त है । अब गांव वालों ने करीब 5 लाल रुपये लगा कर 16 कमरे बना दिए हैं । मैंने दुबारा फिर शिक्षा मन्त्री जी का प्रोग्राम अपने गांव के लिए रखवाया था लेकिन वे मैथ्यू कमीशन की तैयारी में संस होने की वजह से आ नहीं सके । इसी प्रकार से सन 1948 से यहां पर सड्कों का भी एक स्कूल 8सी कक्षा तक का ही चला आ रहा है । वहां पर गांव वालों ने अब 16 कमरे बना दिए हैं । सरकार के नार्म्स के मुताबिक गांव वालों ने 16–16 कमरे बना कर दोनों स्कूलों की पूरी बिल्डिग तैयार कर दी है । इस– लिए अब मेरी आपके जरिए सरकार से प्रार्थना है कि उन दोनों स्कूलों को 10वीं ससी सैक का दर्जा दिया जाये । लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है । जब तक 'देहात की लड़कियां नहीं पढ़ेगी, तब तक कोई देश या प्रदेश तरक्की नहीं कर सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं ० 18 के बारे में बोलना चाहता हूं । इस डिमांड के बारे में सैनी साहब ने भी काफी विस्तार से विचार प्रकट किए हैं । मैं समझता हूं कि पशुओं के हस्पताल हर गांव में होने बहुत जरूरी है । आदमी जब बीमार होता है तो वह कार में या दूसरे साधनों के जरिए हस्पताल तक जा सकता है लेकिन पशुओं को नहीं ले जाया जा सकता । आजकल 10– 10 हजार रुपये की एक–एक भैस आती है । यदि वह बीमार हो जाए तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले

जाया जा सकता । मेरे गांव में एक डिस्पैन्सरी बनी हुई है । गांव वालों ने बहुत–सा पैसा लगा कर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग तैयार कर दी है । इसलिए अब मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर पशुओं के लिए एक पूरा हस्पताल बना दिया जाये क्योंकि गांव वालों ने अपनी तरफ से पैसा लगा कर पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । बह बात सही है कि हरियाणा का जो परिवहन विभाग है, वह सारे हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर है । यहां का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट पिछले तीन सालों से लगातार देश के दूसरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंटों के मुकाबले में प्रथमस्थान पर है । यह बहुत खुशी की बात है कि हम इस मामले में दूसरे प्रदेशों से आगे हैं । यहां पर सैनी साहब ने जिक्र किया हे कि सरकार कुछ नई बसें खरीदने जा रही है । दिनांक 23– 11–83 और 27– 10– 84 को मुख्य मन्त्री जी बरवाला में गए थे । उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि उकलाना और बरवाला दोनों जगहों पर बस–स्टैण्ड बना दिया जाएगा । ये दोनों कस्वे बहुत बड़े हैं । मुख्य मन्त्री जी वहां पर बस स्टैण्ड बनाये जाने का पत्थर भी रख कर आये थे । अब पता चला है कि उस बस स्टैण्ड के लिए सरकार ने पैसा भी अलाट कर दिया है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों जगहों पर बस स्टैण्ड जल्दी से जल्दी बना दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 24, जो टूरिज्म के बारे में है, कुछ कहना चाहूंगा । वैसे तो टूरिज्म डिपार्टमैंट ने काफी काम किया है । जब जी०टी० रोड पर देखते हैं तब पता चलता है कि टूरिज्म डिपार्टमैंट ने कितने ही कम्पलैक्स खोले हुए हैं । अभी पिछले दिनों टूरिज्म डिपार्टमैंट ने कैथल में भी एक नया कम्पलैक्स चालू कर दिया है । वहां पर इस कम्पलैक्स की बहुत आवश्यक्ता थी । उपा– ध्यक्ष महोदय, बरवाला बहुत बडा कस्बा है । इस कस्बे की आबादी 25 हजार है । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वहां पर मुख्य मन्त्री जी 2 3– 11–83 और 27–10–84 को गए थे । मुख्य मन्त्री जी के सामने लोगों की तरफ से मांग रखी गई थी कि बरवाला में एक टूरिज्म डिपार्टमैंट का कम्पलैक्स होना चाहिए क्योंकि जब हिसार से चण्डीगढ़ आते हैं तो बरवाला मेन रोड पर पड़ता है । उस समय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि यहां पर भी टूरिज्म कम्पलैक्स जल्दी से– जल्दी बुना दिया जायेगा । (.घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही खत्म कर देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात मैडिकल हैल्थ के बारे में कहना चाहूंगा । मेरा विचार है कि स्वास्थ्य सुधार बहुत जरूरी है । मैडिकल हैल्थ पर सरकार प्रति वर्ष काफी पैसा लगाती है । मैंने अपने गांव में एक डिस्पैसंरी बनवाई हुई है । उसकी काफी बडी बिल्डिंग है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि

उस डिस्पैन्सरी को प्राईमरी हैल्थ सैन्टर में कन्वर्ट कर दिया जाये क्योंकि कागजात सारे तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात डिमाड नं ० 16, जो श्रम तथा रोजगार से संबंधित है, कहना चाहूंगा । आज देश में बहुत बेरोजगारी फैली हुई है । आज देश के अन्दर बहुत से शिक्षित और ट्रेन्ड नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं । बरवाला एक बहुत बड़ा कस्बा है । मैं वहां पर श्री राजेश शर्मा जी को लेकर गया था । मैंने वताया था कि वहां पर कोई रोजगार का कार्यालय नहीं है । उस समय उन्होंने कहा था कि हफ्ते में दो दिन जा कर रोजगार विभाग के कर्मचारी वहां बच्चों के नाम दर्ज किया करेंगे । इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बरवाला कसे की जनसंख्या को देखते हुए और आसपास के एरिया को देखते हुए वहां पर फुल–फलैज्ड रोजगार कार्यालय बनाया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चौधरी अजमल खां (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहस, सप्लीमैंटरी बजट की जो मांगें हाउस के सामने रखी गई है उनकी संख्या 3, 4, 15, 18, 20 और 23 के बारे में मैं थोड़ा–थोडा कहना चाहूंगा । डिमांड 3 के संबंध में मैं यह कहूंगा कि यह सही है कि क्राइम्ज को रोकने में पुलिस का रिकार्ड बहुत ही अच्छा और शानदार है । हरियाणा में अमनो–अमान कायम रखने में भी इसकी शानदार कार– कदैगी है लेकिन देखने की बात यह है कि

क्या कारण हैं कि समाज का शरीफ तबका आज भी थानों में जाने से झिझकता है और डर महसूस करता है । इस बात की तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा कि क्या वजह है कि पुलिस थानों में जब सगलर्ज और दूसरे गलत काम करने वारसे लोग जाते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है लेकिन अच्छे लोगों की बेइज्जती की जाती है और वे वहां जाने से झिझकते हैं । शायद मेरे दोस्त इस बात को कहेंगे कि पुलिस की इतनी अच्छी कारकर्दगी होते हुए भी मैं नुक्ताचीनी कर रहा हूं लेकिन यह मेरा जाती तजुर्बा है । गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए भी कुछ पुलिस अफसरों के गलत रवैये के बारे में मैंने कहा था और आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं । 1982 में जब मैं हसीन हल्के से निर्वाचित होकर आया था तो मैंने अपने इलाके के लोगों से 5 आदमियों को'' रैड हैंडिड पकड़वाया था. और पुलिस के सुपुर्द किया था लेकिन उनकी खुशकिस्मती है और हमारी बदकिस्मती है कि वे सभी आदमी बहाल होकर अच्छी पोस्टों पर चले गए हैं । जब लोगों ने पुलिस की तवज्जुह इस तरफ दिलाई तो इससे पहले कि हम इस बात का इन्तजाम करं पाते, सारी बाते उन लोगों तक पहुंच गई । इन. बातों को ध्यान में रखते हुए लोग किसी को पकड़वाने से भी डरते हैं । हसीन हल्के में तो उल्टे उन आदमियों के खिलाफ, जिन्होंने उन लोगों को पकड़वाया था, केस रजिस्टर हुए. थे । इसलिए मेरा सुझाव है कि सी ० आई सी ०, ऐंटी करप्शन स्टाफ और विजिलैस स्टाफ को, पुलिस स्टाफ से अलग कर दिया जाए और इस स्टाफ में ईमानदार और अच्छे इन्सान रखे जाए ताकि वे

सही जानकारी सरकार को दे सके । डिप्टी स्पीकर साहब, औफिसर्ज की सौरी अपने तौर से काम करती है और बदले की भावना से काम किया जाता है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । मांग संख्या 4, जो रैवेन्यू डिपार्टमैंट के संबध में है, के ऊपर मैं यह सुझाव दूंगा कि गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में भी पटवार सर्कल 3 हजार एकड़ का कर दिया जाए क्योंकि बाकी सत्र जगह भी ऐसा कर दिया गया है । पटवारी के जिम्मे आज बहुत से काम है । उसे बिछल फुर्सत नहीं मिलती । पुराने जमाने की तरह अब उसके पास जामाबन्दी और रैवेन्यू का ही काम नहीं होता बल्कि उसकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गुडगांव और फरीदाबाद जिलो में भी पटवार सर्कल का रकबा 3 हजार एकड़ कर दिया जाए ।

डिमांड नं ० 15 इरीगेशन डिपार्टमैंट के बारे में है । आज इरीगेशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में बता सकता हूं कि जो काम हुए हैं वे केवल नाम के लिए हुए – हैं । जितनी भी नहरें या खाल खोदे गए उनको देख कर कोई नहीं कह सकता कि वहां कोई कामु हुआ । है । कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी डाल दी गई, कहीं कुछ और कर दिया गया । परिणाम यह हुआ कि लोगों को पानी नहीं मिल पाया । यही नहीं जितना लैवल निर्धारित किया गया था उतने तक भी काम नहीं हुआ । रिकार्ड पर तो उसे मुकम्मल कर दिया गया लेकिन जब नहर में पानी आया तो उसने बैडज के ऊपर से निकल

कर लोगों के खेतों को तबाह किया और अब भी कर रहा है । 14 दिसम्बर, 1985 को सुलतानपुर माजरा क्लैंजर के लोग डी ०सी ० के सामने पेश हुए और उन्होने शिकायत की कि हमारे गांव की फसल तबाह हो गई है । डी०सी ०, साहब ने एस ०डी ०ओ ० और तहसीलदार को आर्डर दिया कि इस बात की जांच की जाए । तहसीलदार और पटवारी ने 29 तारीख को जब देखा तो महसूस किया कि वाक्या ही लोगों के साथ ज्यादती हुई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी । 30 तारीख को इरीगेशन डिपार्टमैंट के आदमियों ने रैस्ट हाउस क्लैजंर में मीटिंग की और खुद जे ०ई ० ने रात को उसी जगह से पानी दुबारा कटवा दिया और कहा कि देखता हूं कि कौन शिकायत करता है । उल्टे लोगों के खिलाफ केस बनाए गए । डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह से किसानों के साथ ज्यादती होतीं है लेकिन खुशकिस्मती यह हुई कि तहसीलदार. एस ०डी ०ओ ० को रिपोर्ट दे चुका था कि किसानों के साथ ज्यादती हुई है क्योंकि 14 दिसम्बर से पहले इलाके में फ्लड आया हुआ था और छोटी फसलों को पानी देने की जरुरत नहीं थी । एस० डी०ओ ० और मेरे कहने से केस वापस लिए गए । इसी तरह की कहानी रीठट गांव के लोगों की है । उन्होने अफसरों से बार– बार दरख्वास्त की कि नहर के किनारे इतने नीचे है कि रजबाहों में पानी नहीं चल सकता और बैडज के ऊपर से पानी जाकर के उनके खेतों को नुकसान ‘ करता है लेकिन जब कोई ऐक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं नहर में रेत डालकर बांध लगाया ताकि पानी आगे न जाए और उनके खेतों में खड़ी फसल

को तबाह न करे । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जहां औफिसर्ज अलाइनमैंट से कम नहर को बनाते हैं और पैसे को वैसे ही बरबाद करते हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए और डिपार्टमैंट में नीचे से लेकर ऊपर तक जो अच्छे अफसर हैं उन्हें छांट कर विजिलैसं सैल में लगाया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तक से में अर्ज करूं कि गंगवानौ माईनर पर मिट्टी नहीं डाली गई थी । इसकी हमने इंक्वायरी करवाई थी । मौके पर तो लोगों को पता नहीं कि इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है लेकिन मुझे पता लगा है कि रिपोर्ट औफिसर्ज के हक में जा रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, जब तक हम यहां खुलकर बात नहीं करेंगे और गवर्नमैंट के नोटिस में नहीं लाएंगे तो औफिसर्ज इसी तरह से करोसे रुपया बरबाद करते रहेंगे और उनके हौसले बढ़ते न्हैगे और आज जो पैसा खर्च हो रहा है वह भी नहीं होगा । डिप्टी स्पीकर साहब, जितना पैसा इस डिपार्टमैंट का बरबाद होता है उतना किसी और डिपार्टमैंट का नहीं होता । लोग चाहे अपनी सरकार होने के नाते से यहां बातें न कहें लेकिन हकीकत से सौर नहीं किया जा सकता ।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब मैं ऐनीमल हसबैडरी की डिमांड नं० एस के बारे में अर्ज करूंगा । मेरे इलाके में ऐनिमल हंसबैडरी के बहुत थोड़े हस्पताल हैं । एक परेशानी यह है कि वहां डाक्टर नहीं जाते । अगर किसी –की ट्रांसफर करवाते

भी हैं तो वे वहां ठहरते नहीं । वे दुबारा ट्रांसफर करवा करके अम्बाला, रोहतक, जींद आदि के अपने इलाकों में आ जाते हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सोत एरिया के लोगों को ही नौकरी दी जाए । जब तक उस इलाके –के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, गुड़गांव जिले के लोग वहा नही रहेंगे तब तक हस्पताल खाली रहेंगे । अगर सरकार मुनासिब समझे तो मेरी रिक्वैस्ट यह है कि वहीं के लोग ट्रेन्ड करके वहाँ लगाए जाएं । वह फ्लड का इलाका है और वहां ज्यादा पशु मरते हैं । अगर ज्यादा न हो सकता हो तो कम से कम बुल अटैन्डैन्टस की नौकरी तो वहां के लोगों को दी जाए ताकि बच्चों को थोडा बहुत रोजगार मिल सके ।

डिमांड नं ० 20 फौरैस्ट डिपार्टमैंट की है । डिप्टी स्पीकर साहब, गुडगांव में फौरैस्ट का काफी काम हो रहा है लेकिन किसान लोग यह परेशानी महसूस कर रहे हैं कि उनके दरखतों को कोई लेने वाला नहीं है यानी किसानो के पास कोई आदमी लेने के लिए नहीं जाता है । मैंने इस बारे में गवर्नर एडैरस पर बोलते हुए भी कहा था कि जहां सरकार की ओर से इन्हें लगाने में मदद की जा रही है वहां इनके बिकवाने – की भी मदद की जाये । जो पौधे तैयार हो नये हैं, उनके खरीदने का सरकार को सही बन्दोबस्त करना कहिए ताकि किसानों का हौसला बुलन्द रहे ।

अब मैं आपके थ्रु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में –अर्ज करना चाहता हू । बसों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को काफी आमदनी हो रही है लेकिन अकसर जिन –बसो के टायर पुराने हो जाते हैं, और पैचंर हो कते हैं बसे रास्ते में खड़ी रहती हैं, जिसके कारण सरकार को कांफी नुक्सान होता है और सवारियों का भी टाईम जाया होता है । दूसरी बात मैं अपने हल्के फिरोजपुर झिरके के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । फिरोजपुर झिरके से चण्डीगढ़ के लिए कोई बस नहीं चलती, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हैडक्यार्टर तक बसें आती हैं । जब होडल से चण्डीगढ़ के लिए बस आ सकती है जो कि हरियाणा के लास्ट में पड़ता है और पलवल रूट पर पड़ता है तो फिरोजपुर झिरका से बस क्यों नहीं आती । फिरोजपुर झिरका अलवर रूट पर पड़ता है लेकिन वहां से चण्डीगढ़ के लिए कोई बस नहीं आती है । मेवात में बड़े–बड़े गांव हैं । वहां से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर या दिल्ली के लिए तो बस आती हैं लेकिन चण्डीगढ़ के लिए नहीं आती । डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के लिए भी बहुत कम बसे आती हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि हर तहसील और सब–डिवीजनल लैवल से रात के टाईम परं चण्डीगढ़ के लिए बस चलनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो । दूसरे हमारे इलाके में नयी बसें चलायी जायें क्योंकि पुरानी बसों के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इन शब्दों के साथ मैं इन सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स डिमान्डज का समर्थन करता हूं ।

मास्टर राम सिंह (एस०सी० रादौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत धन्यवादी हू कि आपने मुझे सप्लीमैंटरी डिमान्डज पर बोलने का समय दिया । मैं मांग नम्बर 1, 3, 4, 9, 15, 18 तथा 23 पर बोलना चाहता हूं । सब से पहले मैं मांग नम्बर एक जो विधान सभा के बारे में है और उसके खर्च के लिए 10,51,780 रुपया मांगा गया है, उसके विषय में अर्ज करना चाहता हूं । इस माग के लिये बहुत कम पैसे का प्रावधान किया गया है । एम०एल०एज० फ्लैट्स के लिए काफी फर्नीचर की आवश्यकता है । फ्लैट नम्बर 22 अलाट भी नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर फर्नीचर नहीं है । मेरी आपके जरिए रिक्वैस्ट है कि जहां फर्नीचर नहीं है वहां प्रोवाइड किया जाये और जिन फ्लैट्स पर नाजायज तौर पर कब्जा है, उनको छुड़ाया जाये ताकि जो एम०एल०एज० साहेबान रहना चाहें आसानी से रह सकें । एम०एल०एज० को जो भी सुविधायें मिलनी –हैं वे पूरी तरह से दी जायें । डिमान्ड नम्बर तीन होम डिपार्टमैंट के बारे में है । –जैसा कि नैन साहब ने भी कहा था कि एस०एच०ओ० तथा अन्य स्टाफ के लिए थाने के पास ही मकान बनाये जाये क्योंकि जब अमरजेन्सी के अन्दर –एस०एच०ओ० या अन्य स्टाफ की आवश्यकता हो जाती है तो थाने के पास मकान न होने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता हे । थाने के अन्दर रात के समय किसी भी वक्त केस आ सकता है । अगर एस०एच०ओ० का मकान थाने से दूर होता है तो उसे घर से बुलाया जाता है । घर थाने से दूर होता है इसलिए अमरजेन्सी के समय काफी दिक्कत होती है । मैं आपके

जरिए सरकार से डिमान्ड करूंगा कि एस०एच०ओ० तथा स्टाफ के रहने के लिए पुलिस स्टेशन के आसपास ही पुलिस कालोनी बनायी जाये ताकि अमरजेन्सी के समय फौरन कार्यवाही की जा सके ।

डिमांड नम्बर चार रैवेन्यू के बारे में है । डिप्टी स्पीकर साहब, रादौर में बीं०एडी० ओ ० ब्लाक के अन्दर एक छोटा सा कमरा ले कर सब–तहसील बना रखी है जिसके कारण स्टाफ को काफी दिक्कत का सामना करना ए रहा है । सब– तहसील के लिए जमीन एक्वायर कर ली गई है, कम्पनसेशन दे दिया गया है लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया । मैं निवेदन करूंगा कि फाईनैन्स डिपार्टमैंट की तरफ से पैसा दे दिया जाये ताकि बिल्डिंग बन सके और नायब तहसीलदार और दूसरा स्टाफ ठीक तरह से काम कर सके ।

डिमांड नम्बर नौ एजूकेशन के बारे में है । जै सा कि भाई साहब सिंह सैनी ने कहा था कि अध्यापकों ने हर विधायक के घर पर धरना दिया था और अपना मांग पत्र भी दिया था । उन्होंने अपने मांग पत्र में रिक्वैस्ट की थी कि हमें ग्रामीण सत्ता, मैडिकल अलाएन्स आदि की फैसेलिटीज दी जाये । उनकी मांगे बहुत जायज हैं, उन्हें मान कर उन्हें पूरी सुविधायें दी जायें जिससे वे अपने घरों से आराम से और निःसंकोच हो कर आये, जब उन्हें अपने परिवार की कोई चिन्ता नहीं होगी । तभी वे बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा सकेंगे । जितना अच्छा स्टैन्डर्ड

अध्यापकों का बनेगा, उतना ही अच्छा बच्चों का बनेगा । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अध्यापकों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये और जो उन्हें सुविधायें दी जा सकती हैं वे दी जायें । मांग नम्बर 15 इरीगेशन एण्ड पावर के बारे में है । मेरे हल्के रादौर में इतने ट्यूबवैल्ज हैं शायद हरियाणा में किसी स्री हल्के में न हों । लेकिन मेरे हल्के में बिजली पूरी नहीं जाती है । दूसरे वाटर लैवल भी नीचे चला गया है जिसके कारण पांच हार्स पावर की मोटर काम नहीं कर सकती । अगर वे साढ़े सात हार्स पावर की मोटर लगा लेते हैं तो बिजली वाले तंग करते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा बिजली दी जाये ताकि किसान अपनी मोटरें सलार सके । अगर मेरे हल्के में ज्यादा बिजली दी जायेगी तो उत्पादन और अधिक बढ़ेगा । मेरा हल्का काफी उपजाऊ है । वहां पर गेहूं, जीरी और गन्ना बेहद माता में पैदा होता है । जैसा कि आपको पता है, कुरुक्षेत्र जिला अन्न के उत्पादन में सब से आगे है और कुरुक्षेत्र जिले में मेरा हल्का सब से आगे है इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली और पानी का प्रावधान किया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जमुना हमारे यहां से बहती है । वह बरसात के दिनों में अपने किनारों के पास की जमीन को काट देती है । बहुत से गरीब किसानों की जमीन कट जाती है जिस से उन्हें काफी नुक्सान उठाना पड़ता है । मेरी प्रार्थना है कि जमुना के किनारे पर स्टैंड लगाये जायें और ये स्टैंड भी बरसात के आने से पहले लगाये लाये क्योंकि बहते हुए पानी में अगर स्टैड लगाये

जायेंगे तो पानी बहा ले जाता है इसलिए स्टैड बारिश के आने से पहले लगाये जायें ताकि जमीन कटने से बच सके । जमुना के किनारों पर हर साल चालीस पचास एकड़ जमीन कट जाती है । मैं इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करुंगा कि ये स्टैड बारिश होने से पहले लगाये जायें ताकि जमीन कटने से बच सके ।

मांग नम्बर 18 ऐनिमल हस्बैन्डरी के बारे में है । डिप्टी स्पीकर साहब मेरे हल्के में एक स्टौक असिस्टेन्ट को दस दस गांवों में जाना पड़ता है । एक आदमी इतनी दूर दूर नहीं जा सकता है । मुझे याद है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब एग्रीकलचर मिनिस्टर होते थे तो यह महकमा उनके पास था । उन्होंने उस टाईम पर अनाउन्समैंट की थी कि गमथला में हस्पताल होना चाहिए लेकिन वहां पर अब तक पशु हस्पताल भी नहीं बना । लोगों ने जमीन की रजिस्टरी सरकार के नाम करवा दी है और बिल्डिंग बनाने के लिये भी पैसा देने को तैयार हैं इसलिए वहां पर' जल्दी' से हस्पताल बनाया जाये । दूसरे वहां पर स्टाकमैन सैन्टर भी खोला जाये ताकि लोगों को लाभ पहुंच सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में अब मैं डिमान्ड नं ० 23 पर बोलना चाहता हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । यहां पर काफी जगहों परे सड़कें बन चुकी हैं, जैसे मुस्तफाबाद से बडतौली, लाडवा, खेड़ी, रामनगर, बहलोलपुर आदि । इन सड्कों

पर बसों की बहुत जरुरत है । इन सड्कों पर 15– 16 गांव आते हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इन सब' के लिये बस का कोई प्रावधान नहीं है । मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इन सड्कों पर जल्दी से जल्दी बस चलायी जाये जो मुस्तफाबाद से बडतौली वाया लाडवा पहुंचे और एक लाडवा से कुरुक्षेत्र के लिये एक सुबह और एक शाम को ' बस लगायी जाये । इससे लोगों को काफी सुविधा होगी । दूसरे मेरे यहां कुछ स्पाट्स ऐसे हैं जहां पर क्यू–शैल्टर्ज बनाने की काफी आवश्यकता है । मैंने मिनिस्टर साहब को लिखकर भी दिया था लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि जठलाना, गुमथला ईशर हेड़ी, भाटुवास, खेड़ी लखा सिंह, बबैन आदि ऐसे इलाके हैं जहां पर क्यू–शैल्टर्ज की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है । गांवों से वह जगह काफी दूर है जहां पर बस रुकती है । लोग गांवों से आकर बस की इन्तजार में बैठे जाते हैं । लोगों के लिए शैल्टर्ज न होने की वजह से काफी दिक्कत है । इससे वहां से लोगों को आमदनी भी होगी क्योंकि काफी लोग रेहड़ों और तांगों में आते हें । इससे एक तो लोगों को बैठने की सुविधा मिल जायेगी और दूसरे लोगों को फायदा व आराम मिल जायेगा । एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पर उस एरिया में सड़के तो तकरीबन सब जगह पर हैं लेकिन बारिश होने की वजह से वे टूटी हुई हैं और वे खस्ता हालत में हैं जैसे जमुना नगर से जखौली, गुमथला, गढ़ी बहावलपुर और करनाल । इन सड्कों की इतनी बुरी हालत है कि इनको ठीक कराना निहायत ही जरुरी है । अलोलपुर से हुडिया एक दीं किलोमीटर

का टोटा है । इस को बनाने से 15–20 किलोमीटर का सफर बच सकता है इसी प्रकार एक टुकड़ा मेहमदपुर से थुम्बड है । यह केवल डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा है । इसको बना देने से लोगों को 15– 16 किलोमीटर का सफर बच सकता है इनके अलावा एक अलाहर से जयपुर का टुकड़ा है । यह आग किलोमीटर दमा टुकड़ा है, इ सको बना देने से लोगों को 25–30 किलोमीटर का चक्कर काट कर जो आना जाना पड़ता है, वह बच सकता है । यह टुकड़ा तो सैक्शन भी हो चुका है । मैं राजेश जी को वहां पर ले कर भी गया था । इन्होंने अनाउन्समैंट भी की थी लेकिन अभी तक भी वहां पर कुछ नहीं हुआ है । यह सारे इन्टरडिस्ट्रक्ट लिंक्स हैं । यदिं मेरी इन डिमांड्ज को पूरा कर दिया जाये, सो मैं सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा । अन्त में मैं ' आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती शांति देवी (करनाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमैट्री डिमांड्ज यहां पर रखी गयी हैं, मैं उन पर अपने विचार रख रही हूं और अपने हल्के में जो कमियां हैं, उनके बारे में सरकार से निवेदन करुंगी । सबसे पहले मैं डिमांड नं ० 9 जो शिक्षा के बारे में है कुछ कहना चाहूंगी । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी इन्द्र सिंह नैन पदासीन हुए) यह तो सभी को मालूम है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिये वहुत जरुरी है । शारीरिक विकास, मानसिक और आत्मिक विकास के लिये शिक्षा बहुत जरुरी है और मनुष्य के

जीवन को यह परि– मार्जित और परिष्कृत करती है । इस तरफ हरियाणा सरकार का ध्यान तो बहुत है लेकिन मैं अपने हल्के में इस बारे में कुछ कमियों व त्रुटियों की ओर इनका ध्यान दिलानी चाहूंगी । प्राइमरी स्कूल मेरे यहां लगभग सभी किराये के मकानों में हैं और ज्यादातर गलियों में चारों तरफ से घिरे हुए मकानों में हैं । वहां पर न रोशनी का और न ही हवा का ठीक प्रबन्ध है । सरकार प्राइमरी स्कूलों में पैसे तो देती नहीं है इसलिये बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से वह जगह उपयुक्त नहीं है । बहुत पुराने भवन होने की वजह से वे बहुत ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं । बारिश के दिनों में और भी दिक्कत होती है । एक समस्या यह है कि स्कूलों में कमरे बहुत कम हैं । पिछले वर्ष मैंने शिक्षा मन्द्री जी को वहां पर एक स्कूल दिखलाया भी था । 4 कमरे और एक साईन्स रूम बनाने के लिये इन्होंने वायदा किया था क्योंकि वह स्कूल मिडल स्कूल करना है इसीलिए साईन्स रुम बनाने की इन्होंने इजाजत दे दी थी । वहां पर पहले तो चारदीवारी– भी नहीं थी । इसके न होने की वजह से कई बार पशु यानी सूअर वगैरा आ जाते थे और बच्चों को चोटें आदि भी लग जाती थीं, कुल 18,000 रुपये हमें मिला । इससे तो चारदीवारी ही बनी है । मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि जब चार कमरे और एक साईन्स रुम बनाने की इजाजत दी गयी थी, तो उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि बच्चों का पढ़ाई का उचित प्रबन्ध हो सके । इसी प्रकार से सैकण्डरी शिक्षा के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी । राम नगर और प्रेम नगर की जो बस्तियां हैं, वहां पर 1947 में जब

पुरुषार्थी पाकिस्तान बनने के बाद इधर आये, इन लोगों के लिए इनका निर्माण हुआ' था उसी समय बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेम नगर हाई स्कूल खुला था । स्कूल के क्लास रुम हट्स टाइप के बने थे । जमीन से कुछ ऊंचा उठा कर न बनाए जाने के कारण जब बारिश होती है तो उन हट्स के अन्दर पानी भर जाता है । अब वह हट्स खराब होकर टपकने लग गई हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से और खतरे की दृष्टि से वह स्कूल भवन उपयुक्त नहीं रहा है । 3 साल से मैं सुनती आ रही हूं– कि 20– 25 लाख रुपया इसके लिये मन्जूर हो जाता है लेकिन वहां पर अभी तक इस स्क्ल के भवन का निर्माण नहीं हुआ । मेरा नम्र निवेदन यह है कि अब की बार जो बजट आने वाला है, इस बजट में इस स्कूल बिल्डिंग के लिये पूरा रुपया दिया जाये ताकि करनाल के बच्चों को पढ़ाई करने के लिये उपयुक्त रयान' प्राप्त हो सके । इसी तरह से करनाल में कालेज के लिए भी कोई विशेष जगह नहीं है । अभी दो–चार साल पहले गवर्नमैंट कालेज बनाया गया है । वह कालेज एक' नौर्मल स्कूल की बिल्डिंग में बनाया गया है जहां पहले 10 वीं पास टीचर्ज को ट्रेनिंग दी जाती थी । मेरा कहने का मतलब यह है. कि कालेज के लिये जगह कम है । बच्चों की सुविधा के लिए अब अर्बन एस्टेट्स में हुड्डा ने कालेज के लिये नया स्थान निश्चित किया है । अभी तक चूंकि कालेज की बिल्डिंग नहीं बनाई गयी है इसलिये बार– बार नोटिस आ रहे हैं कि वहां पर बिल्डिंग बनाओ वरना हम उसे वापिस ले लेंगे और उसको कालेज के लिये नहीं रखेंगे । मेरा नम्र निवेदन यह है कि चूंकि वह एरिया बहुत

बढ़िया है, कालेज के लिये वह जमीन मिली भी हुई है इसलिये यदि अब उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो सरकार को बहुत हानि उठानी पड़ेगी । अगर अब वहां पर यह बिल्डिंग न बनाई – गयी तो फिर बाद में जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसा आपको खर्च करना पडेगा । इसलिये मेरा कहना यह है कि कम से कम बांसों गेट गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल प्रेम नगर और गवर्नमेंट कालेज तीनों की बिल्डिंगों के लिये तो पैसा इस बजट में रखा ही जाना चाहिये । बाकी प्राइमरी स्कूलों के पास तो जगह ही नहीं है । उनके बारे में तो मैं बाद में पता करूंगी कि वहां के लिये आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी या और कुछ हो सकता है लेकिन वहां पर आपको दूसरे प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्ज भी बनानी पड़ेगी । अब मैं डिमांड नं ०10 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूं । यह तो सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि मनुष्य जीवन के लिये स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है । हैल्थ इज वैल्थ । स्वास्थ्य ही मानव के लिये सब कुछ है । स्वास्थ्य के बिना तो जीवन पराधीन हो जाता है । शरीर को स्वस्थ रखने के लिये, इसे रोगों से बचाने के लिये मनुष्य का अपना कर्तव्य है कि वह खाना पीना, उठना बैठना, सोना–जागना वातावरण और अपने विचार व्यवहार ठीक रखे, इसके साथ ही साथ सरकार का भी फर्ज होता है कि यदि कोई दुर्भाग्यवश रोगी हो जाते हैं तो उसके रोग को दूर करने के लिए अस्पतालों का निर्माण करे । चेयरमैन साहब, करनाल का हस्पताल सौ साल पुराना है और किसी समय में वह बहुत बड़ा तथा बढ़िया अस्पताल होता था लेकिन सौ साल

में सारे तरीके बदल गए । वहां पर नालियां और लैटरीनज सब पुराने ढंग की हैं इसलिये उनका आधुनिकीकरण जरुरी है । नए अस्पताल के निर्माण के लिये मैंने मुख्य मच्छी जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने तीन साल पहले करनाल के अस्पताल का शिलान्यास किया था । पुराने अस्पताल में जमीन बहुत है लेकिन भवन जीर्ण–शीर्ण हो चुका है । उसी जगह पर दूसरा अस्पताल बनना है । कुछ पैसा दिया गया था जिससे डाक्टर वगैरह के रहने के लिए कुछ फलैट्स बने हैं अस्पताल का भवन बनना बहुत जरुरी है लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी काम शुरु नहीं हुआ है । जब लोग बार–बार मुझे अस्पताल निर्माण के बारे में कहते हैं तो मुझे बड़ी बेइज्जती लगती शै । कई बार इसी सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी की भी आलोचना हो जाती है जिससे मुझे बहुत कष्ट होता बै क्योंकि मैं चाहती हूं कि कोई उनके बारे में आलोचना न करे । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि करनाल का अस्पताल बढ़िया से बढ़िया ' बनाया जाए । हरियाणा के अन्दर हिसार का बस अड्डा भवन निर्माण की दृष्टि से फर्स्ट माना गया है और कहीं का अस्पताल फर्स्ट माना गया है । चेयरमैन साहब, करनाल का जिला हरियाणा के सभी जिलों में सब से अच्छा जिला है । वहां के लोग शान्तिप्रिय, नम्र और हिंसा आदि से दूर रहने वाले हैं । वहां पर हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी मिलकर रहते हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि वहां के अस्पताल की बिल्डिग ऐसी बढ़िया बनाई जाए कि जब कभी प्रतियोगिता रखी जाए तो करनाल का अस्पताल प्रथम आना चाहिए । मेरा यह भी निवेदन गै कि उस

अस्पताल के लिए पूरी राशि इस वर्ष के बजट में रखी जाए ताकि सारा अस्पताल एकदम तैयार हो जाए ।

12.00 बजे

चेयरमैन साहब, अगली 13 नम्बर डिमान्ड है । यह डिमान्ड समाज कल्याण तथा पुनर्वास से संबंधित है । हरियाणा सरकार बधाई की पास है कि उसने वृद्धा– वसा के असहाय लोगों, विधवाओं, असहाय बच्चों और विकलांगों की सहायता के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं तथा काफी धनराशि का प्रावधान किया है । चेयरमैन साहब, जब तक लोग काम कर सकते हैं, तब तक वे पैन्शन के लिए नहीं कहते लेकिन जब शरीर अस्वस्थ तथा निर्बल और काम करने के लायक नहीं रहता तब वे पैन्शन के लिए अपना फार्म भरते हैं । देखने में आया है कि फार्म भरने के बाद एक डेढ़ साल पैन्शन मिलने में लग जाता है । उस समय तक कई लोगों की मृत्यु हो जाती है । मेरा नम निवेदन है कि ऐसा तरीका अपनाया जाए कि फार्म भरने के तीन महीने बाद या छरू महीने बाद पैन्शन मिलने लग जाए । दूसरी बात यह है कि जिनको पैन्शन मिलती है उनको निरन्तर समय पर पैन्शन मिलनी चाहिए। तीन–तीन महीने की पैन्शन इक्ट्ठी भेजने का नियम है । लेकिन छरू छः महीने हो जाते हैं, उनको पैन्शन नहीं पहुंचती । लोग पैन्शन की इन्तजार करते रहते हैं । उनको लोग उधार देना पसन्द नहीं करते । दुकानदार समझते हैं कि बूढे हैं पता नहीं क्या हो जाए । मेरा नम निवेदन है कि ऐसे लोगों की

पैन्शन की तरफ सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए । पिछली बार मैंने कहा था कि स्टाफ की कमी है इसलिए स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । इन लोगों को यह आदेश दिया जाए कि समय पर काम होना चाहिए । चाहे कुछ ओवरटाईम देना पड़े या किसी और तरह से काम कराया जाए ताकि हर सूरत में असहाय लोगों को समय पर पैन्शन मिल जाए क्योंकि सरकार ने यह काम उनकी सुरक्षा तथा सहायता की दृष्टि से किया है, इस– लिए उनको मदद समय पर मिलनी चाहिए । जब आदमी को पैन्शन मिलने लग जाती है तो वह निश्चित हो जाता है कि पैसा मिलेगा तो वह जो काम पहले कर लेता था वह भी छोड़ देता है । इसलिए भी ऐसे असहाय लोगों को समय पर पैन्शन मिलनी चाहिए । मेरा नम्र निवेदन शै कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके समय पर लोगों को पैन्शन भिजवाने की कृपा करें । चेयरमैन साहब, मुझे इन तीन डिमान्डज पर ही विचार रखने थे, आशा है कि ये अवश्य पूरी की जाएंगी ।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहबाद) : चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं डिमान्ड नम्बर 3, 9, 8, 15, 13 और 24 पर अपने ख्यालात रखूंगा । चेयरमैन साहब, डिमान्ड नम्बर 3 के बारे में कई मैम्बर्ज बोले हैं । मैं यह कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि हरियाणा की पुलिस सारे भारत में पहले नम्बर पर है और उसकी जो उपलब्धियां हैं, वे

सब के सामने हैं । जब पंजाब जल रहा था उस समय थोड़ी सी आग भी हरियाणा में नहीं पहुंची । इसका श्रेय हरियाणा सरकार को और हरियाणा पुलिस को जाता है । मेरा कहना यह है कि, स्टाफ, रैजीडैंसं और जीपों आदि के बारे में इनकी जो भी डिमान्ड हो, वह पूरी की जाए । इनको इंसैन्टिंव दिया जाए जिससे पुलिस अधिक से अधिक सेवा कर सके । चेयरमैन साहब, फतेहबाद में पुलिस स्टेशन बिल्कुल शहर के अन्दर है । अरोड़ा साहब ने भी वह मौका देखा है । पुलिस को थोड़ी बहुत उन लोगों के साथ, जो गुण्डागर्दी करते हैं या औफेन्स करते हैं, सख्ती करनी पड़ती है । सेन्ट्रल प्लेस में पुलिस स्टेशन होना अच्छा नहीं लगता । सरकार ने नए पुलिस स्टेशन की स्कीम बनाई था, मेरी प्रार्थना है कि उसको जल्दी पूरा किया जाए । मेरी यह भी प्रार्थना है कि सरकार जितनी अच्छी स्कीम्ज बना सकती है वह बनाए जिससे कि जनता का भला हो । चेयरमैन साहब, दूसरी डिमान्ड 8 नम्बर है जोकि रोड्ज के बारे में है । इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा रोड्ज के मामले में सर्वप्रथम है लेकिन मेरी कास्टीचूऐंसी में कुछ रोड्ज ऐसी हैं जो कहीं आधा किलो– मीटर नहीं बनी और कहीं एक किलोमीटर बाकी रह गई है । तीन चार इस तरह की रोडज हैं जहां छोटे–छोटे टुकड़े बनने बाकी हैं और इन छोटे टुकड़ों के न बनने से उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता । मेरी प्रार्थना है कि पी ०डब्ल्यू ०डी ० मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान दें । चेयरमैन साहब, डिमान्ड नम्बर 9 ऐजुकेशन की है । भारत सरकार बड़ी दिलचस्पी से ऐजुकेशन के ढांचे को बदलने का – प्रोग्राम बना

रही है । इस काम के लिए कई कमेटीज बनाई गई हैं । स्टेट लैवल पर, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और सब–डिविजनल लैवल पर मीटिंग्स की गई हैं जिनमें बहुत सुझाव दिए गए हैं । चेयरमैन साहब, अडल्ट ऐजुकेशन के बारे में मैं यह –कहना –चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए और आठवीं क्लास पास बच्चियां अगर छठी क्लास को पढ़ाए तो अच्छा नहीं लगता । अडल्टस को पढ़ाने के लिए अच्छा स्टाफ रखना चाहिए । जब इसके लिए भारत सरकार से ग्रांट मिलती है तो हमारी सरकार को चाहिए कि वह अच्छा स्टाफ लगाए, टीचर्स अच्छे लगाए । अच्छे टीचर्ज लगाने से बहुत लाभ होगा । चेयरमैन साहब, सरकार से स्कूलों की मरम्मत आदि के लिए ग्रान्ट मिलती है । उसमें इंस्ट्रक्शंज यह हैं कि स्कूल की चारदीवारी, कमरा या छत पी० डब्ल्यू०डी ० द्वारा बनवाई जाए लेकिन पंचायत चाहती है कि यह धन उनको दिया जाए । वह उस ग्रांट में अधिक कमरे बना सकती हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कमरे या चारदीवारी आदि पंचायत बनाए, न कि पी ० डब्ल्यू ० डी ०। अगर पी ० डब्ल्यू ० डी ० वाले अपने नार्मज के अनुसार जितने पैसे में एक कमरा बनाती है तो पंचायत वाले सने अमाउंट में तीन कमरे बना सकते है । इस लिये सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ।

इससे अगली बात मैं सोशल वैलफेयर विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि यह विभाग समाज

सुधार का कार्य कर रहा है । इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है कि यह विभाग विकलांग, डैस्टीव्यूट्स, विडोज की मदद करता है लेकिन जितनी जल्दी इन गरीब लोगों को इस विभाग से मदद मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही है क्योंकि इनका पैन्शन सैंक्शन करने का जो लम्बा प्रोसीजर है, वह ठीक नहीं है । ऐसी लम्बी लम्बी फारमैलिटीज लोगों को पूरी करने में काफी समय लग जाता है । जैसे अभी बहन जी ने कहा कि डेढ़ दो साल तक लोगों को –इस विभाग की तरफ 'से इमदाद नहीं मिलती और उतनी देर में –वह व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद वह पै से उसके घर में पहुंचते हैं । इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इस लम्बी फारमैलिटीज के प्रोसीजर को ब्रीफ किया जाए चाहे, इस काम को निजी तौर पर करवाने के लिये पटवारी या सोशल वैलफेयर अफसर वगैरह की ड्यूटी लगवाई जाए ताकि 'यह सारा प्रोसीजरल कार्य जल्दी ही निपट सके और लोगों को जल्दी पैसे मिल सकें । चेयरमैन साहब, होता यह है कि जो बी ० डी ० ओज ० बैठे हुए हैं वे ब्लाक्स में बैठे–बैठे ही फामों में गलतियां निकाल –कर, आबजेक्शन लगाकर फार्मज नीचे भेज देते हैं । जिस तरह उनकी मर्जी में आया कर दिया । सिवाये इस काम के और उनका कोई काम नहीं – लेकिन विभाग को इस बारे में अपने प्रोसीजर को चेन्ज करना ही होगा जिससे गरीब लोगों को समय पर उचित मदद मिल सके । मेरे पास तो इस तरह की बीसों मिसालें हैं जिनमें फार्मज इतनी लम्बी–लम्बी कौरसपौन्डैन्स के बाद टुकड़े–टुकड़े हो जाते हैं जिस से लोगों को बड़ी दिक्कत का

सामना करना पड़ता है । इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि इस लम्बे प्रोसीजर को जितनी जल्दी हो सके, कुछ बीफ किया जाए ताकि लोगों को जल्दी ही पैसा मिल सके ।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं डिमांड नम्बर 15 जो इरीगेशन के बारे में है अर्ज करूंगा । इरीगेशन के लिये जो मेन आधार है, वह बिजली है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरियाणा सरकार ने बिजली उपलब्ध करने के लिये बेहद कोशिश की है इसके लिये हम सरकार के धन्यवादी हैं परन्तु सब–डिवीजन फतेहबाद के अन्दर इस बार बिजाई के वक्त बिजली का कुछ छोटा–छोटा सामान उपलब्ध न होने की वजह से किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा । चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि किसान हाथ पर हाथ रख कर तो बैठ नहीं सकते । अगर किसान के पास खेती के साधन न होंगे तो वह बेचारा कहां से खायेगा, कहां से अपने बाल बच्चों का गुजारा चलायेगा? कभी कनेक्शंज के लिये तार नहीं हैं तो कभी विभाग के पास कैडक्टर्ज नहीं हैं । इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार की तरफ से फतेहाबाद तहसील के अन्दर किसानों की दिक्कत को समझते हुए बिजली के छोटे मोटे सामान को पहुंचाया जाए जिससे वे अपने ट्यूबवैल्ल के जरिए अच्छी खेती बाड़ी कर सकें और जिन्स पैदा कर सकें । चेयरमैन साहब, हमारे यहां ट्रांसफार्मरज की भी बहुत कमरे है, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए । इनकी रिप्लेसमैन्ट की ओर भी कस तवज्जो दी जाए । इससे आगे मैं डिमांड नम्बर 24

पर अपने विचार रखना चाहता हूं । यह टूरिज्म से संबंधित है । इस में कोई सन्देह नहीं कि हरियाणा सरकार ने टूरिज्म में काफी नाम कमाया है । फतेहाबाद के अन्दर टूरिज्म काम्पलैक्स के लिये जमीन एक्वायर की गयी थी । उसके नजदीक लोगों ने प्लाट्स वगैरह भी खरीद रखे हैं । मार्किट वगैरह भी अच्छी बन सकती है । यह नैशनल हाईवे पर स्थित है लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही इस तरफ कोई ध्यान ही दिया जा रहा है । इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि इस काम को प्रायरिटी दी जाए । यह हल्का चीफ मिनिस्टर साहब का अपना है । वहां पर टूरिज्म काम्पलैक्स अवश्य बनाया जाए । इससे सरकार को काफी आम– दनी होगी और आने जाने वालों को भी सुविधा हो जाएगी और इलाके की डिवैल्प– मैंट भी हो जाएगी ।

चेयरमैन साहब, जहां तक हरियाणा ट्रांसपोर्ट का संबंध है, इस में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट आज सारे देश में नम्बर वन पर है । इस लिये इस संबंध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । इन शब्दों के साथ 'चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ओं अन्त में फिर मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि जो जो बातें मैंने यहां पर कहीं हैं, उन पर गौर करके उनको अवश्य ही पूरा किया जाए । धन्यवाद ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : चेयरमैन साहब, सब से पहले तो में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपुने मुझे बोलने

का .'सुअवसर प्रदान किया । मैं डिमांड 2 और ' 3 पर अपने– विचार सयुक्त रूप ' से रखना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों– ही मिलती जुलती डिमांडज हैं । एक सामान्य प्रशासन व दूसरी गृह. से संबंधित. है । चेयरमैन साहब, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन हर लिहाज 'से अच्छी चल रही है और इसकी जितनी तारीफ की जाए थोड़ी ' है । चेयरमैन साहब आप जानते हैं कि हमारा पड़ौसी राज्य आज बुरी तरह से जल रहा है और वहां की .....

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य ने बोलते हुए पड़ौसी राज्य के संबंध में जो कुछ कहा है इन बातों को कहने पर आनरेबल मैम्बर को रिस्ट्रेन किया जाए और मेरी रिकवैस्ट है कि यह शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाएं ।

श्री सभापति : ठीक है । जो कुछ आनरेबल मैम्बर ने पड़ौसी राज्य की सरकार के बारे में यहां हाउस में कहा है, वह रिकार्ड न किया जाए ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : चेयरमैन साहब, मैंने कोई दूसरी भावना से बात नहीं की थी । मेरा कहने का केवल यही अभिप्राय था कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारे राज्य का प्रशासन कितना शांतिपूर्वक चल रहा है । माननीय मन्त्री महोदय ने

उस पुर ऐतराज किया है, इसलिये मैं ऐसी बातें नहीं कहूंगा लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसा कि पुलिस का विभाग है, उसमें अभी और सुधार की आवश्यक्ता है । जैसा कि मेरे साथियों ने अभी बोलते हुए कहा कि इस विभाग की अपनी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी हरेक दिक्कत सरकार को जल्दी ही दूर करनी चाहिए । अब मैं डिमांड नम्बर 15, जोकि इरीगेशन से संबंधित है, पर कुछ कहना चाहूंगा । इस मांग से संबंधित अपने–अपने विचार व्यक्त करते हुए मेरे कई साथियों ने बताया कि इस डिपार्टमैंट में काफी काम हो रहो है । खालें, रजवाहे पक्के किये जा रहे हैं जिससे पानी की काफी बचत हो रही है । लेकिन अभी 'बहुत सारा काम बकाया है जिसकी ओर सरकार को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये । चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6.60 लाख फुट –एम ० आई ०टी० सी ० द्वारा खालें पक्की करने की वजह से पानी में बढ़ौत्तरी हुई है और काफी पानी की बचत हुई है । इसलिये मेरी सरकार से अपील है कि इस काम में जो कमियां रह गई हैं, जो खालें 1 रजवाहे पक्के होने शेष हैं, उनकी तरफ सासू तवज्जो दी जाए । चेयरमैन साहब, खालें पक्का करने के कारण किसानों से सरकार ने जो पैसा लेना था, वह सरकार को नहीं मिल रहा है, फिर भी सरकार किसानों की भलाई के लिये, किसानों की बहबूदी के लिये हर संभव पग उठा रही है । चेयरमैन साहब, 27 करोड़ रुपया हमने बैकों का भी देना है । इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि इस काम के लिये. बजट में और पैसे 'की प्रोवीजन की. जानी चाहिये

ताकि बैकों का पैसा जो हमने ले रखा है, उनको देते भी रहें औंर उन से पैसे लेकर आगे सरकार अपना काम काज भी । चढ़ाती रहे । इस तरह से यह लेन–बेन चलता रहने के लिये यह आवश्यक है कि इस बजट में और पैसे का प्रोवीजन. रखा जाए ।

चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में कुछ पुलों को बनायें जाने की भी डिमांड है जैसे कि मिट्ठा–थल फीडर है, उस पर पुल नहीं बना हुआ है । इसी तरह से दुई. कैनाल है, उसके ऊपर पुल नहीं है जिसके न होने के कारण किसानों को आने जाने में काफी असुविधा होती है । उनको दूसरी ओर अपने खेतों में जाने के लिये जी अति रोड का काफी लम्बा चक्कर काट कर जाना पड़ता है । इसी तरह से एक और पुल धमाना माईनर पर भी बनना रहता है । इसके लिये भी काफी दूर दूर से होकर आना जाना पड़ता है । यह छोटे छोटे पुलों की डिमांड है । मेरी वित्त – मंत्री व इरीगेशन मिनिस्टर महोदय से अपील है कि ये पुल जल्दी से जल्दी बनवा दिये जाएं ताकि किसानों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो । पेटवार कैनाल पर काम आरम्भ, हो गया है, इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । इससे लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी । यहां दोनों तरफ सड़क थी लेकिन नहर क्रौस करके 5 किलोमीटर जाकर फिर आना पड़ता था । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो–जो काम मैंने अपने हल्के के बताए हैं, उनकी तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए ।

चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में एक हाजमपुर रजवाहे की मांग की गयी है, उसको भी मुकम्मल करवाया जाए ।

इससे आगे मैं डिमांड नम्बर 8 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । चेयरमैन साहब, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं । मैं यह कहना चाहूगा कि जहां आज जगह–जगह हरियाणा के अन्दर सड्कों का जाल बिछा हुआ है वहां कई एक सड़कें अभी भी बनने वाली रहती हैं । इस में कोई शक नहीं कि हरियाणा का कोई भी बड़ा गांव सड़क से न जुड़ा हुआ हो, फिर भी जिन सड़कों का काम अभी होने वाला है या अधूरा है, वह मैं बता देता हूं । जैसे मैहदा से ढानी यहां पर बिछल सड़क नहीं है । ढानी कुमारां से ढानी पीरवाली । इसी तरह से एक सड़क मदनहेड़ी से सिंगबा जो तीन किलोमीटर लम्बी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई । इसके बाद मैं डिमांड नं० 9 जो एजुकेशन के बारे में है, पर आता हूं । कल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बताया था कि गांव गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन मैं उनका ध्यान इस 'ओर दिलाना चाहता हूं कि गांवों में जो प्राइमरी, स्कूल है, उनकी बिल्डिंगों की हालत ठीक नहीं है । हांसी में भी 3–4 प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत खराब है, जैसे सदर बाजार स्कूल, रामपुर स्कूल, ढाणी राजू और खड़खड़ा स्कूलों की बिल्डिंगें गिर चुकी हैं । इनको सब से पहले बनाया जाए ताकि जो बच्चे दूसरे गांवों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वे अपने गांव में ही शिक्षा प्राप्त कर सकें । गवर्नर एड्रैस में लड़कियों के स्कूल खोलने के बारे में

भी जिक्र आया था । मैं चाहूंगा कि मेरे हल्के में जहां–जहां डिमांड हो, वहां पर लड़कियों के स्कूल भी खोले जाए । मिडल स्कूल को हाई स्कूल किया जाए ताकि लडकियां अपने ही गांव में शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनको बाहर न जाना पडे ।

इसके साथ ही मैं डिमांड नं ० 13 जो सोशल वैलफेयर के बारे में है, पर बोलना चाहता हूं । अभी बहिन जो भी बता रही थीं कि पैन्शन के बारे में हरियाणा सरकार बहुत कोशिश कर रही है । जितने भी विकलांग, हैंडीकैप्ड या बूढ़े हैं उनको पैन्शन देने के लिये काफी प्रावधान किया गया है । चेयरमैन साहब, कुछ केसिज में ऐसी हालत है कि विकलांग को तो पैन्शन जल्दी मिल जाती है और जो बूढ़े है जिनका कोई सहारा नहीं होता उनको दो–तीन साल तक पैन्शन नहीं मिलती । कई केसिज में डैथ होने के बाद किसी की पैन्शन मन्जूर होती है । मैं चाहूंगा कि जैसे हम और कामों में काफी सुधार ला रहे हैं, उसी तरह इस काम में भी जितना हो सके, सुधार लाया जाए ताकि बूढ़े आदमियों को अपनी जिन्दगी बसर करने का अच्छा अवसर मिल सके । जिनकी औलाद नहीं है, जमीन नहीं है, खास कर हरिजन और बैकवर्ड सास के लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको प्रायरिटी देकर उनकी पैन्शन जल्दी मंजूर की जाए ताकि से ठीक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें ।

इसके साथ ही डिमांड नं ० 23 ट्रांसपोर्ट के बारे में है । काफी साथियों ने इस बारे में कहा है । हरियाणा रोडवेज सारे

देश में नाम पैदा कर रही है, अपने काम में भी और पैसेंजरों को आराम से ले जाने में भी । हमारी बसें सारी स्टेटों से अच्छी है । एक वक्त था जब लोग हरियाणा रोडवेज में सफर करना पसन्द नहीं करते थे लेकिन आज वही रोडवेज सब से अच्छी है । परिवहन मन्दी जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हिसार से हांसी तक की लोकल सर्विस है । हांसी से बच्चे हिसार कालेज में पढ्ने के लिए जाते है । बसों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और कई बार एक्सीडंट भी हो चुके हैं । मैं चाहूंगा कि उस रूट के लिए 3– 4 बसे और दे दें । इसी तरह से सीसर से हांसी के लिए भी काफी सवारियों का रश रहता है । बसों के न होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है । प्राइवेट लोगों ने छोटे छोटे फोर वीलर बना रखे हैं उनमें लोग सफर करते हैं । इसलिये लोगों की डिमांड को देखते हुए वहां बसें दी जाएं ताकि लोग आराम से सफर कर सकें । इससे सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी और प्राइवेट लोग जो टैम्पो वगैरह चला रहे हैं वह भी बन्द हो जाएंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ससे बोलने के लिए समय दिया ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी) : आदरणीय चेयरमैन साहब, टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद । सबसे पहले मैं सभी डिमांडज की तारीफ करता हूं । अब मैं डिमांड नं ० 3 के बारे में कहना चाहता हूं । यह होम के बारे में हैं । ला एंड आर्डर की हालत हरियाणा में सारे भारत से अच्छी है इसमें कोई शक

वाली बात नहीं है । आपस के तालमेल के लिए जो इन्तजाम की कमी है, वह पूरी कर लेनी चाहिए ताकि एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से जोड़ा जा सके । डिमांड 5 एक्साइज एंड टैक्सेशन की है ।

श्री सभापति : आप पहले सभी डिमांडज का नम्बर बता दें जिन पर आप बोलना चाहते हैं।

सेठ राम दास धमीजा : अब मैं डिमांडज 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18 और 23 पर बोलूगा । डिमांड नं ० 5 एक्साइज एंड टैक्सेशन की है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल की निस्बत इस साल टैक्सों से हमारी 110 करोड़ रुपए की आमदन बढ़ी है । मैं चाहता हूं कि टैक्सों का रेट सारे हिन्दुस्तान में एक जैसा होना चाहिए । अगर सारे. हिन्दुस्तान में एक जैसा रेट होगा तो टैक्स से आमदनी और बढ़ सकती है । चेयरमैन साहब, खास तौर पर दिल्ली में टैक्स का रेट बहुत कम है उस वजह से हमारी सरकार को नुकसान होता है । जितना टैक्स कम होगा उतनी आमदन बढ़ेगी और जितना टैक्स ज्यादा होगा उतनी उसकी चोरी होगी । इसके बाद मैं डिमांड नं० 8 जो विल्डिग्ज एण्ड रोडज की है, पर ' आता हूं । मैंने 18 तारीख को एक क्वैश्चन दिया था और उसके उत्तर में हमारे पी०डब्ल्यू ० डी० मन्त्री ने उस सड़क को फोर लेन की बजाए 30 फुट चौड़ा करने का वायदा किया है कि हम उसको 31 मार्च, 1987 से पहले बना देंगे । इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने वायदे को पूरा करेंगे । मैं तो यह चाहता हूं कि उस सड़क पर कोई हादसा न हो ।

इसके बाद डिमांड नं० 9 तालीम के बारे में है । हमारे यहां 12 सरकारी स्कूल हैं जिनमें से एक हाई, दो मिडल और बाकी प्राइमरी हैं । ये स्कूल 50–60 साल पुराने हैं । पिछले 40 साल से तो मैं इनकी तरफ देख रहा हूं इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया । वहां की आबादी डेढ़ लाख के करीब है । इन स्कूलों की छतें बैठने वाली हैं । हाई स्कूल की छत तो गिर भी चुकी है । इसलिये इनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए ताकि कोई बच्चा इनकी छत के नीचे आकर दब न जाए । मेरा एक सुझाव है कि तालीम का ढांचा बदल दिया जाए । हमारा जो सिलेबस है उसमें नैशनल, सोशल, धार्मिक, मिल्ट्री और आई०टी०आई० की तालीम होनी जरूरी है । आज कल बाबू तो पांच रुपए में मिल जाता है लेकिन मजदूर 25 रुपए में मिलता है । हमारी तालीम में तकनीकी तालीम बहुत कम है । जैसे मैंने अभी कहा कि बाबू तो पांच रुपए में मिल जाता है लेकिन लुहार नहीं मिलता । हमारे देश में नैशनल क्रैक्टर की कमी है । नैशनल क्रैक्टर स्कूल और कालेजों से बनता है । अगर हमारी तालीम का, ढांचा वही अग्रेजो, के वक्त वाला रहेगा तो हमे ऊपर नहीं उठ सकेंगे । नए स्कूल शहरों में खोलने के लिए तथा उनको अप– ग्रेड करने के, लिए कुछ नार्मज सरकार ने बना रखे हैं । उन नार्मज को शहरों के स्कूल, कभी पूरा नहीं कर पाते. । इसलिये असर नार्मज पूरे नहीं. होंगे तो स्कूल नहीं खुलेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि उन नार्मज में ढील देकर शहसे के स्कूलों को अप ग्रेड करना चाहिए । अगली डिमांड नम्बर 13 है जो सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट की है । यह

बात तो बहुत अच्छी है कि यह –डिपार्टमैंट अपंगों, विधवाओं और बूढो को पैंशन देता है लेकिन जो पैशन देने का सिस्टम है, वह ठीक नहीं है उनको पैशन, बहुत लेट मिलती है । जो बूढ़े लोग है वे 8– 8 महीने तक इन्तजार में रहते हैं लेकिन उनकी पैशन नहीं पहुंचती है । वे लोग हमें हर रोज आ कर पूछते हैं कि हमारी पैशन कब आएगी? इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनकी पैशन तीन –सहीने से ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए । पैंशन देने का जो सिस्टम है इसमें 15– 18 महीने लग जाते है । यह बहुत ज्यादा अर्सा है । इतना समय नहीं लगना चाहिए । ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में उनको पैशन दी जानी चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि पैशन के लिए जिसकी दरख्वास्त आती है उसको 6 महीने में पैशन दे देनी चाहिए 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि कोई बूढ़ा आदमी पैशन, की इन्तजार में आशा लगाते– लगासे मर जाए और. उसके मरने के बाद उसकी पैशन सैंक्शन हो । यदि मरने से पहले उसको पैशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा । खासतौर पर जो बूढ़े आदमी हैं उनको उनके बेटे नकारा समझते हैं, उनको कुछ नहीं देते है इसलिए वे पैशन पर निर्भर करते हैं । सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उनकी पैशन का इन्तजाम जल्दी हो ताकि उनको कोई दिक्कत न हो ।

अगली डिमांड नम्बर 14 है जोकि फूड एंड सप्लाईज के बारे में है । इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रोजमर्रा की चीजों

पर जितना कंट्रोल कम होगा लोगों को उतनी ही तकलीफ कम होगी । रोजमर्रा की चीजों पर कंट्रोल कम करके लोगों में चीजों की खुली तकसीम कर दी जाए तो उससे बहुत फायदा होगा । जैसे श्री किदवाई ने लोगों में रोजमर्रा. की चीजों की खुली तकसीम करने का तजुर्बा किया था और लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ था, उसी. तरह से वह तजूर्बा यहां पर किया जाए । उससे लोगों को बहुत फायदा होगा ।

अगली डिमांड नम्बर 15 है जोकि सिंचाई से संबंधित है । इस बारे में में कहना, चाहूंगा कि अम्बाला कैट में ड्रेनेज का – कोई इन्तजाम नहीं है । अम्बाला कैट में अंग्रेजों कें' जमाने में डिग्गिया बनी थीं जिनमें पीने की पानी भरा जाता था। वे डिग्गियां बहुत पुरानी' हो चुकी हैं और उनमें बरसात का पानी भर जाता है जिसको बाहर निकालसे के लिए कोई ड्रेन का 'इन्तजाम नहीं है । यदि बरसात अच्छी हो जाए तो मेरा शहर डूब जाने का खतरा हो जाता है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन का इन्तजाम किया जाए उस पर कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है। यदि 10–20 लाख रुपए लगा कर उस पानी को निकालने के लिए कोई ड्रेन बना दी जाए तो अम्बाला कैट फलड से बच सकता है । इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि धूलकोट बिजली का सब–स्टेशन है, और वह अम्बाला के पास है लेकिन अम्बाला को उससे बिजली नहीं मिलती । उस सब– स्टेशन से हर जगह बिजली मिलती है लेकिन

अम्बाला को नहीं मिलती । धूलकोट सब स्टेशन से कुरुक्षेत्र, जमूनानगर और नारायणगढ़ बिजली जाती है, लेकिन अम्बाला ' कैट में नहीं जाती । हम तो बराबर का. सलूक चाहते हैं, सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए । कम से कम बराबर का हक तो हमें मिलना चाहिए । अम्बाला कैट को बिजली न मिलने के कारण कारखाने वालों ने फरवरी के पहले हफ्ते में 3–4 बार जलूस निकाले । वह जलूस मेरा ही निकलता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए । अम्बाला में लगभग 7 हजार छोटे कारखाने लगे हुए हैं और सारे हरियाणा के कारखानों का जितना माल एक्सपोर्ट होता है, उसमें वन–थर्ड अम्बाला के कारखानों से एक्सपोर्ट होता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अम्बाला के कारखानों को बिजली देने का प्रबन्ध किया जाए ताकि उनका काम ठीक तरह से चल सके । अगली डिमांड नम्बर 18 है जोकि पशुपालन विभाग के बारे में है । मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि अम्बाला कैट की डेढ़ लाख की आबादी है लेकिन पशुओं के केवल दो ही अस्पताल हैं । सारे हरियाणा में पशुओं के 16०2 हस्पताल हैं उनमें से केवल 2 हस्पताल अम्बाला कैट में हैं । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अम्बाला कैट में पशुओं के ज्यादा हस्पताल खोले जाएं । अगली डिमांड नम्बर 23 है जो ट्रांसपोर्ट के बारे में है । यह बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश की बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट है और इसका सारे भारतवर्ष में बहुत नाम है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अम्बाला कैट का जो बस अड्डा है,

वह उस समय बना ' था जिस समय हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश इक्ट्ठे हुआ करते थे । उस समय से लेकर आज तक उस बस अड्डे की हालत वैसी की वैसी है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस बस अड्डे को बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हों । इन शब्दों के साथ मैं सभी डिमांडज का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : चेयरमैन साहब, जो अनुपूरक मांगें सदन के सामने प्रस्तुत हैं मैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इन डिमांड्ज में सभी बातें लोगों की भलाई को ध्यान में रख कर ही रखी गई हैं । मैं जिन, डिमांडज पर बोलना चाहूंगा, वे हैं डिमांड नम्बर 3, 4, 8, 9, 13, 15, 17 18, 19, 20, 23 और 25 चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 3 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में ला एंड आर्डर की अच्छी सिचुएशन होने का कारण पुलिस की एफि– शिएंसी है । पुलिस का नाम है, पुलिस की सेवा अच्छी रही है । चेयरमैन साहब, रोजमर्रा की जिन्दगी में लोगों का पुलिस वालों के साथ वास्ता पड़ता रहता है । कभी 107ध्51 के केसिज में, कभी भैस और गाय के केसिज में लोगों का पुलिस वालों के साथ वास्ता पड़ता रहता है और इन मामलों में लोग पुलिस वालों के पास जाते रहते हैं । जब लोग इन मामलों को ले कर पुलिस वालों के पास जाते है तो

पुलिस को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए । अगर कोई आदमी कायदे कानून की बात को लेकर पुलिस वालों का दरवाजा खटखटाए और पुलिस वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार करें तो लोगों की पुलिस के प्रति अच्छी भावना होगी । लेकिन पुलिस का जो सिस्टम है, वह पुरानी परम्पराओं पर चला आ रहा है इसलिए उसमें काफी सुधार करने की जरुरत है । इसलिए मैं सरकार से अनु– रोध करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे । इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 4 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । यह डिमांड रैवेन्यू से सबंधित है । मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि इस विभाग में पटवारियों की जहां कमी है वहां पर उनकी पूर्ति की जाए । पटवारियों के साथ लोगों को हर रोज काम पड़ता रहता है । आम तौर पर तहसील में उनका काम रहता है । कई लोगों का पटवारियों के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पटवारी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि हर जगह धांधलेबाजी है, हर आदमी करप्ट है, बहुत से लोग ईमानदार भी है । लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आनरेरी तहसीलदार का प्रावधान कर दिया जाए तो लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि जो छोटी–मोटी रजिस्ट्री वगैरह का काम है, उसको लोग देख सकते हैं । चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 8 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । मैं कहना चाहूंगा कि रोड्स बनाने का काम हरियाणा में हुआ है लेकिन कहीं–कहीं पर ऐसी सड़कें भी हैं, जिनका शहर या गांव के साथ सीधा लिंक नहीं है । जैसे मेरे हल्के में एक जलबेड़ा

गांव है । यदि उस गांव से अम्बाला कैंट जाना हो तो पहले अम्बाला शहर जाना पड़ेगा, उसके बाद अम्बाला कैट जा सकते है । इसी तरह से एम्बो और सुधरा गांव है । यदि इन गांवों से अम्बाला कैंट जाना हो तो पहले हिसार रोड पर जाना पड़ेगा, उसके बाद अम्बाला कैट जा सकते है या अम्बाला शहर हो कर जा ' सकते हैं । इस किस्म के रोड्स हैं । ऐसे रोड्स चाहे कहीं पर भी हों, ऐसे रोड्स को बनाने की तरफ प्रायरिटी दी जानी चाहिए ताकि लोगों को एक दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा चक्कर न लगाना पड़े । इसी तरह से कई ऐसे गांव हैं जहां पर पुल बनाने बहुत ही जरूरी हैं । जब बरसात होती है तो उन गांवों का शहरों से लिंक टूट जाता है । मेरे हल्के में ब्राह्मण माजरा, समालखा और खरोली गांव– हैं और इस किस्म के गांव और भी हो सकते हैं, उन गांवों के पास पुल बनाने बहुत ही जरूरी हैं । इसी तरह से. यदि मोहड़ा गांव के पास रेलवे ब्रिज बना दिया जाए तो कम से कम 150 गांवों को फायदा होगा, ' क्योंकि उन. गांवों वालों को शाहबाद शुगर मिल में गन्ना लाने के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी ।. मैंने उस रेलवे ब्रिज के बारे में मन्दी जी से डिस्कशन की थी, मन्त्री जी कहने लगे कि अभी बहुत– ब्रिज बनने हैं, इस बारे में भी देख लेंगे । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस पुल को भी बनाया जाए ।

चेयरमैन साहब, अब– मैं. डिमांड नम्बर 9 जो एजुकेशन के बारे में है बोलना चाहूंगा । आज के दिन कहीं–कहीं पर. स्कूल

की बिल्डिंगों और टीचर्ज का काफी अभाव है । मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । मेरे हल्के में एक बहुत बड़ा गांव बबियाल है । उस गांव के काफी लोग नौकरी–पेशे में. हैं । गांव की आबादी भी 10 हजार' के आसपास है । इस गांव में लड़के और लड़कियां के दो स्कूल हैं लेकिन दोनों स्कूलों की बिल्डिगों की बहुत –खस्ता हालत है । इन की बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जो कोई भी देखेगा वह यही कहेगा कि इन स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं सकते । इस बारे. में मेरा सरकार को सुझाव है कि ऐसे स्कूलों को पैसा देकर उनकी बिल्डिंगों को ठीक कराया जाये, और शिक्षा का जो मसला है उसको सुधारा जाये । प्रत्येक बच्चे की जिन्दगी शिक्षा से जुड़ी हुई है । इसलिए स्कूलों में अच्छे टीचर्ज और – शिक्षित टीचर्ज होने चाहिएं । आज के जमाने में बच्चों पर किताबों का बोझ बहुत लाद दिया मया है । मैं समझता हूं कि शिक्षा में विशेष सुधार की आवश्यकता है । इस. बारे में सरकार ने शिक्षा नीति को चेन्ज करने का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है । सरकार ' की बहुत अच्छी स्कीम है कि लड़कियों को फी शिक्षा दी जायेगी ।

अब मैं डिमांड नम्बर, 13 जो समाज कल्याण के बारे में है, पर – बोलना चाहूंगा । सरकार का यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो बृद्ध लोग, विधवा औरतें, डाइबोर्स्ड लड़कियां और गरीब लोग हैं, उनकी पैन्शन के रूप में या दूसरे तरीके से सरकार सहायता कर रही है । लेकिन इसमें एक बात देखने में आई है कि

पैन्शन – तो देनी होती है 500 को, लेकिन एप्लीकेशन्ज मंगवा ली जाती हैं 4000 के करीब । इससे लोगों को फायदा नहीं होता । कई तो बेचारे पैन्शन के – चक्कर में भगवान को प्यारे हो जाते हैं । जितने लोगों को पैन्शन दी 'जानी हो उतनी ही एप्लीकेशन लोगों से लें । मान लो 100 लोगों को पैन्शन देनी है तो ज्यादा से ज्यादा 125 या 150 एप्लीकेशंज ले ली जाये । एप्लीकेशन तो ले लेते हैं 1000 की और पैशन देते हैं 100 आदमियों को । इस तरह 900 आदमी बेचारे इन्तजार करते रहते हैं । जब एप्लीकेशन्ज ज्यादा आती हैं तो उन बेचारों को इन्तजार करवाने की बजाये कह दें कि पैसा नहीं है, इसलिए आपको पैन्शन अब नहीं मिल सकती । इसके साथ–साथ जो सरसि आदमी पैन्शन के लिए दरखास्तें देता है, वह भी कई बार कहीं रास्ते में रुक जाती हैं । इन एप्लीकैशन्ज की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । इसलिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों और सरकार के बीच में कोई दरखास्त न रुके और कोई घपलेबाजी या ऐप्लीकेशन की मिसप्लेसमेट न हो । इस स्कीम के बारे में ' 'मुर्दे के मुंह में पानी डालने वाली' ' कहावत लागू होती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पैन्शन की सुविधा लोगों को दी जा रही है, उसे ठीक– तरह से दिया जाये । (इस समय, श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 15, जो सिंचाई से ताल्लुक रखती है, उस पर बोलना चाहूंगा । हमारी सरकार के सिंचाई मन्त्री एक योग्य मन्त्री हैं । सरकार एस०वाई०एल ० से या

दूसरे सोर्सिज से जो पानी का बन्दोबस्त कर सकती है, वह कर रही है । अम्बाला जिले में भी सिंचाई की कई स्कीमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । मैं सरकार से यही दरखास्त करूंगा कि जिन स्कीमों को अन्तिम रूप दिया जा सु का है उनको जल्दी से जल्दी. पूरा किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 17, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । स्पीकर साहब, सरकार ने किसानों की खाद के मामले में या बीज के मामते में काफी ईमदाद की है लेकिन आज के दिन किसानों को बिजली और पानी के लिए तडफना पड रहा है । इस संबध में मेरा सरकार को सुझाव है कि जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, उस में वह 3– 4 एकड़ में प्लांट लगवाये और इस में प्लांट लगाने में जो खर्च आए उसको सरकार वहन करे । जब तक वे प्लांट तैयार न हो जाएं तब तक जो भी खर्चा किसान को आए, सरकार उनको वह खर्चा दे । जब प्लांट तैयार हो जाएं तो सरकार बेशक अपना पैसा किसान से सूद समेत वापिस ले ले । ऐसा होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्लांटस भी अधिक से अधिक लग सकेंगे । वैसे इस मामले में लैण्ड मौर्गेज बैंक किसानों की सहायता कर रहा है । लेकिन यह सहायता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए । मैं चाहूंगा कि किसानों को जो सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, उसको बढ़ाया जाये । आज के दिन हिन्दुस्तान के अन्दर अनाज की कोई कमी नहीं है । कई

बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अनाज को स्टोर करने की जगह भी हमारे पास नहीं होती । अगर सरकार किसानों को पेड–पौधे लगाने में सहायता करें तो किसान इसमें बढ़चढ़ कर भाग लेंगे । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 18, जो पशुपालन से संबंधित है, पर बोलना चाहता हूं सरकार ने पशु हस्पताल और डिस्पैन्सरिया काफी खोली हुई हैं । कई जगहों पर पहले तो सरकार ने पशुओं के लिए डिस्पैन्सरियां आदि खोल दी लेकिन बाद में बन्द कर दीं । ऐसा मेरे हल्के के दो गांव बिन्जोला और माजरी में हुआ । पहले सरकार ने डिस्पैन्सरी खोल दी लेकिन बाद में बन्द कर दी । इतना ही नहीं, सरकार ने इस काम के लिए बिल्डिग भी बना दी थी लेकिन फिर भी वे डिस्पैन्सरियां बन्द कर दीं । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जहां पर एक बार डिस्पैन्सरी खोल दी उसे बन्द नहीं किया जाना चाहिए और अगर कहीं बन्द कर दी हैं तो ऐसी डिस्पैन्सरियों को दुबारा चालू किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि खोली हुई डिस्पैन्सरी को बन्द करना एक बहुत बु री बात है । सरकार अच्छे नसल के सांडों और झोटों का सीमैन तो इक्ट्ठा करती ही हे लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव और है कि हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अच्छी नस्ल के घोड़े और गधे रखे जाने चाहिए ताकि लोग अच्छी नस्ल के धोड़े–घोडिया और गधे पाल सके । (हंसी)

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, श्री निर्मल सिंह की गधे की बात पर हंसते तो हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी आमदनी किसी को गधों से हो सकती है उससे ज्यादा किसी और पशु से नहीं हो सकती। (हंसी)

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 19, जो मछली पालन से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा । मछली पालन के बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि किसानों को टी ०वी ० के जरिए या दूसरे तरीकों से बताया जाना चाहिए ताकि किसान अधिक से अधिक मछली पालने का काम कर सकें । मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को मछली के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 19, जो वनों से संबंधित है, पर कुछ कहना चाहूंगा । आज वन विभाग द्वारा बड़ी तादाद में वन लगाये जा रहे हैं । जहां पर वनों को काट दिया गया था, आज महसूस किया जा रहा है कि ये वन गलती से काट. दिए गए थे । मैं चाहूंगा कि फौरेस्ट डिपार्टमैंट को फौरेस्ट लगाने में किसानों को ठीक सलाह देनी चाहिए और उनकी जमीन में अधिक से अधिक पेड–पौधे लगाने में उनकी सहायता करनी चाहिए । वन विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वे किसानों से मिलें और उनको लोन आदि देकर उनसे अधिक से अधिक पेड़–पौधे लगवायें । बाद में बेशक वन विभाग अपना लोन किसानों से वापिस ले ले ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 23, जो परिवहन से संबंधित है, पर कुछ कहना चाहूंगा । आज के दिन हरियाणा की परिवहन लोगों की बहुत अच्छी सेवा कर रही है लेकिन कई बार देखा गया है कि बसों में जो चालक और परिचालक देते हैं, वे ठीक ढंग से बात नहीं करते । दूसरे मायनों में देखा जाये तो परिवहन सरकार का एक बिजनैस का साधन है । जिस प्र कार प्राईवेट लोग अपने बिजनैस को चलाने के लिए लोगों से अच्छे ढंग सें पेश आते हैं, मीठा बोलते है उसी प्रकार परिवहन विभाग के ड्राईवरों और कन्डक्टरों को भी मीठा बोलना चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो । एक बात आम देखने में आई है कि जी० टी ० रोड पर जो बसें चलती हैं, उनके बस चालक और परिचालक, सड्कों पर जो ढाबे जगह – जगह बने हुए हैं, उन पर अपनी बसें रोक लेते हैं, और खाने के नाम पर सवारियों को लुटवासे है । मेरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब? को सुझाव है कि परि– वहन विभाग को, जहां जहां पर बसें रुकती हों, वहां पर अपनी दुकानें खोल कर चलानी' चाहिए ताकि लोगों को ठीक रेट, पर अच्छी चीजें मिल सकें ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग सख्या 25 पर बोलना चाहूंगा । यह मांग लोनज एण्ड एडवासिज बाई स्टेट गवर्नमैंन्ट के बारे मे है । को–आप्रेटिव बैक और लैड मौर्गेजं बैंक द्वारा किसानों को कर्जा दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि यह लोन साफ कर देना चाहिए । मैं समझता हूं कि लोन साफ करने में बहुत

दिक्कत है और यह लोन साफ हो भी नहीं सकते । बैंकों से पैसा लेकर के लोग अपना कारोबार करते हैं । अगर वे किसी वजह से समय से पैसा न लौटा पाएं तो उनसे कानूनी तरीके से पैसा वसूल किया जाना चाहिए 1 स्टेट बैंक के पैसे को अगर कोई नहीं लौटा पाता तो वे कोर्ट के द्वारा उससे पैसा वसूल करते हैं । वे कोआप्रेटिव बैक या लैंड मोर्गेज बैक की तरह किसी किसान के बीबी बच्चों को–. तक नहीं करते या किसान को बिना नोटिस दिए हवालात में बन्द नहीं करवाते । लोगों से इस तरह पैसा लेने का यह तरीका गलत है । होना यह चाहिए कि जब कोई कोआप्रेटिव बैंक या लैड मौन से बैक से कर्जा ले ले. तो उसके 6 महीने के –बाद चौक किया जाना चाहिए. कि आया वह किस दे रहा है या नहीं । अग र नहीं दे रहा हो तो उसे किस देने के लिए ' कहा जाए । हो सकता है किसान 'उसे समय पैसा देने की पोजीशन में हो । लेकिन दु:ख की बात यह है कि उसे, सौ अढ़ाई. साल तक पूछा नहीं जाता । तब तक वह कर्से में 'दस जाता ' है और एकदम पैसा लौटा नहीं सकता । क्यों नहीं समय से चौक किया जाता? इसका कारण ' यह है ओक बीच के अधिकारी लौग किसान से पैसा लेते हैं । जब ' किसान उनके हाथ में 50 रुपये रखता है तो 6 महीने आगे की तारीख दे दी जाती है। इस बात को सीरियसली लेना चाहिए । आप उससे उस वक्त कर्जा वापस लें जब. वह' कर्जा देने की पोजीशन में हो । स्पीकर साहब, कर्जा देने का तरीका' भी बड़ा पेचीदा ' है । किसान साधारण होता है और गु सराह हो जाता है । उसे कर्से की रकम भी कम दी जाती

है । स्पीकर सास,, मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमैट की सीस बहुत अच्छी हैं । इतनी ज्यादा आबादी, इतनी अधिक समस्याओं के बस सूद भी यह लोगों की भलाई के बारे में सोचती है लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें ब्यूरोक्रेसी कहें या कुछ और कहे, जो लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचने नहीं देते । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बात को चौक किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमैंटरी बजट का समर्थन करता हूं ।

वित्त मुन्त्री (श्री सागर राम गुप्ता) : स्पीकर साहब, वर्ष 1985– 86 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस की दूसरी किस्त पर आज हाउस में बहस हुई । बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव दिए हैं । मैं सरकार की तरफ से उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने रचनात्मक तरीके से इन डिमांडज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । साथ ही साथ मुझे खेद भी बड़ा भारी है क्योंकि विपक्ष के भाई इस हाउस. में नहीं हैं । अगर वे यहां– होते और इन डिमांडज के ऊपर अपनी बातें कहते, कुछ अपने इलाके की जरूरियात के बारे में रोशनी डालते तो मैं समझता कि जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा हुआ है उनके प्रति वे अपनी जिम्मेदारी और वफादारी निभा पाते । उनके इस – हाउस में न आने से यह साफ बात लोगों के सामने आई है कि वे साहेबान जिन लोगों के द्वारा चुने गए, हैं उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे हैं और जैसा यहां जिक्र आया था वे केवल कुर्सी पाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं

लेकिन कुर्सी मेरे ख्याल में इस जिन्दगी में तौ उन्हें मिलती नहीं आगे की जिन्दगी के बारे में भगवान जाने । स्पीकर साहब, ज्यादा अच्छा होता अगर वे यहां आकर इन–– डिमांडज के बारे में बातें करते, अपने हल्के की जरूरियात के बारे में बातें करते ताकि उन लोगों की भी सेवा कर पाते जिन्होंने विपक्ष के भाइयों को चुनकर भेजा स्पीकर साहब, मैं सदन को' यह' बताना' चाहता हूं कि कुल ' रकम' जो इन ऐस्टीमेटर्स के द्वारा मानी गई 'है वह 88.77 करोड़ रुपये की है जो पिछले साले के मुकाबले में काफी कम है । इसके अलावा मैं सदने को यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह न समझें कि ' बजट पास होने के बाद और सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस की 'पहली किस्त पास होने के बाद यह ' छ 8. 77 करोड़ रुपया. सरकार ' के खजांने? से निकलेगा ही । वास्तव में ऐसी बात नहीं है । इसमें से बहुत बड़ा भागे यानी' 35.50 करोड़ रुपया कैवल ' ऐडजस्टमैंट ऐन्ट्रीज ' से पूरा हो जाएगा और केवल 53.27 करोड़ रूपये की हमें जरूरत होगी । यह भी जरुरी नहीं है कि' यह सारा रुपया भी. सरकार के खजाने में से निकलेगा । स्पीकर साहब, साल के अन्त में बहुत. से विभाग कुछ पैसा सरन्डर करते हैं । कई विभाग किन्हीं– कारणों से उनके डिपार्टमैंट का साल का जो बजट बनता है उसे पूरा खर्च –नहीं कर पातेरू बल्कि कुछ पैसा बजटिड अमाउट में से वापस कर देते हैं जिसको सरन्डर कहते– हैं । कहने का मतलब यह है कि कुछ रुपया बतौर सरन्डर हमारे पास आएगा और 31 मार्च चक वह भी ऐडजेस्ट हो जाएगा । इस तरीके से मेरा अन्दाजा' यह ' है कि इन ऐस्टीमेटस

के द्वारा. जो सरकार का पैसा निकलेगा वह शायद 40–41 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो ।

स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले कहा मैं उन माननीय सदस्यों को बहुत आभारी हूं जिन्होंने बोलते हुए बहुत ही कीमती सुझाव दिए हैं । मैं इस बात के लिए भी उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमारे बहुत से डिपार्टमैट्स की वर्किन्ग के बारे में बहुत ही अच्छे रिमार्कस हाउस में पास किए हैं । मिसाल के तौर पर तकरीबन सभी ने हमारे पुलिस डिपार्टमैंट की बहुत तारीफ की । स्पीकर साहब, आप भी महसूस करेंगे कि ला एंड आर्डर की जो सिचुएशन हमारे प्रान्त में रही है वह वाक्या ही काबिले तारीफ है । सरकार को भी इस पर गर्व है और' हरियाणा की जनता को भी गर्व होना चाहिए । डिसिप्लिन, सूझबूझ और मेहनत के लिहाज से निश्चित तौर पर हमारा पुलिस डिपार्टमैंट तारीफ के काबिल है । कुछ माननीय. सदस्यों ने यह जिक्र किया कि पुलिस के व्यवहार में कुछ सुधार होना चाहिए । हमारे एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि पुलिस स्टेशन्ज पर जाते हुए आज भी कुछ आदमी घबराते हैं । यह बात ठीक हो सकती है कि कहीं पुलिस स्टेशन्ज के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का व्यवहार उतना अच्छा न हो जितना जनता उम्मीद करती है । इसके बारे में सरकार की तरफ से मेरा यह कहना है कि सरकार इस मसले के बारे में पूरी तरह सजग है और मैं इस सदन के द्वारा हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक हमारी पुलिस के व्यवहार का

ताल्लुक है उसमें पहले से काफी सुधार आया है और निरन्तर हम इस बात की कोशिश में हैं कि हमारे पुलिस औफिसर्ज जनता के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें । जब भी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आकर किसी बात की शिकायत करे उसकी शिकायत को पूरे तौर पर सुना जाए और कानून के मुताबिक उस पर कार्यवाही की जाए लेकिन स्पीकर साहब, कई बार मौका ऐसा आ जाता है कि ला एंड आर्डर मेनटेन करने के लिए पुलिस को ऐसी कार्यवाही करनी पड़ती है जिसे लोग उचित नहीं समझते । उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं कि पिछली 23 जनवरी को अपोजिशन के भाइयों ने रास्ता रोको आन्दोलन किया । आप खुद इस बात का अहसास करेंगे कि हमारी पुलिस ने शान्ति, तसल्ली और सब्र से काम लिया लेकिन जिन भाइयों ने जहां कहीं पर तसद्दुद का रास्ता अपनाया, पुलिस पर पत्थर फैके, पुलिस के साथ मारपीट की वहां पर पुलिस ने सैल्फ डिफेंस में ऐक्शन लिया । देश के अन्दर आज के दिन दो तीन स्टेट्स की बदकिस्मती है कि विपक्ष वाले भाई पुलिस की नुक्ताचीनी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए । आखिर पुलिस का फर्ज था कि वह ला एन्ड आर्डर मेनटेन करे । अगर कुछ सिरफिरे लोगों ने एजीटेशन का बहाना ले कर पुलिस को मार–पीटने, की बात की है या कुछ अन्य लोगों को जो एजीटेशन में शामिल नहीं थे, उनके साथ मारपीट की है तो पुलिस को बीच में आना ही पड़ेगा । मैं कह सकता हूं कि तकरीबन हमारी पुलिस का व्यवहार और काम करने का तरीका काफी ठीक है । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि हमारी स्टेट में बहुत सी स्टेट्स के

मुकाबले में पुलिस का व्यवहार बहुत ही अच्छा है । मैं पडोसी स्टेट का जिक्र नहीं करना चाहता । वहां के बारे में हम खुद अहसास कर सकते हैं कि उसके मुकाबले में हमारी पुलिस फोर्स कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है ।

13. ०० बजे

एक माननीय सदस्य श्री नैन जी ने सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन के पास वीहकल्ज जरूर होनी चाहिए । मैं सदन की सूचना के लिए और खासतौर पर नैन साहब की सूचना के लिए यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस मामले में पूरी तरह जागरुक है और मैं समझता हूं कि पुलिस के पास हरियाणा में सब से ज्यादा बैस्ट फलीट वीहकल्ज का है । मैं तो यह भी कहूंगा कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हमारी स्टेट में पुलिस के पास वीहकल्ज का अच्छा प्रबन्ध है । यह बात ठीक है कि उस फलीट के इस्तेमाल में कुछ रेशनेलाइजेशन या कुछ बैटरमैंट की जा सकती है और उसकी तरफ सरकार जरूर ध्यान देगी लेकिन पुलिस की वीहकल्ज की स्थिति बहुत अच्छी है और सन 198 5–86 गे फास्ट मूविंग वीहकल्ज भी प्रोवाइड किए हैं । स्पीकर साहब, आपने भी जी ०टी ० रोड पर देखा होगा, कितनी पुलिस पोस्टस कायम कर दी गई हैं जिनके पास एम्बूलैसं भी है, फास्ट मूविंग मोटर साईकिल तथा जीप्स भी हैं और उसके साथ साथ एक्सीडेंटल वीहकल्ज को उठाने के लिए क्रेन्ज भी है । तकरीबन तकरीबन हर पुलिस स्टेशन के पास वीह– कल्ज हैं । जैसा मैंने

कहा कि हो सकता है उनके रेशनेलाइजेशन में और डिप्लाएमेंट में कमी हो सकती है । अगर नैन साहब किसी खास पुलिस स्टेशन का नाम नोटिस में लायेंगे तो वहां वीहकल्ज की कमी दूर की जा सकेगी । हो सकता है वहां फास्ट मूविंग वीइकल न हो, पुरानी हालत का हो, उसका इलाज करवायेंगे ।

स्पीकर साहब, बहुत सदस्यों ने जिक्र किया कि हमारी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग की हालत खस्ता है या कहीं किराये के मकान में, धर्मशाला या चौपाल में है । यह बात उनकी बहुत हद तक ठीक है । मैं माननीय सदस्यो को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर काफी ध्यान रखे हुए है । इस बात की अहमियत को सरकार पूरी तरह महसूस करती है कि पुलिस स्टेशन ठीक जगह पर होना चाहिए, ठीक बिल्डिग में होना चाहिए और वहां पूरी तरह से हर तरीके की सुविधा होनी चाहिए । लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्डिंग पर पैसा बहुत लगता है और आज के दिन सरकार के सामने कई तरह के सवाल. हैं । एस ०वाई ०एल ० नहर के लिए पैसा जुटाना है, सड्कों के लिए भी पैसे की मांग है । अभी तक कुछ सड़के बकाया हैं, लिंक रोडज बनाने हैं । हमें किसानों की सुविधा के लिए भी बहुत सी सुविधायें जुटानी है और फाइनेन्स लिमिटिड हैं । यह तो है नहीं कि उन्हें रबड़ की तरह से बढ़ाया जा सकता है । आप जानते हैं कि अगर हमने छोटा सा टैक्स लगाना हो, बिजली के रेट्स बढाने हों या पैसेन्जर फेयर बढ़ाना हो तो बड़ा हो—हुल्ला विपक्ष के भाई

करने लग जाते हैं इसलिए हमें एक बैलेंस्ड तरीके से सारा काम करना है । सरकार ने यह भी देखना है कि किस मामले पर फण्डज का उपयोग पहले किया जाये और किस पर दो दिन के बाद किया जाये लेकिन फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं, कि पुलिस –की इग्बल्डिंग की कन्स्ट्रक्शन का मामला सरकार के दिमाग में पूरी तरह से है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और ज्यादा स्टैप्स ले कर इस जरूरत को पूरा करें । कुछ सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत जरूरियात बतायी हैं कि पुलिस स्टेशन सहर के बीच की बजाए शहर के बाहर होने चाहिएं । यह उनकी वाजिब बात है । दूसरे नैन साहब ने उकलाना या बरवासे के पुलिस स्टेशन का भी जिक्र किया है । ये सब बातें मैं पास–औन कर दूंगा और सरकार निश्चित तौर पर इन बातों की ओर ध्यान देगी ।

स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्यों ने. फौरैस्ट डिपार्टमैंट की वरर्किंग का काफी जिक्र किया है । मुझे खुशी है कि सरकार ने जो कदम इस मामले में उठासे हैं, उसके बारे में माननीय सदस्यों ने काफी सराहना की है और उसके. साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दिये हैं कि किस तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से फौरेस्टरी कर सकते हैं । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी –रचनात्मक तरीके हैं उनकी ओर सरकार ध्यान देगी । स्पीकर साहब चौधरी भले राम जी ने फौरैस्ट के बारे में अपनी बात का जिक्र 'करते हुए कहा कि फौरैस्ट गार्ड

को बहुत ज्यादा पावर दी हुई है और वे अपनी पावर का मिस–यूज करते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं । इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पावर्ज दी जाती हैं उसके लिए रूल्स बने हुए हैं ।, जो डैलीगेटिड लैजिस्लेशन होता है उसके द्वारा ही डिफरैन्ट आफिशियल्ज को पावर्ज दी जाती है । यह बात तो हाउस के हाथ में है । हमारा हर प्रकार का लैजिस्लेशन हाउस में बनता है और जो रूल्स बनते हैं उसके लिये हाउस की कमेटी बनी हुई है । वह रूस के बारे में देखती है । अगर चौधरी भले राम जी को एहसास है कि गार्ड को ज्यादा पावर दी गई हैं, जो नहीं दी जानी चाहिए उसके लिए हमारी सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी बनी हुई है उसमें वे अपनी बात कहें कि किस प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहिए।

स्पीकर साहब, श्री साहब सिंह सैनी पै एक, सवाल उठाया कि सरकार.. ने अब पंचायत की लैण्ड पर ज्यादा फौरैस्ट लगाने का काम शुरु किया है । आप जानते हैं, अगर ज्यादा फौरैस्ट लगेगे तो पंचायत की आमदन सादा बढ़ेगी और उनके पशुओं के लिए ज्यादा सारे का इन्तजाम हो सकेगा । उन्होंने खास तौर पर यह बात प्वायंट आउट की जो बड़ी अहम बात है कि कुछ गांवों में हरिजनों फार्मर्ज या लैण्ड ओनर और लैण्डलैस की आपस में तनाजनी हो गई है कि पंचायत की लैन्ड पर अगर फौरैस्ट लगा. दिये आयेंगे तो लैण्डलैस लोग अपने पशुओं को कहां चरायेंगे? उनकी यह –बात वाजिब है कि उन्हें भी पशु चराने

के लिए लैण्ड की आवश्यकता है । सरकार इस ओर भी उचित ध्यान देगी लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि सारी पंचायत लैण्ड पर कोई फौरेस्ट उगा देने की बात चल रही है या शुरु कर दिया है । ऐसी बात भी नहीं है कि सरकार पंचायत लैण्ड पर फौरेस्ट नहीं लगा रही है । कुछ थोड़े से हिस्से में जिसके बारे में यह उचित समझती है कि कोई खास काम नहीं आती है, उस हिस्से में फौरेस्ट लगाने की कोशिश की जाती है । बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि फौरेस्ट लगाने से लैडलैस लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा । यह बात ठीक है कि कैटल्ज की वहां पर पहले–पहले जाने की मनाही कर दी जाती है ताकि जो छोटे–छोटे पौधे होते हैं, वे कहीं मर न जायें और कैटल्ज कहीं उनको खराब न कर दें । साल या छः महीने के बाद जब वह पौधे बड़े हो जायेंने तो वहां पर घास वगैरा खूब उगेगा । इससे कैटल्ज को बेजिंग के लिये ज्यादा सुविधा होगी । मैं सैनी साहब से कहूंगा कि वे मुझे उन गांवों के नाम लिखकर स्पैसीफाई कर दें जहां इस वजह से कोई टैशन है, हम वहां पर उस मसले को देख लेंगे । हम टैंशन नहीं रखना चाहते । मुझे आशा है कि हम वहां पर टैशन को अवायड कर सकेंगे मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फौरेस्ट्री का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, यह आम लोगों की बहबूदी के लिये बनाया गया है । किसी खास आदमी की बहबूदी के लिये नहीं बनाया गया है । चौधरी अजमत खां जी ने यह कहा कि कुछ प्राइवेट लोग अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिये

फौरेस्ट्स लगाने लग गये हैं । स्पीकर साहब, यह तो और भी अच्छी बात है । हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फौरेस्ट्स लगें । इससे पर्या– वरण अच्छा होगा । इसके साथ ही साथ अगर उनकी आमदनी बढ़ती है तो वे बढ़ायें । मैं सरकार की तरफ से उनको यह बताना चाहता हूं कि हमारे फौरेस्ट बोर्ड ने एक स्कीम बनाई हुई है जिसके तहत हमारा बोर्ड ऐसे फौरेस्ट्स को खरीदेगा जो प्राइवेट लोगों ने उगाये होंगे । शायद उनका कहना यही था कि उनको प्राइस अच्छी नही मिलती है । यह ठीक है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी अपने दरख्त लगाकर और उनको बड़ा करके काट कर बेचता है तो उनको प्राईस अच्छी नहीं मिलती है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे फौरेस्ट बोर्ड ने ऐसी स्कीम बनायी है कि वह ऐसे दरख्तों को खरीदेगा ।

स्पीकर साहब, हाउस में ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया गया । आप जानते ही हैं कि पिछले तीन सालों से हमारी ट्रांसपोर्ट सारे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी मानी जाती रही है । मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे कुलीग उस फर्स्ट को मेनटेन करेंगे जो हम पिछले तीन सालों सै सारे हिन्दुस्तान में लेते रहे हैं । सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है । मैं इस बारें में सारे हाउस को विश्वास दिलाना– चाहता हूं कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस है और जो पैसेंजर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी । यहां पर कुछ जिक्र मैम्बर साहेबान ने, जिनमें सैनी साहब, चौधरी

अजमल खां, चौधरी निर्मल सिंह वगैरा शामिल हैं इस सिलसिले में अपनी डिफीकल्टीज का जिक्र किया है । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो–जो बातें उन्होंने कही हैं, वे सारी बातें कन्सर्न्ड डिपार्टमैंट को भेज दूंगा और मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हाउस में जो कुछ उन्होंने बताया है, उसके ऊपर पूरी तरह से गौर होगा । निश्चित तौर पर जहां किसी चीज की जरूरत होगी, वह पूरी करने की कोशिश की जायेगी । इस सिलसिले में थोड़ा सा सड्कों का जिक्र भी आता है । स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सड्कों की कमी नहीं है । मेरे साल में हम ही ऐसी स्टेट हैं जहां पर कोई भी गांव बाकी नहीं है जो सड़क से कनैक्टिड न हो । सारे हिन्दुस्तान में हम ही पहली स्टेट है । इसके साथ–साथ यह बात भी बिल्कुल ठीक है, जैसे कोई मैम्बर साहेबान ने कहा भी है कि बहुत से लिंक्स अभी बकाया है जो गांवों को आपस में जोड़ने के लिये जरूरी हैं । स्पीकर साहब, हुआ क्या है कि पहले हरेक गांव को एक–एक डायरैक्ट लिंक दिये गये हैं । आप जानते हैं कि गांवों को तो चारों तरफ से भी जोड़ा जा सकता है । डिफरैंट एरियाज में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनको जोड़ा जाना जरूरी है । सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक गांव एक तरफ से तो जुड़ा हुआ है लेकिन उससे दूसरे गांव में या किसी पार्टीकुलर शहर में जाने के लिये गांव का 5 किलोमीटर का टुकड़ा बना देने से उसका फासला बहुत कम हो जाता है । कहने का मतलब यह है कि अगर दूसरा लिंक बन जाये, शायद किसी पार्टीकुलर गांव में दो किलो– मीटर,

किसी में एक–आध किलोमीटर, तो इससे वहां पर लोगों को सहूलियत हो सकती है । इसका मतलब तो यह हुआ कि यह तो डबल लिंक है, या कहीं पर हो सकता है ट्रिपल लिंक की भी जरूरत हो । आप जानते हैं कि सड़कें बनाने के लिये पैसा काफी खर्च होता है । एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिये अढ़ाई लाख रुपया खर्च आता है । इसके लिये बहुत अच्छा एक रास्ता निकल आया है । पिछले 2– 3– 4– 5 सालों से सड्कों का हमारा काम कुछ कम रहा है । उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि हमें मार्किटिंग बोर्ड के पैसे को सड्कों पर खर्च करने की इजाजत नहीं थी । इससे पहले आप जानते ही हैं कि मार्किटिंग बोर्ड या मार्किट कमेटियों का पैसा हमारे देहाती भाइयों और किसानों से आता है । पहले यह पैसा किसानों की बेहतरी, देहातों की डिवैल्पमैंट जिसमें सड़कें भी शामिल थीं, हरियाणा सरकार इस्तेमाल कर लिया करती थी । मार्किटिंग बोर्ड की आम– दनी को' देहातों की तरक्की के लिये, पीने के पानी की सुविधा देने के लिये और दूसरे कामों के लिये हरियाणा सरकार खर्च कर लिया करती थी । 5– 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया था कि सरकार द्वारा उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । चुनांचे जो पै सा मार्किटिंग बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, सड़कें बनाने के लिये, उनको गांवों के साथ मिलाने के लिये, वह रुक गया । यह काम 4– 5 साल तक इसलिए ही कम रहा । मैं हाउस की सूचना के लिये यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को रिव्यू करके अब यह इजाजत दे दी है कि

मार्किटिंग बोर्ड की कुल आमदनी का कुछ हिस्सा हम इस पर खर्च कर सकते हैं । सड्कों की तरक्की, नयी सड़कें बनाने और पुरानी सड्कों की मेनटेनैंस पर और कुछ दूसरे रूरल एरियाज में काम करने के लिये अब हम यह रुपया खर्चे कर सकते हैं । ई हाउस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सड़कों के निर्माण का काम जो पिछले कुछ सालों से सुस्त रहा है या बहुत कम होता रहा है, वह कमी अब दूर करने की पूरी कोशिश की जायेगी । स्पीकर साहब, जैसा कि आपने भी सुना होगा, हमारे पी०डब्ल्यू ०डी० मन्त्री जी ने एलान किया है कि हर गांव के स्कुल को, हास्पिटल को, मंदिर को और दूसरे धार्मिक जगहों को सड़क से मिला दिया जायेगा और साथ–साथ ऐसे लिंक्स भी बनाये जायेंगे जिनसे एक जगह से दूसरी जगह तक कम डिस्टैंस में पहुंचा जा सके । मेरा यह पूरा विश्वास है, मैं सरकार की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैम्बर साहेबान ने सड्कों के मामलों में जो जरूरियात, या शिकायतें बतायी हैं, वे उनकी आने वाले समय में कम से कम हो जायेंगी । एक बात के लिये स्पीकर साहब, मैं जरूर धमीजा साहब की तारीफ करना चाहूंगा । उन्होंने यह कहकर मेरी सिफारिश कर दी कि नार्दन स्टेट्स. में सेल्स टैक्स का रेट एक ही होना चाहिए । स्पीकर साहब, मैं बतौर फाइनांस मिनिस्टर हाउस को यह बता सकता हूं कि हम हरियाणा में सेल्ज टैक्स का रैवेन्यू जितना एस्टीमेट करते थे, उतना नहीं आ पा रहा है क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स ने कुछ चीजों पर सेल्ज टैक्स का रेट जान–बूझ कर कम कर दिया है । मैं डिटेल्ज में नही जाना चाहता और हाउस का

टाईम खराब नहीं करना चाहता । मिसाल के तौर पर मैं एक ही बात बताना चाहता हूं । ट्रैक्टर्ज मेरे ख्याल में सारे हिंदुस्तान में जितने बनते हैं, उसका 273 टैरक्टर्ज हमारे हरियाणा में बनाये जाते हैं । फरीदाबाद में और एच०एम०टी० पिंजौर में इसकी फैक्ट्रियां हैं । हमारे यहां पर ट्रैक्टर्ज की सेल पर सेल्ज टैक्स 10 परसैटं है जबकि नेबरिंग स्टेट में किसी ने 4 परसैटं किसी ने 6 परसैटं कर दिया है । नतीजा यह हुआ है कि ट्रैक्टर्ज बनते तो हमारे यहां हैं लेकिन उन स्टेट्स में जाकर बिकते हें जहां पर टैक्स थोड़ा है । हरियाणा में नहो बिकते । यू०पी० में, दिल्ली में जाकर बेचते हैं । इस तरीके से हमारी आमदनी घट गयी है । हम हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश कर रहे हैं । हमने सैट्रल गवर्नमैंट को इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाजह किया है कि यह कम्पीटीशन नहीं होना चाहिये और नार्दन स्टेट्स में डिफरैटं आईटम्ज पर सेल्ज टैक्स का लैवल तकरीबन एक ही होना चाहिए । ताकि स्टेट का जो जायज रैवेन्यू है वह मिल जाए । स्पीकर साहब, इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारी स्टेट में बहुत कारें बनती हैं । स्पीकर साहब, मैं मारूति कार का जिक्र कर रहा हूं । पहले तो बराबर की स्टेट्स में और हरियाणा में एक जैसा ही सेल्ज टैक्स था लेकिन बाद में दूसरी स्टेट्स ने घटा दिया । इस समय हमारी स्टेट में सेल्ज टैक्स की दर ज्यादा हैं । दूसरी स्टेट्स द्वारा दर घटाने की वजह से अब कम्पनी ने सेल्ज आफिस दूसरी स्टेट्स में बना लिए जिससे हमारी स्टेट का रैवेन्यू खत्म हो जाता है । इस बारे में हरियाणा सरकार बहुत चिन्ता करती है कि

इस तरीके से जो रैवेन्यू सरकार का घट रहा है, उसकी पूर्ति कैसे होगी । हम –केन्द्रीय सरकार से बात कर रहे हैं और काफी जोर दे रहे हैं कि इस मामले में हरियाणा के साथ जो अन्याय है, वह खत्म होना चाहिए ।

स्पीकर साहब, यहां पर सोशल वैलफेयर के बारे 'में बातें कही गई । तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने इसकी तारीफ की । पैन्शन के बारे में थोड़ी सी चिन्ता भी व्यक्त की सई कि पैन्शन भेजने में बहुत डिले होती है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हू कि हरियाणा सकार निश्चित रूप से इस मामले में कुछ कदम उठाएगी ताकि लोगों कों समय पर और रैगुलरली पैन्शन मिल सके । स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने कुछ और बस्ते उठाई हैं लेकिन समय थोडा है । मैं हर माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह मैं अपने डिफरैन्ट कुलीग्ज को डिपार्टमैंट वाइस भेज दूंगा । आप विस्वास रखें कि उनकी हर बात पर मुनासिब कार्यवाही की जाएगी । सन् शब्दों के सथ मैं फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं डिमाण्डज को वोटिंग के लिए पुट करता हूं ।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,51,780 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No.1—Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,70,58,100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,56,19,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45,07,860 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,35,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,48,01,596 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,41,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No 9—Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 58,36,734 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 12—Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 for revenue expenditure and Rs. 10,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 13—Social Welfare an d Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 42,28,000 for revenue expenditure and Rs. 10,27,28,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 14—Food

and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,31,66,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,20,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48,26,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 32,82,250 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 19—Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No.

20—Forest.

The motion was carried.

Mr. gpeaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,38,82,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will came in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. —23—Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,48,00,165 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1986 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब हाउस 25 फरवरी, 1986 बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है ।

13.25 बजे

(तत्पश्चात सदन मंगलवार दिनांक 25—2—1986 को बाद दोपहर 2.00 बजे तक से लिए स्थगित हुआ)